5 o'clock. I will read out the time available to different parties. The Congress Party has one hour and fifty-seven minutes and 13 speakers. ...*(Inerruptions)*... There shall be no grace period. The BJP has 11 minutes and two speakers. The CPI (M) has no time left. The AIADMK has six minutes and one speaker. The JDU has four minutes and two speakers. The CPI has no time left and has one speaker. Nominated Members have 14 minutes and four speakers. Others have one hour and forty minutes and 14 speakers. ...*(Interruptions)*... मैं बताता हूं, आप ठहरिए। The Samajwadi Party has six minutes and three speakers. So, the parties that have been given more time have four hours and twelve minutes. ...*(Interruptions)*... मंत्री का समय अलग है, मैं उसको निकालकर ही बोल रहा हूं। हमारे पास BSP का कोई नाम नहीं है। Name cannot be given just at any time. Now, I would request hon. Members to kindly not exceed the time allotted to them because they would be taking up others' time. I would request parties that have been given more time to accommodate those who have not been given much time. But there, only one speaker would be allowed. If they have no time left, the only grace allowed would be that one person would be allowed to speak. ...*(Interruptions)*... The reply is at 5'o clock. श्री प्रभात झा।

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला (राजस्थान): जो लोग बोल नहीं पाते हैं, ...(**व्यवधान**)... जैसे लोक सभा में होता है कि वे अपने भाषण को ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: वह रूल आपने नहीं बनाया, इसलिए हम भी फॉलो नहीं करेंगे।

———

THE BUDGET (GENERAL), 2009-10

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आम बजट पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले तो वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे सामने एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है, जिसने हमें न केवल विकास का रास्ता दिखाया है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में, समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। आज विश्व में आर्थिक स्थिति कैसी है, पूरे विश्व में कितनी आर्थिक मंदी चल रही है, इसके बारे में सब जानते हैं। ऐसे हालात में भारत को बचाकर रखना तथा इसके बावजूद आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए और समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ देना, मेरे ख्याल से ऐसा प्रणव बाबू जैसा अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता था। आज से 34 साल पहले भी वे इस देश के वित्त मंत्री थे। अब 34 साल के बाद उन्हें पुनः वित्त मंत्री बनने का मौका मिला है। इस दरमियान जो उनका अनुभव था, वह इस पूरे बजट में दृष्टिगत होता है। मैं इसके लिए उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे एक मित्र जो कारपोरेट वर्ल्ड से हैं, उन्होंने एक दिन कहा कि इस बजट में कारपोरेट वर्ल्ड को कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं दिया। मैंने कहा कि fringe बेनिफिट टैक्स का फायदा तो मिलेगा? उन्होंने कहा कि वह तो मिलेगा। मैंने कहा कि जो सरचार्ज इनकम टैक्स से हटाया है, उसका फायदा किसे मिलेगा? उन्होंने कहा कि वह तो मुझे मिलेगा। यह तो ठीक है कि कुछ तो मिला, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिला। कुछ तो मिला, बहुत ज्यादा नहीं मिला, इसका अंतर आपको सीधे-सीधे बजट के प्रस्ताव को देखने में मिलेगा। आप यह देखिए कि प्रणब बाबू के बजट का मुख्य फोकस किस पर है, उनके बजट का मुख्य फोकस आम आदमी पर है। उनका मुख्य फोकस भारत की जनता पर है, जो गांव में रहती है, जो मध्यम वर्ग तथा

निम्न वर्ग की है या समाज के निचले स्तर पर रहती है। आज heavy borrowings है। उन्होंने चार लाख करोड़ से ज्यादा की borrowing की। यह घाटे का बजट है। यह 6 प्रतिशत से ज्यादा घाटे का बजट है, लेकिन मान्यवर, कई बार घाटे का बजट देश के विकास के लिए फायदेमंद होता है। क्योंकि इसमें इस तरह का काम होता है, जिससे आम आदमी को, समाज और देश को राहत मिलती है। आज चार लाख करोड़ से ज्यादा ऐसी योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। यदि हम सिर्फ ग्रामीण विकास की योजनाओं को ही देखें, तो सबसे पहले NREGA है, ...) उन्होंने नरेगा पर 144 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अगर इसके पूरे रिकॉर्ड को देखा जाए, तो आप देखेगें कि उन्होंने किस तरह से 39,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान इसके लिए किया है। इसके बजट में 144 प्रतिशत का उछाल दिया है। इसके अलावा उन्होंने हाउस होल्ड के लिए भी 4.47 करोड़ की व्यवस्था की है। मेरा वित्त मंत्री जी को एक ही सुझाव है कि नरेगा में काम के स्कोप को बढ़ाना चाहिए। अभी ज्यादातर ध्यान खुदाई और मिट्टी के कार्य पर रहता है। गांव में कई चीजें ऐसी बन सकती हैं, चाहे स्कूल बनाने का काम हो, चाहे दूसरे तमाम काम हों, अगर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पंचायत घर आदि बनाने का काम भी नरेगा के अधीन लाया जाए, उसका स्कोप बढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है कि पूरे देश के स्तर पर एक बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है। दूसरी बात प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की है। इसके लिए उन्होंने 12000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मान्यवर, नरेगा एक ऐसी स्कीम है, जिसके बारे में कोई कुछ भी कहे, चाहे आलोचना की जाए या कुछ और बात हो, ऐसी कोई स्कीम नहीं है, जिसमें विकृतियां न हों, Every scheme has got some aberrations. But this is one scheme which is tangible and which is visible. You go anywhere at the grassroot level and see that people are taking advantage of this scheme. This is one scheme which should be appreciated by everybody. I think that this kind of fillip which has been given to the scheme should be appreciated by everyone. "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" तीसरी ऐसी योजना है, जिसका फायदा इस देश की जनता को मिल सकता है। वित्त मंत्री जी ने 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के लिए किया है। इस योजना के बारे में इतनी बात बताना चाहता हूं कि राज्य सरकारों के अधीन यह योजना होती है और राज्य सरकारें इसे लागू करती हैं, लेकिन वहां इसके कांट्रेक्ट देने में सावधानियां बरतनी होंगी। ऐसी कंपनियों को कांट्रेक्ट देने चाहिए, जो इस योजना को जल्दी से पूरा करे और आम आदमी के लिए गांव में जल्दी से जल्दी विद्युतीकरण का काम पूरा हो, जो नहीं हो पाता है। उसकी वजह यह रहती है कि कुछ राज्य सरकारें इस मामले में जितनी तेजी से काम करना चाहिए, उतनी तेजी से काम नहीं कर रही हैं। वह काम उनको उतनी तेजी से बढ़ाना चाहिए ताकि इसके लिए जरूरी टारगेट को पूरा किया जा सके। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन स्कीम का फायदा सभी लोग ले सकते हैं और गरीब की आंख का आंसू पोंछा जा सकता है। जितने भी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनमें जो वृद्ध हैं, उनके लिए इस योजना का लाभ है। इसमें ढाई सौ रुपए भारत सरकार देगी और बाकी ढाई सौ रुपए का कंट्रीब्यूशन राज्य सरकार को करना होगा। जहां राज्य सरकार तत्पर है, वह अपनी तरफ से ढाई सौ रुपए का कंट्रीब्यूशन देकर अगर पांच सौ रुपए एक गरीब व्यक्ति को गांव में देती है, यदि समाज में नीचे रहने वाले व्यक्ति को पैसे मिलते हैं, तो यह उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। अगर उसको यह धन न मिले - इस धन की वजह से उसको परिवार के लोग भी तंग

करते रहते हैं और उसका अपना जीवन-यापन नहीं हो पाता है, तो सोचिए कि कितनी बड़ी तकलीफ एक आम आदमी के सामने पैदा हो जाती। आम आदमी के फायदे के लिए जो इस तरह के काम उन्होंने किये हैं, उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी कम है। मैं एक बात यहां पर शहरी व्यक्ति के लिए भी कहूंगा। जो Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission है, उसके माध्यम से पिछले पांच सालों में काफी काम हुआ है। वे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और राज्य सरकारें उनका बहुत लाभ उठा रही हैं, जो सचमुच अपने प्रदेश के लिए, अपने शहरों के लिए कुछ करना चाहती हैं। आप जिस शहर का नाम लीजिए, वहां इस योजना के तहत पैसा दिया गया है। पिछले पांच सालों में केन्द्र सरकार ने इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती, कोई पक्षपात नहीं किया और राज्यों को जमकर पैसा दिया। जिन राज्य सरकारों के अंदर विल पॉवर थी, जिनके अंदर इस तरह की इच्छा थी कि हम लोगों के लिए काम करें, हम देश के लिए, प्रदेश की जनता, शहरों और गांवों में रहने वाले लोगों के लिए काम करें, उन लोगों ने काम किया है और इसका लाभ लिया है। जिनके मन में इच्छा नहीं थी, जहां वे अपनी ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल नहीं रख पाए, वहां यह स्थिति है कि इसका लाभ नहीं मिल पाया और वहां से आलोचना का काम चालू होता है। अगर आप देखें तो इसमें 87% का एलोकेशन बढ़ाया गया और 3,973 करोड़, 4000 करोड़ का प्रावधान Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission के लिए किया गया। मुझे लगता है कि अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर को इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रणब बाबू ने अपने बजट में बहुत जबर्दस्त काम किया है और ऐसा focus देने की कोशिश की है, जिससे इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। इसमें मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। कल सर्व शिक्षा अभियान के बारे में में बात हो रही थी। सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसी योजना है, जो हर गांव में दिखती है, गांवों में जहां-जहां स्कूल्स हैं, ज्यादातर सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से दिखती है। यह योजना नीचे तक पहुंची है। लेकिन यहां पर मेरा वित्त मंत्री जी को एक सुझाव भी होगा कि ऐसी education schemes का review निश्चित रूप से करें, जो schemes सिर्फ कागजों पर दिखती हैं। अगर ऐसी schemes का पैसा divert करके सर्व शिक्षा अभियान को भेजा जाए या उच्च शिक्षा में लगाया जाए, तो इसका लाभ मिल सकता है। इसके लिए मैं एक उदाहरण भी पेश करता हूं। सदन में सारे सम्मानित सदस्य बैठे हैं। वे हर जगह जाते हैं, पूरे देश का दौरा करते हैं, सब जगह घूमते हैं। बहुत कम सदस्य ऐसे होंगे, जिन्हें प्रौढ़ शिक्षा से पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति मिला हो। मुझे आज तक प्रौढ़ शिक्षा में पढ़ा हुआ एक भी व्यक्ति नहीं मिला, जबकि इस योजना पर पिछले 10-20 सालों में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस तरह की योजनाएं, जिनमें सिर्फ कागजों पर पैसा खर्च होता है, तमाम एनजीओज़ यह पैसा ले जाती हैं और इसके बाद वे कुछ नहीं करती हैं, ऐसी योजनाओं को बन्द करके उनका पैसा सर्व शिक्षा अभियान की तरफ divert करना चाहिए, उनका पैसा higher education की तरफ divert करना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे यहां R&D का काम बहुत अच्छा हो सकता है। भारत में बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत talent है। यहां के लोग बाहर जाकर अमेरिका और इंग्लैंड में उसी research and development के काम में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे यहां हमारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे कालेजज़ में वे सुविधाएं नहीं है। अगर उसी से वह infrastructure create किया जाए, जिसमें R&D की सुविधा बढ़ाई जा सके, तो मुझे लगता है कि भारत के शिक्षा के क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता हंै। जिस तरह से कम्प्यूटर के क्षेत्र में बीपीओ का काम मिला हुआ है, जिसमें लाखों लोगों को रोज़गार मिला है, बहुत से पश्चिमी देशों के लोग अपना R&D का काम भारत shift कर सकते हैं और यह रोजगार का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन सकता है। इस तरफ भी वित्त मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा है। ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं अपने समय का ध्यान रखूंगा।

सर, मैं इसमें एक और बात रखना चाहता हूं। आज सुबह भी क्वेश्चन ऑवर में यह बात आई थी कि infrastructure के लिए हम जो पैसा दे रहे हैं, उसमें monitoring का कोई-न-कोई प्रावधान जरूर होना चाहिए। राज्य और केन्द्र सरकार के बीच तमाम योजनाएं इस वजह से अटब जाती हैं, चाहे land acquisition का मामला हो, चाहे single window clearance न हो, उनकी वजह से प्रोजेक्ट्स लटके रहते हैं। अगर infrastructure को गति देनी है, अभी एक कमेटी भी बनाई गई है, प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स भी बनाई है, अगर इसको गति देनी है, तो राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठकर एक ऐसा mechanism तैयार करना चाहिए, जिससे प्रोजेक्ट्स delayed न हों और जल्दी-से-जल्दी प्रोजेक्ट्स पूरे हों। मुझे याद है कि Rural Development Ministry के एक सेक्रेटरी ने मुझसे कहा था कि दिल्ली से पिछले 60 साल में जितना पैसा गांवों के लिए और infrastruture के विकास के लिए लिया गया है, अगर सचमुच लग गया होता, अगर यह इंजीनियर-ठेकेदार nexuxs न होता, अगर यह सचमुच लग गया होता, तो सोने के गांव हो जाते और अमेरिका, इंग्लैंड के गांव भी इस तरह के न होते, उनसे बेहतर हमारे गांव होते। लेकिन दुख यह है कि पैसा पहुंच नहीं पाता है। आज हम सबको पार्टी से ऊपर उठकर यह काम करना पड़ेगा और सबको मिल कर इस nexus को तोड़ना होगा। अगर यह पैसा नीचे जाए, हजारों-लाखों करोड़ रुपए हैं, तो हम देखेंगे कि इनकी तस्वीर बदल जाएगी, इनकी शक्ल बदल जाएगी।

मैं आखिर में एक बात और रखना चाहता हूं। इस बजट में मीडिया को भी stimulus package दिया गया है, जो एक बहुत अच्छी बात है। प्रिंट मीडिया को राहत दी गई है, चाहे सर्विस टैक्स में हो, चाहे davp rates में हो। हमारा आग्रह सिर्फ यह था कि बाहर टेलीविजन चैनल वाले मिले थे, वे कह रहे थे कि हम भी तो मीडिया हैं, हमारे साथ क्यों ज्यादती हो रही है। अगर प्रिंट मीडिया को कुछ दिया है, तो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को भी वही चीज मिलनी चाहिए। सरकार को इन दोनों में भेद करने का काम नहीं करना चाहिए। हमारा वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध है कि वे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भेदभाव न करें। जो भी देना हो, चाहे एक रुपया दें, दोनों को दें। ऐसा न करें कि एक को तो रख लें और दूसरे को न दें। यह काम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अपने बजट भाषण में वे इसमें सुधार करेंगे। यही मेरा अनुरोध है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रघुनन्दन शर्मा (मध्य प्रदेश) : सम्माननीय उपसभापति महोदय, मैं अपनी बात प्रारम्भ करूं, उससे पूर्व मैं एक छोटी सी व्यवस्था संबंधी बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मैंने दो चार दिन पहले देखा कि जो हमारी आसन व्यवस्था है, वहां पहले सबके नाम के सामने 'श्री' लिखा हुआ था, लेकिन सारे सदन में आपनू फ्लूड लगा करके उस 'श्री' को मिटा दिया है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि 'श्री' को मिटाने के पीछे क्या कारण है? ...(**व्यवधान**)...

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (Bihar) : It is a curious thing.

श्री रघुनन्दन शर्मा : यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं आपके मस्तिष्क में या सदन में कहीं न कहीं वायुमंडल का प्रभाव तो नहीं है। कहीं आप जो सैकुलर या एंटीसैकुलर शब्द है, उसके कारण प्रभावित होकर तो 'श्री' को नहीं हटा रहे हैं।

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, it is a very valid point. Whitener has been put, and, 'shri' has been removed from every name. It is very amazing thing and Sir, it is a very interesting matter.

श्री रघुनन्दन शर्मा : अब हो गया, मैं बोल लूंगा ...(**व्यवधान**)... मैं स्वयं इस बात को बोलने में समर्थ हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You have brought it to our notice. We will look into it. ...*(Interruptions)*... यह पार्लियामेंट का मैटर है, and nobody can replace. We will look into it. हम इसे देखेंगे।

श्री रघुनन्दन शर्मा : नहीं, 'सुश्री' और 'श्रीमती' तो हैं, लेकिन बाकी लोगों को अपने जैंडर विहीन कर दिया गया है।

श्री उपसभापति : हम इसे देखेंगे ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्ल : यह गलत नहीं है ...(**व्यवधान**)... नेम प्लेट पर अपने ही नाम के आगे श्री नहीं लगाया जाता है ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now, Please ...*(Interruptions)*... Don't create ...*(Interruptions)*... Please ...*(Interruptions)*...

श्री रघुनन्दन शर्मा : उपसभापति जी, अब मैं अपनी बजट की बात पर आता हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : विप्लव जी, आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... अब आप बोलिए ...(**व्यवधान**)... शुक्ल जी, आप बैठिए ...(**व्यवधान**)...

श्री रघुनन्दन शर्मा : हो गया, राजीव जी, आपकी बात हमने ध्यान से सुन ली है ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : शुक्ल जी, आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... Please. ...*(Interruptions)*... हां, अब आप बोलिए ...(**व्यवधान**)...

श्री रघुनन्दन शर्मा : माननीय उपसभापति जी, अब मैं बजट की बात पर आ रहा हूं। मैंने वित्त मंत्री जी का संपूर्ण भाषण ध्यान से सुना है और समाचार पत्रों में उस पर टिप्पणी भी देखी है। उन समाचार पत्रों की टिप्पणी में यह स्पष्ट आया है कि वित्त मंत्री जी अपने सम्पूर्ण बजट भाषण में केवल एक ही बार हंसे। निश्चित रूप से उस सम्पूर्ण बजट में मुस्कुराने जैसी कोई बात थी ही नहीं। वह इस बात पर मुस्कराए कि पहली बार वह दस लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन उनकी टीम के लोगों के लिए और उनके दल के लिए मुंह लटकाने की बात यह भी थी कि चार लाख करोड़ रुपये से अधिक का घाटा इस बजट में रखा गया है, जो निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है।

माननीय उपसभापति जी, कृषि हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है और इस कृषि के ऊपर ही आर्थिक दृष्टि से अन्य सारी बातें निर्भर करती हैं। सम्पूर्ण देश की अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादन पर ही निर्भर करती है। उन्होंने उसमें कहा कि 2.87 हजार करोड़ रुपये का ऋण प्रवाह किसानों में पहले से ही है और उसे बढ़ा कर उन्होंने 3.80 हजार करोड़ करने का प्रयत्न किया है। इसके माध्यम से निश्चित रूप से उनका यह प्रयत्न है कि जो किसान हैं, उनको और अधिक कर्जदार बनाया जाए। लेकिन उसमें इसके लिए कोई समुचित व्यवस्था या इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि उनका कृषि उत्पादन किस प्रकार से बढ़े। कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसमें कोई व्यवस्था होती, ऐसी योजना प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। उसमें खाद, बीज, उपकरण, खेती का आधुनिकीकरण, बंजर भूमि को उर्वरा में बदलने का प्रयत्न इत्यादि पर समुचित योजना होनी चाहिए थी और फिर उस योजना पर कार्यवाही का प्रयत्न भी किया जाना चाहिए था, लेकिन यहां से वहां तक मुझे इस बजट में ऐसे प्रयत्नों की थोड़ी भी छटा दिखाई नहीं देती।

मान्यवर महोदय, उसमें उर्वरकों के बारे में भी कहा गया है कि उर्वरकों की सब्सिडी की पद्धति को बदल दिया गया है और अब वह इसे सीधे किसानों को देंगे, लेकिन यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि यह सब्सिडी समाप्त कर किसानों को किस प्रकार से दी जाएगी? उसमें कितने छोटे किसान आएंगे कितने बड़े किसान आएंगे और फिर सीधे-सीधे सारे उर्वरकों की कीमत कितनी बढ़ेगी? यदि उर्वरकों की कीमत ज्यादा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उससे कृषि उत्पादन भी प्रभावित होगा और यदि कृषि उत्पादन प्रभावित होगा तो कृषि घाटे का व्यवसाय बन जायेगी और फिर कृषि घाटे का व्यवसाय एक ही बार नहीं बनेगी, बल्कि कृषि उत्पादन स्थायी रूप से घाटे की अर्थव्यवस्था में बदल जाएगा। इस तरह निश्चित रूप से उनकी पद्धति में कहीं न कहीं दोष है। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए थी, लेकिन बजट में यह बात कहीं भी स्पष्ट नहीं हुई है।

माननीय महोदय, महाराष्ट्र के किसानों के बारे में एक बात और कही गई है, जिसे यहां कई वक्ताओं ने स्पष्ट किया है कि साहूकारों के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए महाराष्ट्र में इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा। मंत्री जी ने पृष्ठ 7 के अपने भाषण में कहा है कि बड़ी संख्या में किसानों ने निजी ऋणदाताओं से ऋण ले रखे हैं, लेकिन ऋण माफी योजना में उन्हें शामिल नहीं किया है। इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब वित्त मंत्री जी ध्यान देने की आवश्यकता की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर समुचित कार्यवाही के लिए उन्होंने कहीं आश्वासन नहीं दिया है, कहीं कार्य-योजना नहीं दी है या कहीं कार्यवाही का प्रयत्न नहीं किया है। ध्यान देना और कार्यवाही करना, दोनों में बड़ा अंतर है। माननीय महोदय, यह बात भी यहां पर आई है कि निश्चित रूप से केवल महाराष्ट्र के किसानों के लिए यह बात कही गई है। उनका ध्यान महाराष्ट्र के आने वाले विधान सभा के चुनावों पर ही था, अन्यथा मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सम्पूर्ण देश के किसानों का साहूकारों के कर्जे से मुक्ति का अभियान प्रारम्भ हो गया है या वे उनसे मुक्ति पा गये हैं? निश्चित रूप से देश के अन्य प्रांतों के किसान साहूकारों के कर्जे से मुक्ति नहीं पा सके हैं। वे अभी भी उसके बोझ से लदे हुए हैं, लेकिन उनका ध्यान केवल वहीं गया है।

माननीय महोदय, इस सत्र में इस सदन में और लोक सभा में दो बजट प्रस्तुत हुए हैं - एक रेल बजट और दूसरा सामान्य बजट। इन दोनों बजट के प्रस्तुत करने वाले, दोनों महानुभाव, बंगाल के थे। इस बार सारे देश में अनावृष्टि है, लेकिन बंगाल के ऊपर इस बजट में खूब वर्षा हुई है। उसके पीछे स्पष्ट कारण यह है कि वहां पर भी चुनाव आने वाला है। इसलिए उन चुनावों को जीतने के लिए बजट का दुरुपयोग करने का प्रयत्न किया गया है। निश्चित रूप से यह ठीक कार्य नहीं है, यह कहीं-न-कहीं पक्षपात और दुर्भावना से परिपूर्ण है।

माननीय महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कौटिल्य का उदाहरण दिया है। पहली बार उनको कौटिल्य याद आया। निश्चित रूप से उसके पीछे यह भावना रही होगी कि उनके जो पहले वामपंथी साथी थे, वे पुराने ऋषियों, मनीषियों और चिंतकों के बारे में, भारतीय चिंतकों के बारे में उन पर किसी भी प्रकार से दबाव बनाए रख कर उनको उस दिशा में चलने से रोकते थे। इसीलिए इस बार जब वह अपने वामपंथी मित्रों से मुक्ति पा गए तो उनको कौटिल्य याद आया। प्राचीन भारत के ऋषियों और मनीषियों तथा उनका अर्थ-चिंतन उनको याद आया, मैं यह कहना चाहता हूं वैसे सीता राम येचुरी जी ने भी इस बार अपने भाषण में कौटिल्य को याद किया है। हमारे तिवारी जी ने भी कौटिल्य को याद किया है। यह एक अच्छी बात है। यदि हम कहीं कौटिल्य की बात करते तो हम पर भगवाकरण का आरोप लगा दिया जाता। अब यह भगवाकरण की ओर बढ़ रहे हैं, यह प्रसन्नता की बात है।

सम्माननीय महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इन्होंने कोटिल्य की बात का उदाहरण तो दे दिया, लेकिन उन्होंने जिस सम्भावना के प्रति संकेत किया है और उन्होंने कहा कि आपदाओं की सम्भावनाओं का अनुमान लगाना होगा। यह निर्देश कौटिल्य ने अपने "अर्थशास्त्र" में दिया है, लेकिन उससे कहीं प्रेरणा प्राप्त नहीं की है, केवल quote करने के लिए ही कौटिल्य के नाम का प्रयोग हुआ है। बजट में इस आपदा-सम्भावनाओं के लिए भी प्रावधान होना चाहिए था। देश मे महामारी फैल सकती है, भूकम्प आ सकता है, बाढ़ से तबाही हो सकती है और नक्सलियों, आतंकवादियों, उपद्रवियों तथा माओवादियों का कहर देश पर हो सकता है, वे देश में विध्वंस मचा सकते हैं, लेकिन इन सब का मुकाबला करने के लिए, इन सब आपदाओं से बचाव हेतु व्यवस्था और प्रबंधन करने के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसीलिए मुझे यह लगता है कि केवल कौटिल्य के नाम का उपयोग किया गया है, उनसे प्रेरणा लेने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ है। बेहतर होता कि उन भारतीय ऋषियों-मनीषियों के अर्थ-चिंतन से और उनके तत्व-दर्शन से यह कुछ ज्ञान लेते, उसके अनुसार कुछ करने का विचार रखते तथा उसे कार्य रूप में परिणत करते।

मान्यवार महोदय, पहली बार सरकार ने feed back देकर समाचार पत्रों में यह छपवाया कि इन 25 वर्षों में पहली बार महंगाई-दर शून्य से नीचे गई है। यह शून्य से नीचे गई है, इस बात को कई दिनों तक प्रचारित किया गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। खाद्य-पदार्थ, दालें तथा सामान्य जीवन में उपयोग की वस्तुएं इन 25 वर्षों में जितनी महंगाई की छलांग लगा करके कीमतें आसमान को छूने में समर्थ हुई है, उतनी देश में किसी भी 5 वर्षों में ...। उतनी किसी भी एक वर्ष में नहीं हुई है, जितनी इस एक वर्ष में हुई हैं। मान्यवर, 25 वर्षों का रिकॉर्ड महंगाई की बढ़ती दर ने तोड़ दिया है, लेकिन आप प्रचारित कर रहे हैं कि महंगाई दर शून्य से नीचे पहुंच गई है। यह तो गोएवल्स को भी पीछे छोड़ने जैसा कुप्रचार है, कपट नीति है। प्रचार में कोई भी इस प्रकार का छल और प्रपंच नहीं करता है, लेकिन यहां छल और प्रपंच किया गया है। अभी कुछ समय पूर्व मैंने दैनिक भास्कर के बिजनेस पृष्ठ पर पढ़ा था। उसमें कहा है कि छल और कपट से देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए मूल्य सूचकांक में परिवर्तन किया गया है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अनाजों के नए थोक मूल्य सूचकांक में आम आदमी द्वारा इस्तेमाल होने वाली चीजों की हिस्सेदारी घटा दी गई है और यह बात बेहद चिंता पैदा करने वाली है। अनाजों की हिस्सेदारी 5.01 से घटाकर 4.09 कर दी गई है, दूध की हिस्सेदारी 4.37 से 3.24 कर दी गई है, उसी प्रकार चीनी की हिस्सेदारी 3.62 से घटाकर 1.68 पर आ गई है, खाद्य तेल की हिस्सेदारी 2.76 से घटाकर 2.60 कर दी गई है। इस प्रकार जब थोक मूल्य सूचकांक निर्धारित करने का मापदंड ही आप बदल देंगे और उस आधार पर मूल्य सूचकांक तय होगा तो निश्चित रूप से आप शून्य से और नीचे, 25 अंक नीचे भी ले जा सकते हैं। यदि यही छल और छलावा करना है तो फिर आपको इस प्रकार से झूठे प्रचार करने से कौन रोक सकता है? लेकिन वास्तव में जनता इस मार को झेल रही है, आसमान छूती महंगाई को झेल रही है, महंगाई की इस आग की भट्टी में वह जल रही है, इसलिए आपके इस कुप्रचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और हां इस बजट के माध्यम से व झूठे प्रचार के माध्यम से देश और इस सदन को गुमराह करने का प्रयन्त किया गया है।

माननीय सभापति जी, आर्थिक मंदी के दौर में भी भारत पूरी तरह से बचा रहा और उस पर केवल आंशिक प्रभाव ही पड़ा, यह बात बजट में कही गई है। लेकिन आंशिक प्रभाव ही पड़ा और भारत बचा रहा, इसका कारण क्या है? मान्यवर, भारत के बचे रहने का मूल कारण है यहां की सनातन संस्कृति, सामाजिक जीवन पद्धति का

निर्माण, जो हजारों वर्षों में हुआ है और हमारी पारिवारिक व्यवस्था। संयुक्त परिवार प्रथा के कारण भारत इस महा मंदी के दौर से भी बचा रहा है। आज भी भारत की अर्थ-व्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था है और इस कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था के कारण जबकि इस महंगाई की चपेट में सारे देश आ गए, लेकिन भारत बचा रहा। इसके अलावा तीसरी बात यह है कि भारत के परिवारों में जो बचत करने की प्रवृत्ति है, इस बचत करने की प्रवृत्ति के कारण भी हमारा देश इस आर्थिक मंदी से बचा रहा।

मान्यवार सभापति महोदय, आप घाटे की अर्थ-व्यवस्था में इस देश को ले जाना चाहते हैं, अमेरिका के पद-चिह्नों पर चलना चाहते हैं। पिछले समय अमेरिका में 45 खरब डॉलर का घाटा हुआ। वहां 2006-2007 में जो देश की सकल आय थी, उस सकल आय में जो व्यय हुआ, वह व्यय 45 खरब डॉलर अधिक था और इस कारण वहां अर्थ व्यवस्था पिट गयी। इस कारण अर्थिक मंदी के दौर में केवल वहीं नहीं बल्कि सारे संसार और हम लोगों तक भी इसका प्रभाव पहुंचा। मान्यवर महोदय, निश्चित रूप से इस का उपयुक्त उदाहरण यह है कि हम अपने ढंग से, अपनी सकल आय के आधार पर, बिना किसी अन्य की नकल करते हुए अपनी अर्थ-व्यवस्था को बनाए रखें। मान्यवर, हमारे यहां एक कहावत है, "ताकत कम गुस्सा ज्यादा, ये पिटने के लक्षण हैं और आमद कम खर्चा ज्यादा, ये मिटने के लक्षण हैं।" आप भी इस देश को इसी तरह से अमेरिका के पदचिह्नों पर ले जाकर घाटे की ओर बढ़ाना चाहते हैं। मान्यवर, रूस मिट गया, अमेरिका भी मिटने वाला है, 8-10 वर्षों में अमेरिका आर्थिक दृष्टि से सब से पीछे की पंक्ति में खड़ा होगा। वहीं भारत, जो यहां की कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था है, उस के कारण, संयुक्त परिवार व्यवस्था के कारण, यहां के लोगों की बचत की प्रवृत्ति के कारण फिर एक आर्थिक महा-शक्ति के रूप में दुनिया में सिर ऊपर कर के खड़ा रहेगा। मस्तक ऊपर करके दुनिया के सामने हमारा देश आर्थिक दृष्टि से भी मार्गदर्शन करेगा, नेतृत्व करेगा।

श्री उपसभापति : आप समाप्त कीजिए।

एक माननीय सदस्य : बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री उपसभापति : अच्छा बोल रहे हैं, मुझे मालूम है ...(**व्यवधान**)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (Bihar) : It is a maiden speech, Sir.

श्री उपसभापति : नहीं-नहीं, देखिए आपके 11 मिनट बचे थे, अब 15-16 मिनट हो गए हैं। ...(**व्यवधान**)... नहीं-नहीं, दूसरों को भी बोलने दीजिए। I have to allow others also. ...*(Interruptions)*.. Please understand, today, the compulsion. ...*(Interruptions)*.... अब आप खत्म कीजिए, प्लीज।

श्री रघुनन्दन शर्मा : माननीय उपसभापति महोदय, 4 लाख करोड़ का कर्जा प्रणब मुखर्जी ले सकते हैं, मुझे पांच मिनट आप उधार क्यों नहीं देंगे? अगले टाइम से मेरे पांच मिनट आप काट लीजिएगा।

श्री उपसभापति : नहीं-नहीं। आप दूसरों से request कीजिए, मुझसे request मत कीजिए।

श्री एम. वेंकैया नायडु (कर्नाटक) : सर, इन्होंने एक संवैधानिक सवाल उठाया कि जब सरकार 4 लाख करोड़ मार्केट से borrow कर सकती है तो क्या आप उन्हें 5 मिनट उधार नहीं दे सकते हैं?

श्री उपसभापति : मैं तो उधार नहीं दे सकता। दूसरे मैम्बर्स अगर चाहें तो दे सकते हैं। ...(**व्यवधान**)...

AN HON. MEMBER : Members are agreeing, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please conclude. ...*(Interruptions)*... Please conclude.

1.00 P.M.

श्री रघुनन्दन शर्मा : माननीय उपसभापति जी, मैं एक और बात के ऊपर आना चाहता हूं।

श्री उपसभापति : नहीं, आप आखिरी बात कीजिए, एक और बात नहीं।

श्री रघुनन्दन शर्मा : मैं कोशिश करूंगा कि आखिरी बात ही करूं।

श्री उपसभापति : कोशिश नहीं, करना ही पड़ेगा। नहीं तो मेरी bell बजेगी।

श्री रघुनन्दन शर्मा : माननीय उपसभापति जी ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, बहुत ही प्रभावी हिन्दी बोली जा रही है।

श्री उपसभापति : मैं भी सुन रहा हूं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : शुद्ध हिन्दी।

श्री रघुनन्दन शर्मा : हमारा देश नक्सली समस्या से ग्रस्त है। श्री शिवराज पाटिल पांच वर्षों तक यह कहते रहे कि यह नक्सली समस्या, आतंकवाद, उग्रवाद या देश में विध्वंस का तांडव करने वाली व्यवस्था नहीं है। इसमें केवल सामाजिक और आर्थिक कारण ऐसे हैं, जिसके कारण यह समस्या खड़ी हुई है, लेकिन वास्तव में यह बात नहीं है। नेपाल में ऐसी बात नहीं थी। देश को तोड़ने वाली प्रवृत्तियां हैं। इस देश की प्रभुसत्ता को नष्ट करने के लिए जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, उनमें से यह एक देशद्रोही प्रवृत्ति है, जो अपना सिर उठा रही है। माननीय महोदय, यह नक्सलवार - यहां साढ़े चार साल तक श्री शिवराज जी यह कहते रहे, लेकिन वे अपने साथियों का उपयोग नहीं कर सके। जो नेपाल में जाकर गुमराह मित्रों को हिंसा से अहिंसा की ओर ले जा सकते हैं, मुख्य धारा में ले जा सकते हैं, क्या वह साढ़े चार साल तक अपने बगल में बिठाये रखे लोगों से यह उपयोग नहीं ले सकते थे कि उनको समझाइश देकर अच्छे रास्ते पर लाते? लेकिन यह समस्या ऐसी नहीं है। यह समस्या राजनैतिक समस्या है। इस देश में इस प्रकार की हिंसा खड़ी करना और प्रछन्न रूप से जो उनको समर्थन दे रहे हैं, वे लोग बाद में जब शक्तिशाली हो जाएं तो उसको साथ लेकर सत्ता के ऊपर कब्जा कर लें। ...**समय की घंटी**...

श्री उपसभापति : बस, अब हो गया।

श्री रघुनन्दन शर्मा : एक अंतिम बात।

श्री उपसभापति : नहीं, मैं मजबूर हूं, प्लीज। आप समाप्त कीजिए।

श्री रघुनन्दन शर्मा : माननीय महोदय, 300 करोड़ रुपये प्रति वर्ष नक्सली वसूल कर रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री ने सार्वजनिक बयान के माध्यम से कहा है। देश में इनको रोकने के लिए इस बजट में 300 करोड़ रुपये की भी व्यवस्था नहीं की गई है। वे केवल एक प्रांत में 300 करोड़ वसूल कर रहे हैं, पांच प्रांतों में लगभग डेढ़ हजार करोड़ रुपये देशवासियों से, ठेकेदारों से और सरकार के नुमाइंदों से वसूल करके शास्त्रास्त्र खरीद रहे हैं और वे आधुनिक शस्त्रों से लैश हो रहे हैं। वे इस देश को तबाही की ओर ले जाना चाहते हैं।

माननीय महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देने के साथ मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि एक रुपया भेजा जाता है उसमें से 15 पैसे ही उपयोग में आते हैं। यह सदन, यह सरकार और हम सब मिल कर यदि यह संकल्प करें कि यहां से भेजा जाने वाला पूरा का पूरा रुपया देश के विकास में काम आएगा तो हम इस देश को - भारत के निर्माण करने तक ही सीमित नहीं रहेंगे बल्कि हम इसे संसार की एक महाशक्ति बनाने में समर्थ होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति : श्री अवतार सिंह करीमपुरी। आपके पास 8 मिनट का समय है।

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला (राजस्थान): आज Lunch Hour नहीं है?

श्री उपसभापति : जी, Lunch Hour नहीं है।

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला : हाऊस की सैंस ले लिया है।

श्री उपसभापति : सैंस तो ले लिया है।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी (उत्तर प्रदेश): सर, आपने मुझे इस बजट की अहम discussion में participate करने के लिए समय दिया है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। समय बहुत कम है, इसलिए मैं इस कम समय में कुछ important issues ही उठाना चाहूंगा।

सर, फरीद साहब ने अपनी वाणी में लिखा कि -

फरीदा जे तू अकल लतीफ, तां काले सिख न लेख

आपनड़े गिरबान में सर नीवां कर देख।

फरीद साहब कहते हैं कि अगर आपके पास यह शक्ति है, यह talent है, यह opportunity है कि आप कुछ लिखते हैं, आप कुछ प्लान करते हैं, तो वे कहते हैं कि *काले लिख न लेख, आपनड़े गिरबान में सर नीवां कर देख,* अपने पांव की ओर भी कभी सर नीचे करके देखना है, Self analysis करने की भी जरूरत है। मैंने जब बजट को पढ़ा तो देखा कि उसमें खास तौर से PPP - Public Private Participation - का बहुत इस्तेमाल किया गया है। जगह-जगह पर यह Public Private Participation दिखाया गया है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस देश को बचाना है तो हमें इस Public Private Participation की समीक्षा करनी होगी और हम आपको suggest करना चाहते हैं कि let us replace PPP. मैं भी PPP propose कर रहा हूं और वह PPP क्या है? उसमें पहला P Poverty के लिए है। आज इस देश के सामने गरीबी एक major challenge है, यह एक गंभीर समस्या है। हम पिछले 61 बरसों से इस देश का बजट तैयार कर रहे हैं और हर बार इस बजट में हम इस देश की जनता से यह वादा करते हैं कि हम गरीबी से निबटेंगे, हम गरीबी को खत्म करेंगे, हम गरीबी को जड़ से मिटा देना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि गरीबी जड़ से मिट नहीं रही है, गरीबी बढ़ रही है और इससे भी ज्यादा अफसोस की बात है कि हमारे देश की सरकार अभी तक confused है, अभी तक यह decide नहीं कर पा रही है कि हमारे देश में गरीबों की संख्या कितनी है। इस बारे में जितने कमीशन बैठाए गए हैं, कमिटियां बैठाई गई हैं, उन सबकी अलग-अलग रिपोर्ट है। अगर सबकी एक रिपोर्ट नहीं होगी तो एक नीति नहीं होगी, अगर एक नीति नहीं होगी, एक योजना नहीं होगी तो हम इस समस्या का समाधान कैसे कर पाएंगे? इसलिए मैं यह चाहूंगा कि इस दिशा में सरकार को संजीदा approach अख्तियार करने की जरूरत है। दूसरा P Population के लिए है। Population is very big challenge for India और हमारी सरकार की इस बारे में कोई गंभीरता नजर नहीं आती है। हमारी सब industry fail नजर आ रही हैं, लेकिन population की field में हम दुनिया में एक नम्बर से, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश के संविधान की रचना की थी, डा. भीमराव अम्बेडकर साहब ने उस वक्त कहा था, जब इस देश का संविधान लागू हुआ था, कि हमारे देश को population control करने के लिए कोई affective योजना बनानी होगी। अगर बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर की बात को हमने माना होता तो आज हमारे देश की यह दशा न होती - आज हमारा बचपन रुल रहा है, आज हमारा बुढ़ापा रुल रहा है। हमारे पास कोई effective social security plan न होने के कारण, हमारे देश में social

insecurity के कारण day by day population increase हो रही है। आज लोग बच्चे इसलिए पैदा कर रहे हैं कि वे उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। आज religious insecurity के कारण भी हमारे देश में population बढ़ रही है और हमारे देश में economic insecurity के कारण भी पापुलेशन बढ़ रही है। इसलिए, महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहूगा कि population control के लिए और social insecurity को दूर करने के लिए एक social special security plan की जरूरत है, effective plan की जरूरत है। उसके लिए हमें गंभीरता से सोचना होगा। जहां तक pollution का सवाल है, pollution तो हमारे agenda में ही नहीं है। यह इंतहा बढ़ रहा है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हमें देश में एक campaign चलाने की जरूरत है - "Let us make India Hygenic."

अब हम क्या कहें, हमें दुःख होता है, हम यह कहना चाहेंगे कि pollution भी देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। Public Private Participation को replace करो और PPP यानी Poverty, Population and Pollution के बारे में आप कोई सकारात्मक नीति बनाओ। आपने बजट में यह वायदा किया है कि हम अगले 5 सालों में slum free India बनाएंगे। हम यह कहना चाहते हैं कि यह आज़ादी का 62वां साल चल रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : अब आप conclude कीजिए।

श्री अवतार सिंह करमीपुरी : हम conclude कर रहे हैं। यह एक गंभीर issue है। Where is the uterus which has created slum India. Let us identify it. The Congress and the BJP, both have ruled India. Both are the uterus, जिन्होंने slum India produce किया है। आज इस देश में 14 करोड़ लोग सड़कों के किनारों पर गड्ढों में बैठे हैं। एक तरफ जिंदा लोग हैं, जो सड़कों के किनारे पर बैठे हैं और दूसरी तरफ मुर्दा लोग हैं, जो पार्कों में पड़े हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : ठीक है, आपने कह दिया, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : इसलिए हम यह कहना चाहेंगे कि इसके लिए हमें constructive plan बनाने की जरूरत है। इसके अलावा Scheduled Castes and Backward Classes की इस देश में जो दशा है, उन पर day-by-day atrocities बढ़ रही हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : अब आप समाप्त कीजिए, अन्यथा यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : बैकवर्ड क्लास की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है।

श्री उपसभापति : वीरेन्द्र भाटिया जी, आप बोलिए ...(**व्यवधान**)... करीमपुरी जी, आप बोलते ही जा रहे हैं, हमें वक्त की कमी है, ...(**व्यवधान**)... अब आप conclude कीजिए।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : हम conclude कर रहे हैं, just one line, please. ***...(Interruptions)...***

उपसभापति महोदय, महोदय, बहुत से स्टेट्स, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अब तक लागू नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि केन्द्र की सरकार यह फैसला करे कि उनकी ओर से स्टेट्स को जो मदद की जा रही है, जो स्टेट्स इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू न करें, उनकी सहायता बंद की जाए।

श्री वीरेन्द्र भाटिया (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, क्योंकि साहू साहब को अवसर देना है, इसलिए मैं बिल्कुल संक्षेप में केवल 4 बातें कहना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से पहली बात तो यह कहना चाहूंगा कि वकीलों पर, लीगल सर्विसेज़ पर और डॉक्टरों पर जो सेवा कर

लगाया गया है, service charges लगाए गए हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। वकील, न्याय व्यवस्था का अंग है। अगर न्याय व्यवस्था पर सर्विस टैक्स लगाया जाएगा, तो जो litigant है, उसको न्याय और महंगा पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर डॉक्टर्स पर सर्विस टैक्स लगाया जाएगा, तो पेशेंट से वह वसूलेगा, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और अर्ज़ करता हूं कि इसको वापस लिया जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं श्री राजीव शुक्ल की बात से इत्तफाक रखता हूं कि जब आपने प्रिंट मीडिया को, जर्नलिस्ट्स को सुविधाएं दी हैं, तो जो दूसरी मीडिया है - टी.वी. मीडिया है, वीडियो मीडिया है - उनको भी उसी प्रकार से सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसलिए मैं श्री राजीव शुक्ल जी की इस बात का समर्थन करता हूं।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि आपने जो मध्यम वर्ग को आय कर में रियायत दी है, वह बहुत कम है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उसे बढ़ाया जाना चाहिए।

चौथी बात मुझे यह कहनी है कि इस समय मकानों की आवश्यकता कम हो गई है और मकान बनने कम हो गए हैं। जो लोग होम लोन लेते हैं, उस पर ब्याज की दर कम की जानी चाहिए और हम लोग जो रिपेमेंट करते हैं, उसमें और सुविधाएं दी जानी चाहिए।

अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हमारे BSP के साथी बोल रहे थे और वे Public Private Partnership का विरोध कर रहे थे। पहले वे अपने राज्य में देखें, जहां सारी योजनाएं Public Private Partnership पर चल रही हैं। पहले वे अपने राज्य की बात करें, जहां पर उनकी सरकार है ...(**व्यवधान**)... इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI S. ANBALAGAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the General Budget. I am the second speaker to speak on behalf of the All India Anna DMK, which is the leading political party in Tamil Nadu. My colleague, Shri Malaisamy, who was the first speaker from my party, with his background as a former bureaucrat, has done his job rightly and aptly. I will supplement his viewpoints here and there on certain areas which, I consider, are relevant to be brought to the notice of the House.

Sir, this is the first Budget of the new Government. The expectations of the people were very high, but the allocations for important sectors such as agriculture, infrastructure, power and for the National Rural Employment Guarantee Programme are very meagre, when compared to the need in these sectors. As rightly observed by my party leader, Puratchi Thalaivi Amma, though the decision to provide BPL families with 25 kg of rice or wheat every month at Rs.3 a kg is welcome, yet non-allocation of specific funds for the same raises question mark about the implementation of the scheme. Sir, I want a clarification from the Government about the method adopted in the selection of beneficiaries of this scheme. I want to put across certain aspects for the consideration of the Government. Firstly, the Government will have to see that the benefits go to the real beneficiaries. Secondly, quality should be taken care of; and thirdly, the programme should be implemented effectively. I request the Government to form a Committee comprising MLAs, MPs, along with officials and two or three representatives of the local bodies to monitor its implementation without any lapse. Sir, how can the Government assure food security to the poor when they have actually

reduced the foodgrains provided to the poor? Under the Antyodaya Scheme, they have now reduced the quantity from 35 kg to 25 kg, and have also raised the issue price from Rs.2 to Rs.3 per kg. These days, two-wheelers and tractors are widely being used by farmers to carry their agricultural produce. Moreover, they have to run their pump sets on diesel due to the acute problem of power cuts that is very much in force in my State of Tamil Nadu. I, therefore, request the Government to consider giving them 25 per cent subsidy on the market price of petrol and diesel.

Sir, exemption of Central Excise Duty to small scale industrial units is given to the extent of Rs.1.5 crores. This is inadequate. The exemption should be increased to a minimum of Rs.3 crores, which will be very much useful for the development of small scale industrial units. Ultimately, this will create employment opportunities in the rural area.

The marginal increase in income-tax exemption makes very little sense in the context of spiralling price of essential commodities. The huge middle class of the country will not be benefited from this. I request the Finance Minister to raise the income tax exemption limit to Rs.5 lakhs.

The AIADMK, in its election manifesto, had promised that if voted to power, it would prevail upon the Indian Government to sanction Rs. 10,000 crores as rehabilitation package for the Eelam Tamils. The Finance Minister's announcement of Rs.500 crores for the rehabilitation of Eelam Tamils is quite meagre; they are only paying a lip service to their cause. There is a proverb in Tamil – Yanai pasikku solapoori, meaning to say, giving peanuts to a hungry elephant. On behalf of my party, the AIADMK, and the General Secretary of our party, Puratchi Thalaivi Amma, I urge upon the Government to sanction Rs. 10,000 crores as rehabilitation package for the Eelam Tamils.

Another point is that there are 20 lakh unemployed youth who are educated and have the skills. But the Government has not announced any scheme for providing employment opportunities for these skilled persons. Without proper employment opportunities in the country, the youth of our countries are going to foreign countries in search of jobs. Hon. Member spoke in Tamil) Why should one go elsewhere when everything is available in this country? Sir, let me conclude with a Tamil quotation. Tamil It means, alertness, learning and bravery are the three basic traits of a good ruler. The people expect these qualities in their Government. Insofar as this Budget is concerned, these expectations have not been met by the Government.

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार) : शुक्रिया महोदय, आज प्रश्नकाल में मेरा भी एक सवाल आया था लेकिन वक्त खत्म हो गया। वहीं से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं कुछ पूछना चाहता था, मैंने कुछ पूछा भी, लेकिन मंत्री जी का जवाब नहीं मिल सका। महोदय, उस जवाब में सरकार ने यह कहा कि जो मंदी की मार पड़ी है, जिन सेक्टर्स में पड़ी है, उसमें वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग अव्वल है। महोदय, हम उनसे पूछना चाहते थे कि खेती के बाद आज भी इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर रोज़गार मिलता है, तो यही बुनकरी के धंधे से और कुटीर उद्योग के धंधे से मिलता है। इन पर मंदी की मार पड़ी है, ये लोग बेरोजगार हुए हैं, ये खुदखुशी कर रहे हैं। बुनकरों के द्वारा

किडनी और खून बेचने की घटनाएं इस मुल्क में हुई हैं - आंध्र प्रदेश से लेकर, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? पिछले बजट में और इस बजट में इस मुल्क के जो दस्तकार हैं, इस मुल्क के जो कारीगर तबके के लोग हैं, बुनकर हैं, धुनकर हैं, दर्जी हैं, वे सरकार से यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि जिस तरह से सरकार ने किसानों का 60 हजार करोड़ रुपया कर्ज माफ किया, उसी प्रकार सरकार उनके बारे में भी सोचेगी। हम किसानों की कर्ज माफी का समर्थन करते हैं लेकिन ये जो दस्तकार हैं, आर्टीजन हैं, बुनकर हैं, ये तो लैंडलेस हैं, भूमिहीन हैं। इनकी कर्ज माफी क्यों नहीं होगी? इसी सदन में यूपीए-टू सरकार आई है। पहले वाघेला जी कपड़ा मंत्री थे। इन्होंने कहा था कि पीएमओ से हमारी बात चल रही है। उन्होंने कहा था कि जो बुनकर हैं, जो दस्तकार हैं, वे कर्ज वापिस करने की स्थिति में नहीं हैं। उनके संबंध में हमारी पीएमओ से बात चल रही है। हम लोगों ने उम्मीद की थी कि प्रणब दा इस संबंध में कुछ पेश करेंगे। पिछली दफा उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया था, इस बार बुनकरों का और दूसरे गरीब तबके के कारीगर लोगों का कर्ज माफ करेंगे। उनका कर्ज ज्यादा नहीं है। आपने वहां 60 हजार करोड़ माफ किया, यहां आपने इसी हाउस में कहा था कि 800 से 1200 करोड़ रुपया कर्जा है। फिर आपने बताया कि बढ़कर 3500 करोड़ रुपया हो गया है। इसे क्यों नहीं माफ किया? इस हाऊस के बाहर प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह घोषण की थी कि किसानों को जिस रेट ऑफ इंटरस्ट पर कर्ज मिलता है, उसी रेट ऑफ इंटरस्ट पर हम बुनकरों को भी कर्ज देंगे? वह आपने इसमें क्यों नहीं दिया? आखिर आपकी बुनकरों से क्या दुश्मनी है? ये बुनकर लोग ही हैं जो आज भी इतनी मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं। आपने क्लस्टर बनाने की बात इसमें कही है। लेकिन आप भूल गए - बिहार में भागलपुर में भूल गए, नाथ नगर भूल गए, चम्पा नगर भूल गए, मानपुर भूल गए, जो गया के पास है - वहां आपने इनके लिए कोई स्कीम नहीं दी। इस प्रकार से आप बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे? उसी तरह से माइनॉरिटी की बात है। पिछली बार अंतुले साहब केबिनेट मिनिस्टर थे। माइनॉरिटी का बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है कि हमारा उस तरफ बहुत ध्यान है। क्या ध्यान है? आपका केबिनेट मिनिस्टर था, इस बार आपने सलमान खुर्शीद साहब को राज्य मंत्री बनाया। और आप कहते हैं कि बजट में हमने सत्रह हजार चालिस करोड़ दिया, एक हजार करोड़ पहले था, आपने बाद में छः सौ पचास जोड़ा था, अभी आपने नौ सौ जोड़ा है। तो यह जो * है तथा अखबार वाले लिखते हैं कि प्रणबदा बंगाल का जादू दिखला रहे थे, वहीं मौलाना आजाद फाउण्डेशन का जोड़ करके, मॉयनोरिटी फाइनेंसियल कार्पोरेशन का जोड़ करके तथा सारा जोड़ करके आपने किया है। आप मॉयनोरिटी की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं और मॉयनोरिटी के लोग इस बात को समझते हैं। सर, आखिरी बात कह करके मैं खत्म करना चाहता हूं। बिहार के साथ आप जो सौतेलापन कर रहे हैं, छः हजार करोड़ की सतरंगी योजना हम लोगों ने दी, आपने कहा कि बजट में हम कृषि पर ध्यान दे रहे हैं, छः हजार करोड़ की सतरंगी योजना में तिलहन, दलहन के लिए तथा दूसरे विकास के कार्यों के लिए हमारी सरकार ने बनाकर दी है, परन्तु आपने एक पैसा उसमें नहीं दिया। कोसी की त्रासदी में आप गए थे और कोसी की त्रासदी में हम लोगों ने चौदह हजार आठ सौ आठ करोड़ मांगा था, लेकिन आपने एक हजार करोड़ दिया। इसमें आप बाकी रकम क्यों नहीं देते हैं?

श्री उपसभापति : आप समाप्त कीजिए।

श्री अली अनवर अंसारी : वे उल्टे एक हजार करोड़ मांगने की बात करते हैं, यह किस तरह का आपका दो तरह का नजरिया है और सौतेला व्यवहार है? हम कहना चाहते हैं कि ये चाहे बुनकर हों, चाहे बिहार के लोग हैं

* Expunged as ordered by the Chair.

आपकी दया और मेहरबानी पर नहीं है। यह हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, यह हमारा अधिकार बनता है। अगर आप नहीं देंगे तो डेमोक्रेसी में जो रास्ता हमारे पास है उस पर हम चलकर अपना अधिकार लेंगे।

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, the voice of Bihar cannot be subdued.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now, Shri M.P. Achuthan. You have govt five minutes; not more than five minutes. ...*(Interruptions)*.

SHRI M.P. ACHUTHAN (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, since various aspects of the Budget have already been discussed by many Members, I will confine myself to three or four points because the time is very limited. Sir, this Budget lacks a realistic assessment of the economic situation in the country and sets feasible targets which are not attainable in the prevailing situation. Take the case of growth rate. The Finance Minister visualises 9 per cent growth rate this year. According to the IMF, the World Bank and the ADB, the growth rate will be below six per cent this year.

Sir, the Finance Minister really sets the targets by under-estimating the gravity of the global economic situation and its impact on our economy. The claim that stimulus packages are yielding results does not match with the situation in the industry or in the export sector. The-exports are going down. The downward trend in the manufacturing sector is continuing. All indicators suggest that this trend will continue. Why is that the stimulus packages have failed? Why does it not mitigate the sufferings of millions of workers adversely affected by the economic, slowdown? The reason of that is the lop-sided policy of the Government. There is over-emphasis on industry, that too, on the corporate sector. The beneficiaries of the stimulus packages and the concessions are industrialists. Last year, according to the Budget papers, Rs. 4,50,000 crores were given by way of concessions.

Sir, the Government has totally neglected the agricultural sector. Without achieving and sustaining, at least, 4 per cent growth rate in agriculture, we will not be able to achieve 8 or 9 per cent growth in the GDP. That is simple. For this, the Government must come forward with a stimulus package of, at least, Rs. 1,00,000 crores for the agricultural sector. It must be a comprehensive package, covering irrigation, seeds, fertilisers, remunerative price of agricultural products, State marketing, processing of agricultural products and everything connected with agriculture. Simply giving more credit to farmers will not help them. The Government is not ready to reduce the interest rates of agricultural loans. Without ensuring remunerative prices, cheap inputs and market facilities, the farmers will not be able to repay the loan. The net result will be pushing the farmers into the debt trap. A pragmatic and feasible solution was suggested by Swaminathan Commission, The Commission suggested giving agricultural loans at the rate of interest of four per cent. In this connection, I would like to bring to the notice of the Government the experience of Kerala. In Kerala, the cooperative sector, is giving the loans at the rate of four per cent to farmers. Moreover, paddy farmers are getting interest-free loan. The Kerala Government is procuring paddy at the rate of

Rs.11 per kg. What is the net result of all these steps? Now, the production and productivity of paddy in Kerala has increased substantially. So, the Government of India must take action to give loans to farmers at four per cent interest rate.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI M.P. ACHUTHAN: Yes, Sir. There is a change in the fertilizer policy. Subsidy on fertilizers is a welcome step. But, I fear that there is every possibility of fertilizer companies hiking the price of fertilizers they sell and corner the benefit of subsidy. So, the Government must ensure that the fertilizers are distributed at a fixed price and then only the farmers would get the benefit of fertilizer subsidy.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, please conclude. You have exceeded your time, please conclude.

SHRI M.P. ACHUTHAN: I have only one last point connected with the people of Kerala.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, you cannot go on speaking. You had made a special request since your party had no time left. Please conclude.

SHRI M.P. ACHUTHAN: I am concluding with only one last point, because it is agitating the people of Kerala. We expected that in this Budget the government will announce some package or help to the NRIs returning from the Gulf countries. Thousands of workers are coming back from the Gulf countries because of the economic crisis, and they are mostly from Kerala. It affects the economic situation and the social sector in Kerala. The Government of India must formulate and announce a package to help and rehabilitate the NRIs returning from the Gulf countries to Kerala.

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA (Nominated): Thank you, Mr, Deputy Chairman, Sir. The decisive election mandate has significantly altered the context and the expectations from the Budget that prevailed before the results were out. In a sense, the mandate has reflected new India's changing aspirations. While on the one hand, it has given greater power to the UPA Government to frame policies and implement decisions, on the other hand, it has shown the importance of growth with equity as the guiding principle for all future Governments.

Sir, the Budget must be viewed against the changed political backdrop as also the green shoots which are appearing to show up in the economic domain. This is a Budget for Bharat. The UPA Government has made handsome allocations for programmes pertaining to rural India and to the urban poor. It is part of their aam aadmi agenda which they have pursued all along. In doing all this, however, they have risked an alarmingly high fiscal deficit at Rs.4,00,000 crores or 6.8 per cent of the GDP. I think, it is, perhaps, the highest in more than a decade. The underlying assumption, of course, is that this greater spending will provide a stimulus to the economy till such time the private

sector investments and the private sector also regain the momentum of boom years. The Finance Minister had two options before him, either to provide a stimulus to the economy or to resort to fiscal rectitude. He has chosen the former. To my mind, it is a gamble, but it is a bold decision and the only way forward.

Unlike the other stimulus that had been provided, this one gives money in the hands directly of the public, of the consumer. This along with ceiling in the personal income tax which in itself would give about another Rs.9,500 crores of disposable income, all this should help to create demand and generate growth, I would like to congratulate the Finance Minister for taking this very bold decision. But there is a concern because the revenues have been shown as that. Therefore, where would the increased money come from? It is bound to put pressure thereby driving up interest rate, making loans much more expensive for the private sector which has just started seeing the upward swing. The Finance Minister's decision, however, to continue with some of the other fiscal stimulus measures to the private sector are a welcome step and indicate his intention to build on the momentum that has been generated. The increase in the minimum tax, however, is a bit of a dampener and with due respect I would like him to consider looking at some sort of review of this. There are many other welcome measures abolishing the FBT, which was a draconian tax and in other targeted areas such as SME sector and the export sector. I have a suggestion for the Finance Minister's consideration. As far as SME sector is concerned, where one is seeing the majority of the job losses, at the moment, the SME sector can only go to the RBI for debt restructuring. That only postpones the problem; it does not do away with it. Many countries have adopted a model where an equity fund is set up to take equity in such small-scale sector units that are found feasible. This will help them to clean up the balance sheet, help them to take fresh loans and go a long way in trying to restore their health. I would like to leave this suggestion for the consideration of the Finance Minister. He has also spoken about bringing India back to the 9 per cent growth. This, to my mind, is not going to happen very soon. This cannot happen unless we see the signs of revival of global economy. However, the return to high growth will only be sustainable when we address the issues of our infrastructure, the gaps in our infrastructures, both hard and soft. Sir, the state of play as far as power sector is concerned, is perhaps the area of the biggest concern.

The Economic Survey also acknowledges that the power sector exhibited considerable shortfall in recent years and due to this the energy shortage has only increased. There is an urgent need for us to reverse this. The Survey also showed that the growth in electricity generated from power utility in 2008-2009 was actually only 2.7 per cent as opposed to the target of over 9 per cent. Our per capita consumption of power also is abysmally low. We are only one-third of China and one-fourth of Brazil. If India wants to emerge as an economic superpower; we cannot be a nation devoid of electricity. The Budget has set aside a good allocation of almost Rs. 16,000 crores, but to my mind, the problem

is not in budgetary allocation, the problem is in transmission and distribution. The state of the electricity boards, the state of the DISCOMS is financially not viable. Projects face an issue in terms of land acquisition, as we have discussed earlier today, in environmental clearances and there are contractual obligations, which are very difficult to meet. This along with other areas in infrastructure development whether it is shortage of ports with ports being congested, airport modernisation needs to be speeded up as also the highways and roads. All this, Sir, is proving to be a bit of a bottleneck if we want to return to a sustained 9 per cent growth. However, Sir, just having wider roads, just having more ports and airports, to my mind, is not going to solve the situation. In the long term, we also have to address what the Prime Minister has termed as the issues pertaining to soft infrastructure. So, the next big leap for India's economy really hinges on our ability to go big on education, to rapidly expand our healthcare system and to help evenly distribute the benefits of high growth. Almost a third of our population is illiterate and only 12 per cent of those who go to primary actually reach colleges. Only one-fourth of those who have got their degrees or who are graduates are employable. This is a pathetic situation leading to a lot of demoralisation.

When the UPA came to power in 2004 it listed, providing universal access to quality education and to health amongst its seven core objectives. In the subsequent Budgets, unlike the previous Government, it made budgetary allocations and the amounts put aside for education and health more than multiplied. It went up almost three times for education and it doubled for health. This Budget too has seen a very good increase, almost 19 per cent for education and 22 per cent for health. Hopefully, the thrust on higher education with more IITs, IIMs and institutes of vocational training which to my mind are the need of the hour, to try and harness the energies and the skills of those who drop out and try and train them to get employment is something that the Government has been focussing on and needs to be speeded up even more. Sir, I will just end by saying that the lesson from the elections and also from India's growing resilience in the face of the economic downturn is that it pays to concentrate on inclusive growth and the efficacy of programmes such NREGA and Bharat Nirman more than point in this direction, but, there is an issue in terms of implementation, and, therefore, its the last mile delivery, it is the delivery system which has to be made much more robust. So right from infrastructure to rural employment the key is in the execution. Also the decision to bring in the Food Security Act is a very, welcome step. Once again the delivery mechanism needs to be in place. The Budget has taken a big gamble in allowing for a very high fiscal deficit. The gamble has to pay off and it is time, Sir, I would like to request that the money must speak.

सरदार तरलोचन सिंह (हरियाणा) : शुक्रिया सर, हम लोग बजट पर बहस कर रहे हैं। बड़े अच्छे-अच्छे लोग बोले, रिज़र्व बैंक के गवर्नर बोले, economist बोले, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा कि deficit financing बन गया, कम्युन्स्टि पार्टी के लीडर्स ने कुछ और राय दी। मैं बड़ा हैरान हूं क्योंकि इस देश में जो बीमारी की जड़ है, वह population है। इस देश में जो population की ग्रोथ हो रही है, चाहे जितनी भी स्कीम्स बना लो - अभी सेंसस आने वाला है, एक साल रह गया है-सारी स्कीमें धरी की धरी रह जाएंगी जब यह पता चलेगा कि मुल्क में जो ये कहते हैं

कि बेरोजगारी भत्ता, यह भत्ता, वह भत्ता, जब लेने वाले कई करोड़ बढ़ जाएंगे तो स्कीमें कहां जाएंगी? रूलिंग पार्टी में आज तक I have not seen a single person who could dare to say कि population की प्रॉब्लम को हमने टैकल करना है। आप इस बात से डरते क्यों हैं? चीन ने क्या किया? कितने लॉज़ बनाए? आज चाइना क्यों आगे जा रहा है, because of population control और India is failing on every front because of population explosion. आप पांच साल के लिए लीडर हो, इतने वोट ले आए, अब क्यों डरते हो? किस वोट बैंक से डर रहे हो, यह कहने के लिए कि population के लिए कुछ करें। मैं हैरान हूं कि सब बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े लीडर्स बैठे रहते हैं। This is not a political issue. This is an issue for India. All parties should have a joint conference कि population के लिए क्या किया जाए। सर, दूसरी बात मैं फार्मर्स के संबंध में कहना चाहता हूं। यहां पर बहुत कुछ कहा गया कि 71,000 करोड़ रुपया लोन वेवर दिया। यह सबको पता है कि पंजाब और हरियाणा इंडिया का 80 परसेंट फूड देता है। मेरे दोस्त नरेश गुजराल बैठे हैं, ये हर रोज़ पंजाब के बारे में बोलते हैं। आप हैरान होंगे कि Out of 71,000 हरियाणा और पंजाब का शेयर is less than three per cent. पंजाब में सिर्फ 1,000 करोड़ रुपया मिला है, Out of 71,000 जो आपको 80 परसेंट फूड देता है, उसको आपने क्या दिया है? इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे लोन वापस करते हैं। जो लोन वापस करे, उसको कुछ नहीं और जो न दे, उसके लिए स्कीमें हैं। आप wasteful expenditure की तरफ से ध्यान हटाओ। ये नयी-नयी स्कीमें रोज़ लाते हैं जैसे गांव में employment scheme है, ये सारी स्कीमें वेस्ट जा रही हैं। किस गांव में आज तक क्या बना है? एक गांव मं आप कह रहे हैं कि कोई नाली बना रहा है, कोई कहता है कि गड्ढे खोद रहा है, उससे देश को क्या फायदा है? ऐसी constructive scheme हो, जिससे देश का बेनिफिट हो इसलिए फार्मर्स पर ध्यान दो कि फार्मर क्या चाहता है? वह चाहता है कि इंटरस्ट रेट 4 परसेंट हो। आप कहते हैं कि 7 परसेंट देंगे और अगर आप पैसे वापस दोगे तो एक परसेंट वापस करेंगे। कौन आपको टाइम पर देता है? कैसे करते हो? क्यों किसानों के साथ मखौल करते हो? जब तक किसान को आप फुली सेटीस्फाई नहीं करते, तब तक कुछ नहीं होगा। अब क्या हो रहा है कि पंजाब हरियाणा में 20 per cent less sowing चावल की हुई है। बारिश नहीं है, बिजली नहीं है, डीज़ल महंगा है। अब क्या हो रहा है कि Every farmer is spending Rs. 300 per acre every day ताकि उसकी पैडी बच जाए। सरकार उसको क्या देगी? अभी पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, वे गरीबी रेखा की तरफ जा रहे हैं। आपने कुछ नहीं दिया। उनका डीज़ल भी at least, now, the price of diesel in Punjab and Haryana for farmers should have been Rs. 10 less than other parts of the country so that they will be able to grow more and get more water. लेकिन आपने इसके लिए कुछ नहीं किया।

सर, आप हैरान होंगे कि sowing में केवल paddy नहीं, बल्कि जितने oilseeds हैं, मक्की है, बाजरा है, इनकी 50% से less sowing हुई है। आप इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि मुल्क में danger आने वाला है। यह आप सबके सामने है।

सर, एक और बड़ा मसला है। मैंने सुबह नोटिस दिया था, लेकिन आपने नहीं माना, कि हजारों लोग इस वक्त स्पेन में हमारी embassy के बाहर बैठे हैं। वे इसलिए बैठे हैं कि फ्रांस, इटली और स्पेन ने अपने law को liberalize किया है to give citizenship to more people. Indians are more entitled than other. लेकिन MEA वाले उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। The Ministry of Home Affairs and the Ministry of External Affairs should

join hands to provide identity certificate to all Indians who are in the Middle East, European countries so that they can apply for citizenship. अब इतनी बात करने के लिए आप कहते हैं कि होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी भेजी है, होम मिनिस्ट्री कहती है कि हमने स्टेट को भेज दी है। चार साल पहले यह स्कीम आई थी। मैं उस समय Minority Commission का चेयरमैन था। मैं इसके लिए बहुत लड़ा। पाकिस्तान के 15 हजार लोग भर्ती हो गए, लेकिन एक भी इंडियन भर्ती नहीं हुआ, because Pakistan Embassy is all out to help Pakistanis. Indian Embassy तो लोगों को नजदीक नहीं जाने देती।

सर, फ्रांस में पगड़ी का केस पहले ही था, अब पिछले हफ्ते शारजाह में आर्डर कर दिया गया है कि कोई सिख ड्राइवर पगड़ी पहन कर गाड़ी नहीं चला सकता। बसों पर जितने सिख हैं, वे नौकरी से हट गए, क्योंकि पगड़ी की पाबन्दी लग गई। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे एनआरआई के मिनिस्टर हमेशा मिडिल ईस्ट जाते हैं, वे हमारा यह इश्यू हल कराएं।

सर, टूरिज्म के लिए सारी दुनिया कहती है कि टूरिज्म बढ़ रही है because of the religious destinations. अब सबसे बड़ी destinations अमृतसर और वैष्णों देवी, जम्मू हैं। मेरी सरकार से विनती है कि वैष्णों देवी और अमृतसर के लिए एक joint project बनाए, ताकि विदेशों से जितने लोग आएं, वे अमृतसर land करें और दोनों जगह जाएं। इसके लिए आप अमृतसर एयरपोर्ट को ठीक कराएं।

सर, minorities के बारे में सरकार keen है, हम इसके लिए सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। यह बहुत अच्छा है। आप minorities की जितनी मदद करेंगे, उतना अच्छा है। आपने अभी एक स्कीम यह दी है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ रुपए नया कैम्पस खोलने के लिए दिया है। सर, चार साल से एक स्कीम pending है। अमृतसर यूनिवर्सिटी में Guru Granth Studies Institute बनना है। प्रधान मंत्री जी ने खुद इसे announce किया है। चार साल हो गए। प्रधान मंत्री जी के एलान की यह value है! चार साल हो गए और अभी तक सरकार ने उस पर sanction नहीं दी है। यूनिवर्सिटी जमीन free दे रही है, लेकिन हर बार नई कमेटी बनती है। अभी मैंने सवाल पूछा था, तो कहते है कि हां, कमेटी work कर रही है। गुरु ग्रन्थ केवल सिखों के लिए नहीं है, यह सब धर्मों के लिए है। वह इंस्टीट्यूट pending पड़ी है। उसमें आज तक सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है, हालांकि इसका benefit inter-faith होगा, जिसका सबको benefit होगा।

सर, यह जो सर्व शिक्षा अभियान स्कीम है, अभी मैं पार्लियामेंटरी कमेटी की तरफ से तीन-चार स्टेट्स में गया था, मैं तो सुन कर हैरान हो गया कि स्कीम में क्या हो रहा है। आप जो टीचर engage करते हैं, वे under-matric हैं, और 50% matric होते हैं। अब आपके पास टीचर्स ही नहीं हैं, तो इस स्कीम मे आप करोड़ों रुपए कहां लगा रहे हैं और किसे पढ़ा रहे हैं? आप लोगों को क्यों दिखा रहे हैं कि हमने इतना पैसा दे दिया? यह स्कीम बिल्कुल properly implement नहीं हो रही है। ऐसी ही rural employment की स्कीम है। इन दोनों स्कीमों को सरकार review करे और यह देखे, ऐसे ही अपनी फिगर बनाने के लिए कि यह किया, ऐसा नहीं होना चाहिए।

सर, आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए शुक्रिया। आप हमेशा हमें टाइम देते हैं, I am always grateful to you. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Keshava Rao. You have ten minutes.

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Sir, I have now been called upon to speak at this stage of the debate and given ten minutes. I think, in the economic jargon, 1 will not be adding any value addition to it for the simple reason, I would not, first, repeat anything that has been said. Second, all that has to be said, in defence of the Budget, is there in facts and figures in the Budget speech. Besides, the Economic Survey has fortified the same thing. But, nonetheless, I was tempted to correct, with all humility, the distortions that have been brought in by my friends from the other side. Sir, I should not be mistaken here. Simply, the major Opposition thought that we were anti-people. First of all, we must know what exactly these people are. If these people thought that India Shining was people; if these people thought that the Zone of India in a country like India were the people, let them. The people have been looking at this Budget with a lot of interest for two simple reasons. Number one, we had got an increased mandate, not without any reason. Number two, we were speaking during this poll campaign to many issues which were very interesting and very basic to the livelihood of this country. And, there were my friends who had been opposing us.

Now, the results have shown, that means, the people have shown, the mandate has shown, the ballot has shown that you were wrong and I was right. I am saying this with all humility; I am not saying that I am a great man here. After all, all of us are patriots. I know we differ; that is why, I heartily welcome the heartening remarks that Mr. Arun Shourie made in the very first sentence. He said that he had congratulated India for its stand in the ADB, where we won the vote and got the loan for Arunachal Pradesh. That should be the spirit. That is our spirit. When we discussed the Motion of Thanks to the President's Address in the House, we did say that we have not won, we have been likened by the people; the people thought that our programmes were right, they thought that our schemes were right; that is why they voted for us. But that does not mean that they have rejected you, they have doubt for you. You have been my good friend. This is exactly what was mentioned by Mr. Yechury. Their Left friends are here. We have never said that we have left you. All that we have done in the elections is that we stood steadfastly to what we believed. Socialism was not taught to us by the Leftists. The land to the tiller was not given by the Left here; it was given by Gandhiji and we stood by it. All that you wanted to do is, whenever we took a stand, really wanted a shore; or get blackmailing grip that you had over us. This is what exactly you really wanted to do. When the majority of the House took a particular stand on an issue where you were also a partner from outside and you had a different view, instead of arguing and convincing us of that view, what you did was to try to vote us out. That exactly is considered as blackmailing. But, yet, let me tell you, we have to accept that your friendship, your association lasted for four years.

But that does not again mean that whatever socialist programmes that we had undertaken were due to you, as Mr. Yechury tried to say. Nationalisation of banks was not your theme. Years back when banks were nationalised, it was an Indiraji's decision. If the Communists want to take credit for it, they can join the bandwagon but should not take the total credit for it. Let us take the Budget. Sir,

I am only trying to correct the distortions. I will not repeat what has already been said. As a matter of fact, I have brought all those things, but I thought not to do so. Let the Communists be very clear on this point. When we have come here, when the new Budget has been presented, it has adhered to what. It has adhered to the same CMP which Mr. Yechury, sarcastically, put as UPA-II. The UPA-I, the CMP of your liking has become the article of faith with us. The real focus today is the rural India; the focus, today, is the aam admi, the focus here is nothing but social democracy. Mr. Abshishek Singhvi tried to debunk most of the untenable arguments made by the BJP friends. I would only sympathise with Mr. Abhishek Singhvi because I know Shri Venkaiah Naidu more than most of the people do. He is one of the best friends, a very good politician, a good Statesman but economics has been his weak forte. Economics has not been his forte but even he said, Sir, that we were anti-development oriented.

I want to know what exactly this anti-development orientation is. He said, 'when you are trying to get the money and trying to spend it, this is anti-development oriented. Now, this is a new theory. Abhishek Manu, of course, treated us to a greater span and he quoted right from Adam Smith's classicism to Feedman's comments, to that of Keynesian intervention of economics to that of new neo-liberalism of our friends. All that we have seen-but that is not necessary now. But if we are trying to look at our own self, the present position, I am coming to the Budget now, what exactly has the Budget tried to do? Whenever we are trying to debate a Budget, we must know when it is being brought. The time and space are the two important things that we look into even in the Budget. Presently, we are going through a worst kind of global crisis since the 1930s. Though it cannot be equated with the Great Depression, nonetheless, the situation is akin to that. We don't have the stagflation today. We don't have that kind of a recession today. But, yet, millions of jobs have been lost. People are out of jobs. The prices have gone up. The exports have got a beating. Although we are not very much impacted by the crisis, but as a part of the inter-dependent world, we cannot claim that we are insulated. So, we did have its impact on us. Against that background of global crisis, against the background of our own failures, we had to come out with the Budget as a solution. What could be the solution? The solution is two-fold. One is, have more growth Earlier we had a blistering growth of 9.9 at one time. It came down to 6.2 but it is now being said that it will go up to 6.7. Having seen that growth, we are thinking, can we get back to that? Can we revive that growth rate? How can it be done? It can be done when you mobilise your revenues. How do you do that? Can this particular situation of financial crisis period give us the strength to get that kind of money? Even if we have that kind of money, what kind of other resource that should be there? How would you distribute it?

So, these two things became very important for our Finance Minister to look into. Now, this situation cannot give us more taxes. Mr. Yechury himself has said that we cannot milch the cow any more. So, we have to go up to a certain stage. Still if some gap is there, what needs to be done?

Should we sit quiet? As Mr. Venkaiah Naidu has said, "To keep the blanket full and not even show your feet out." We cannot do it and the Congress Party will not do it. A great responsibility has been cast on us. The people have offered us their support today. According to some, it might be 7 per cent. According to me, it might be something more. I am not going to repeat Mr. Arjun Sen's report here. But, nonetheless, it is certainly more than what we have been thinking. So, what we need to do is, if the private sector is not coming up, even if foreign capital inflows are going out, are reversing, then the Government needs to step in. How does it step in such a situation? You borrow money. You created nothing but a deficit. You already have a revenue deficit. Revenue deficit is because you could not mobilise the kind of money required because the situation is not there. You cannot get it because the things are not good. At the same time, we cannot impose more taxes because the people are not prepared to pay it. So, then the fiscal deficit comes in. So, we have 6.8 or 4.3; even if you are bringing it down, this deficit becomes inevitable. I totally agree with Rangarajan. He mentioned about the vicious circle in which we could be subjected to tomorrow if this kind of situation continues to go on. But what is the way out? One has to take a risk. I am asking all the economists sitting here, can you create a capital without a risk? One who is not prepared to take a risk will lose everything. So, what I am trying to say is that this risk becomes an economic inevitable thing, inescapable thing. So, we have taken this risk and let us see how do we fill the gap. You are not believing the Government even though reports are there. Today, we are one of the fastest growing economies in the world. We are number two in the world; and if BRIC reports are to be believed, we are going to be the third largest economy in the world along with Japan and China. But even with this report with you, still you have some kind of apprehensions. You are still behaving like doubting Thomases. The Budget papers have told us about the medium-term measures which we would bring in. There is also a time-bound programme in that; within two years, it would be brought down to 3.5. Let us wait and see; from five points it would be brought down to four points. Why all are concerned about deficit is only because of the FRBM. Because we brought FRBM last time, we thought that there is a sanctity attached to the figures of zero and three per cent where fiscal deficit becomes zero and this becomes 3.5. I don't know what is the sanctity attached, but nonetheless, I would not like to comment on it at this point of time. But, Sir, let me tell you, as Mr. N.K. Singh said *...(Interruptions)...* N. K. Singh threw a spanner in our minds. He said this crisis which has come in India has not come due to the global crisis; it had come much before it. He has come out with figures. Last year, in 2008-09 when we brought the Budget – with my greatest respect for the then Finance Minister, who was considered to be one of the best five Finance Ministers of the world – Mr. P. Chidambaram, came out with some kind of a neo-liberal approach.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, Dr. Keshava Rao.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, I shall not take more than a minute. So, he has tightened the market. Today we did not have the money. So, we have that kind of a bottleneck through which we

have to go through. After that what we saw is today's situation. In the last Budget we promised a GDP growth rate of 11 per cent in the Revised Budget; how it is being anchored to the present Budget? Now, we are faced with three challenges. We would like to go back to our 9% GDP; which means all that is being done like tax rationalisation and so on ...*(Interruptions)*... Secondly, we would like to have a public spending; if not coming from the private capital, because the Government will take the responsibility and this spending will be concentrating on the aam admi and would be inclusive so that we cover all. Third and the last point, although we have talked about all this, how about implementation? Sir, all your criticism does not stand validity because the Prime Minister's Office has today a monitoring cell and we have 100 days' programme which agenda gives us everything to be looked into.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Keshava Rao, please conclude.

DR. K. KESHAVA RAO: With focus on these three areas and with a focus on people, the rural population, the poor man, I think this Budget is not only balancing but also pro-poor and inclusive.

श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, पहले तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने "नरेगा" के लिए और पैसा उपलब्ध कराया है, लेकिन उसकी monitoring भी सही ढंग से होनी चाहिए और जिस हिसाब से पैसा दिया गया है, उस हिसाब से लोगों के लिए काम भी निकाला जाना चाहिए। शिकायत यह है कि बहुत से लोगों को काम नहीं मिल रहा है और पूरे ढंग से काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उस रुपए का सही उपयोग हो और भारत की गरीब जनता को पूरा-पूरा काम मिले जिससे कि देश का विकास हो।

सर, दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि इस बजट में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कहीं कोई बात नहीं कही गई है। यह एक बहुत पुरानी बीमारी है, जो कि 13-14 राज्यों में फैली हुई है और आए दिन लोगों की जान जाने की घटनाएं हुआ करती हैं, लेकिन इस बारे में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। इसकी रोकथाम पर गवर्नमेंट का रुपया भी बहुत खर्च होता है, लेकिन सरकार इस विषय में गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए मेरा आप के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या की ओर विशेष ध्यान दे। महोदय, इसका एक कारण यह भी है कि हमारे यहां इन राज्यों में गरीबी भी बहुत है। अगर गरीबी और अमीरी की खाई को पाटा नहीं गया तो यह नक्सलवाद दूसरे राज्यों में भी फैलता जाएगा।

महोदय, अभी एक पिक्चर Slum Dog Millionaire आई थी। उसके अंदर भारत की स्थिति दिखाई गई है कि भारत कैसा है। तो एक तो वह स्थिति दिखाई गई है और दूसरी तरफ एक आदमी एक हजार करोड़ रुपए की लागत से मकान बनाने जा रहा है, जिस में वह रहेगा। तो भाई, यह महात्मा गांधी का कैसा राम राज्य है। सर, कायदे से तो इस पिक्चर को सेंसर बोर्ड की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उससे भारत को कोई उपलब्धि नहीं मिलती।

उससे बदनामी ही मिली है। इस खाई को पाटना चाहिए। अगर इस खाई को नहीं पाटा जाएगा तो नक्सलवाद बढ़ेगा। हम जो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें यह नक्सलवाद बीच-बीच में रुकावट डालेगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

उपसभापति जी, तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत के अंदर जो व्यापारी वर्ग है, उसमें 70-75 परसेंट फुटकर व्यापारी हैं। आज उसका सारा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया है। उसका सारा बिजनेस बड़े-बड़े मॉल्स में चला गया है। आज चाहे आप कनॉट प्लेस देख लीजिए या लखनऊ का हजरतगंज देख लीजिए, पूरे कनॉट प्लेस और हजरतगंज के शोरूम्स के अंदर सन्नाटा छाया रहता है। इस तरह की पॉलिसी जो सरकार की तरफ से बनाई गई है, उससे आज फुटकर दुकानदारों की वही हालत होने जा रही है, जो हालत किसानों की हुई है। इसके ऊपर सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। एक तरफ बड़े-बड़े मॉल्स बनाये जा रहे हैं और दूसरी तरफ फुटकर दुकानदारों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से नक्सलवाद फैलता जा रहा है। तीसरी बात...

श्री उपसभापति : आखिरी बात।

श्री राम नारायण साहू : अभी तो दो ही मिनट हुए हैं।

श्री उपसभापति : ऐसा नहीं है।

श्री राम नारायण साहू : सर, मैं फिल्म उद्योग पर आपको बतलाना चाहूंगा। जो 20 हजार सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर थे, उनमें से आधे से ज्यादा बंद हो गए हैं। कुछ मुट्ठी भर सिनेमाघर, जो कि तीन-तीन स्क्रीन वाले, छह-छह स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्सेज़ बना दिए गए हैं, वहीं सारे लोग जाते हैं। आधे से ज्यादा सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमाघर बंद हो गए हैं और बाकी भी बंद होने की कगार पर हैं। आखिर जब ये सिनेमाघर भी बंद हो जाएंगे तब कम आय वाली पब्लिक कहां जाएगी? जो गरीब हैं, रिक्शे वाले, तांगे वाले और छोटे दुकानदार हैं, ये लोग फिल्म देखने कहां जाएंगे? मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि जो फर्स्ट हैंड पिक्चर्स टीवी पर दिखलाई जाती है, वे एक साल बाद दिखलाई जाएं और नये पिक्चर्स की जो सीडीज़ आती हैं, वे कम से कम छह महीने के बाद लाई जाएं, जिससे इस समस्या का कुछ निदान हो सके।

श्री उपसभापति : अच्छा सुझाव है।

श्री राम नारायण साहू : मुझे बोलने का और समय तो दीजिए।

श्री उपसभापति : नहीं-नहीं। बस। अब हो गया। नेक्स्ट डा. स्वामीनाथन।

श्री राम नारायण साहू : सर, महंगाई जो है - आप महंगाई देख लीजिए।

श्री उपसभापति : देखिए, आपने एग्रिमेंट पर टाइम लिया है। आप सिनेमा की बात कर रहे हैं तो बोलने दिया गया।

श्री राम नारायण साहू : सर, एक मिनट। टीवी पर डीडी-न्यूज में जो दिखाया जाता है, उसमें यह दिखाया जाता है कि महंगाई हर हफ्ते घटती जा रही है। लेकिन इधर दाम बढ़ते जो रहे हैं। इस समय अरहर की जो दाल है, वह 80 रुपये किलो बिक रही है।

श्री उपसभापति : ठीक है, ठीक है। साहू साहब, अब आप बैठिए।

श्री राम नारायण साहू : इस तरह से हर चीजों के दाम, जैसे - सब्जी, घी, तेल आदि सारी चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे हो रहा है?

श्री उपसभापति : डा. स्वामीनाथन। ...(**व्यवधान**)... अब देखिए, मैंने इन्हें बुला लिया। आपके साथ यही मुश्किल है।

श्री राम नारायण साहू : सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

PROF. M.S. SWAMINATHAN (Nominated): Sir, I shall be brief. I want to make four points. First of all, I want to compliment the Finance Minister for the emphasis given on food security in the

Budget. We can live without anything, but not without food. The Government, both the State Governments and the Central Government, of this country have the responsibility to see that adequate food is available for nearly 120 crore of human beings and also 50 crore of farm animals like cows, bullocks, buffaloes, etc. We generally forget that they also need food. In our country, livestock and livelihoods are very, very closely related. Therefore, there is a terrible responsibility. I am very happy that the Government has now stopped the export of 6,000 tonnes of wheat. In today's world, the most precious asset of any country is its grain reserve. Two years ago, we saw in our neighbourhood, Bangladesh, prices going up. We had, fortunately, grain stock. Otherwise, we could not have managed the situation. The price of rice went up by 300 per cent within 2-3 months.

Therefore, we should maintain our food reserves at about 50 million tonnes rice, wheat, jowar, bajra, ragi and so on. The reason given to the pressure of export lobby is that our foodgrains storage is very poor, that there are lot of storage losses and post-harvest technology is very poor. Now, the answer to that is not exporting grains, but, we should now develop storage capacity. This is my own suggestion to the Finance Minister and through him, to the Government of India that at least 50 locations all over the country may be developed to create one million tonne each storage capacity of the foodgrains of the most modern types of storage system, not the gunny bags and so on where there are losses. I think, it is a worthwhile investment. It will pay us. I want to repeat again and I want to go on record that the most precious asset of any country today is its grain reserves. If you don't maintain it, you will be in serious difficulty. The other suggestion I wish to make is that in the report of the National Commission on Farmers, we have a whole chapter on food security. We had recommended the establishment of a National Food Security Board under the Chairmanship of the Prime Minister as a pan-political board where all the leaders of various political parties are presented. I feel the time has come. Probably, in the legislation that is coming up, there should be a provision for an overall political oversight for the food security system. It should be non-political. That's why I call it a pan-political board which should be established. The details are there in the report of the National Commission on Farmers.

Sir, the third is the alarming statistics – yesterday, Mr. Arun Shourie also mentioned it – on child malnutrition in our country. According to the Economic Survey, the position is very serious. Forty-six per cent of children below the age of three years are highly malnourished including in Punjab. Even though there is not so much of poverty, still 28 per cent of the children in Punjab are malnourished. Sir, we are investing lot of money in Knowledge Commission, knowledge power, super power, knowledge era and so on. But, the fundamental fact is that the brain development of a child is completed within the first three years of age. If during that time, the child is going to be malnourished, his cognitive abilities are impaired. So, you are condemning a whole set of children of our country. In an age of inclusive growth, you are excluding the children of the poor from this

knowledge era. So, I would say that the whole food security issue might decentralise the grid of storage of the most modern type with a capacity, at least, of one million tonne each at 50 locations in North, East, South, West and so on. The National Food Security Board, a pan-political board, must be established. Also, the child nutrition must receive the most urgent attention. It can be part of the National Rural Health Mission whatever may be the mechanism. ICDS is there. In spite of ICDS, we find that the statistics are alarming.

Secondly, Sir, again I would like to compliment the Finance Minister for the additional allocation he has given to irrigation water. You can do anything. But, without water, you can do nothing. Both for drinking purpose of human beings and for plants and animals, you require water. Now, I would request the Finance Minister and the Ministries concerned that at least five per cent of the money that they are allocating for bringing more area under irrigation, must be kept for improving irrigation use efficiency, the efficiency of water. They always measure irrigation by supply augmentation like more million hectares are brought under irrigation. But, we are not talking about as to what we are getting out of every drop of water. Sir, fortunately, the Ministry of Water Resources initiated two years ago a programme called 'more crop and income per drop of water' in about 2000 villages. I have studied the data. There is very interesting data. In many cases, 50 to 100 per cent more efficiency and more income can be obtained. I would request that in addition to the allocation to irrigation, at least, five per cent of it should be reserved for irrigation water use efficiency. We can draw the lessons from the programme 'more crop and income per drop of water'.

Thirdly, Sir, again the Finance Minister has rightly said and I quote, "The Women's Self-Help Group movement is bringing about a profound transformation in rural areas. 2.2 million Self-Help Groups have been linked with banks. I would suggest that we start similar Self-Help Groups for small and marginal farmers – for those who own less than one hectare. Over 80 per cent our farm holdings today are less than one hectare in size. Now, they are not satisfied. There is a stagnation. You read the Economic Survey. You can spend any amount of money. But with the efficiency of very small farms, they cannot do ecological farming, integrated pest management, scientific water management and post harvest management; all are poor. Because these are very poor small farmers, I suggest that we start a programme of Small Farmers Self Help Groups as a movement. That means, give incentives like group credit, group insurance and many others, also centralized services for decentralized production. There are schemes like Agri Busines Centres, Agri Clinics, and so on, which are not functioning. If we are not able to bring about a small farm management revolution, I am afraid, our yields will be low; we will go on making investment, but it will not pay. So, my request to the Finance Minister is, just as he has taken pride in the SHG movement among women, start a

similar one for men also. This should be for both, men and women. The *mahila kisans* will also be there in the small farmers' movement.

My fourth point, Mr. Chairman, is, the Finance Minister has, again, mentioned about the National Action Plan for climate change. Now, in the recent L'Aquila meeting, near Rome, of the G-8 countries, which the Prime Minister also attended, they have agreed, they have almost accepted a two degree centigrade rise in average temperature because, as they say, the maximum we can bring down the emissions is about 40 per cent. That will lead to two degrees; otherwise, it will be become four degrees. The two degree centigrade temperature rise has enormous consequences on our country. There are eight missions in the national mission. My suggestion is that one more mission should be added; that is for the coastal areas and the islands; 25 per cent of our population are living within 50 kms. from the shore. Most of our major cities, Mumbai, Calcutta, Chennai, Cochin and Vizag, are along the Coast. And one crore fisherman families are living there. Now, they are all endangered. We had a sample of it during the Tsunami of December 26, 2005. Sea-level rise is one of the consequences of higher temperature, of global warming. Therefore, I would say that let there be also a mission for the coastal areas. We saw in the television what is happening to Mumbai. I do not know what is going to happen in Mumbai if there is going to be a sea-level rise of one or two metres. There will be a great difficulty. They have gone right to the Coast, the Navi Mumbai. Every one of them is going right there. They are putting airports near the shore with the result that they have all been getting inundated. So, this additional mission is a very important one. This mission will be doing anticipatory research and action in order to save lives and the livelihood along the Coast.

Finally, I compliment the Finance Minister again for the Rs.500 crores to Sri Lanka. I have studied this problem in some detail. Therefore, I am suggesting that part of this money should go to the agricultural renewal of the Northern Province, i.e. the internally displaced persons. Most of them are farmers or fishermen. One is, of course, immediate demining, and so on and so forth. But, nevertheless, they should go back to their life; That means, it is really coming back to renewal of agriculture, animal husbandry, fisheries, and so on. So, there is a great opportunity for India to help these very unfortunate victims – Mr. Raja described it yesterday- of a war which was imposed on them. Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mr. Swaminathan. Now, Mr. A.K. Sengupta.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA (West Bengal): Thank you very much, Sir. I am so happy that you called me to speak on this occasion, particularly after Mr. Swaminathan, because I have also a number of suggestions to make. At this last moment, I do not want to get into the general discussion of the Budget. The only point with reference to Finance Minister's speech is that he should not feel, at all, apologetic about the fiscal deficit issue. This is not a major issue. This issue, probably, could

have been considered at a point of time when there was a huge private sector demand, a huge private sector investment. That is not taking place. More than Rs. 1,40,000 crores of money has been injected into the system; that has not been used!

[THE VICE CHAIRMAN, (SHRI TARIQ ANWAR) in the Chair]

So, I think, what he is doing is a right approach, this time, to find the ways of raising demands and give a push to the output and a push to tne GDP. I don't think we should be terribly worried about this criticism of fiscal deficit, particularly, when he has laid down a map that over a period of three years the fiscal deficit will come down. It means that he is aware that fiscal deficit should not go rampant. But at a particular time like this, is not a major issue. He should not be terribly worried about it.

Having said that, I would like to bring to the attention of the Finance Minister that if he is really trying to push his programmes of development, he must see to it that the social development programmes are actually delivered. The point is that he has given three objectives. The third objective is to effectively deliver the programmes. But how is he going to do that? He has not spelt it out and that is the most important thing to do. You must see to it that the money that you have announced, provided in the Budget, actually goes to the people for whom they are actually meant. Sir, for this purpose, I would like to make a suggestion. Please constitute an Authority which is not exactly a part of the Government so that it can retain an arms-length relationship. It is not a commission it has to be actively involved in seeing that the things are done. But an Authority which will have power to look into why a particular programme is not being delivered. It is extremely important to know in the case of NREGA and in the case of many rural development schemes. We have adequate knowledge that they are not being delivered. But there has to be an Authority to see that it is delivered and it should be able to tell the Government to pursue that purpose.

My second suggestion is this. I am very happy that Swaminathanji has raised this question of Self-Help Groups among small and marginal farmers. The Commission I headed till April this year had submitted a report on small and marginal farmers' group. Surprisingly this small and marginal farmers' group account for 84 per cent of our farming families. They get only two per cent of the credit, even less than two per cent. Actually they used to get two per cent in 2004. Now they get less than two per cent of the actual credit. In that report we have suggested that you must now adopt the policy of forming Self-Help Groups of small and marginal farmers exactly on the lines as Dr. Swaminathan has suggested. I should also mention that some such experiment has been done in Andhra Pradesh, but not exactly the way you will try to do it. But this is a thing on which I fully support Swaminathanji. In the same way, he has talked about women Self-Help Group In a sense it

is much more important because small and marginal farmers include women also quite substantially. But the new approach to help the small and marginal farmers is through Self-Help Groups.

The third suggestion is about debt management. I have seen in the newspapers a lot of talk about a Debt Management Authority. It is bad. It can't be done from outside. But there has to be a Debt Management System within the Government, with the Finance Ministry or with the RBI, which will look after the whole amount of debt that has Deen accumulated, how they can be managed over a period of time. I think that has to be taken seriously and at some point of time a mechanism has to be established.

My final point is about disinvestment. It is very clear now that the public enterprises in India were created not on any kind of ideological basis. But it was created by our founding fathers on the basis that public enterprises were, as Panditji termed, "commanding heights of the economy". You will be able to use them for guiding and channelling the resources and energy of the country. That is precisely the role the public enterprises have actually played. We have seen that from the most unlikely quarters praises are coming for our nationalisation policy. It is very interesting. Today, those who are supporting the bank nationalisation, which was done earlier, were very vocal against it at that particular point of time. But again these nationalised banks have played a role of commanding heights. It has really developed Indian agriculture and Indian savings, and a lot of things have been done by that. This is what the public enterprises have been doing. But that does not mean that their investments cannot be sold, particularly when the Finance Minister has categorically stated, the Congress Manifesto has categorically stated and the Congress President has categorically stated that they are not interested in privatisation. That is, at no point of time it will not go below 51 per cent. That will require Parliamentary approval. If that is the case, then the question of investment in public enterprises is like anybody else's investment. My investments need management. I can invest and then I can manage that investment to increase my investment. Similarly, instead of calling it disinvestments, the Finance. Minister may consider setting up an Authority or a Commission to manage public enterprise investment which would include the clause that on certain occasions these can be sold. It can also mean that it can acquire new investments. Why I am suggesting this is, it should be done openly. There should be complete transparency in this. It should not be done stealthily. It should not be done in the background. It should be quite open. There should be an Authority which would be continuously present in the market to look into the opportunities of public enterprises' investment assets, where it can be sold, how it can multiply the value, etc. and sometimes, it can actually acquire assets. I would not be unhappy at all if the ONGC sells some of its

shares in order to acquire a lot of other investments in Russia or even in African countries in the oil reserved areas. This is the way investment economics work and we should apply that to our public enterprises investment also. In that case, it is not disinvestments. It is actually investment management. That is the way the Government should actually pursue this policy. Thank you.

श्रीमती मोहसिना किदवई (छत्तीसगढ़) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो बजट पेश किया है, मैं उसकी ताईद करने के लिए खड़ी हुई हूं। जहां तक हिन्दुस्तान का ताल्लुक है, मुझे याद है कि आज हिन्दुस्तान का पहला बजट गालिबन 2000 करोड़ रुपए का था। फिर तीन हजार करोड़ का अगला बजट हुआ और बीसवीं सदी तक इसी तरह से बजट बढ़ते रहे। मुझे बड़ी खुशी है कि 21वीं सदी में जो पिछला बजट था, वह एक लाख करोड़ से ज्यादा का था और आज जो यह 2009-10 का बजट पेश हुआ है, यह भी दस लाख करोड़ से ज्यादा का है। यह दिखाता है कि हिन्दुस्तान ने कितनी तरक्की की और किस तरह से वह आगे बढ़ा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो यह बजट पेश किया है, जिस वक्त यह बजट पेश किया जा रहा था, उस वक्त मैं समझती हूं कि दुनिया के बहुत से मुमालिक एक economic crises से गुज़र रहे थे और लगता था कि दुनिया की जो economy है, वह चरमरा गई है, लेकिन मैं समझती हूं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का और हमारी यूपीए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कदम है कि उन हालात में उन्होंने इस बजट में हौंसले और हिम्मत के साथ जीडीपी को 9 परसेंट से ऊपर ले जाने की बात कही। हमने इस अरसे में देखा कि 7 परसेंट, 6 परसेंट हुई, वह भी मैं समझती हूं कि दुनिया के हालात को देखते हुए हमारे मुल्क ने इसको सहा। मैं समझती हूं कि इसमें सबसे बड़ा हाथ agriculture का है। बाय ऐंड लार्ज हमारी economy agriculture based है और हमारी 80 फीसदी आबादी इस पेशे में मसरूफ है। मैं समझती हूं कि आज जो हमने यह बजट पेश किया है, इसमें बहुत बड़ा बल agriculture पर दिया है और ऐग्रीकल्चर के नीचे जितनी चीजें आती हैं, चाहे वह horticulture हो, चाहे poultry हो या cooperative banks हों, जितनी भी चीजें आती हैं, उनकी तरफ पूरी तवज्जह दी गई है। जो सबसे बड़ी बात इसमें मुझे नज़र आती है, वह यह है कि यह बजट एक आम आदमी के हालात को, मयार-ए-जिंदगी को ऊपर उठाने का बजट है। मैं बार-बार यह कहती हूं कि यह एक ऐसा दूरंदेश बजट है, जो हमारे रहनुमाओं की जो vision है, जिसने आज़ादी के बाद के हिन्दुस्तान को अब जिस तरह से आगे बढ़ाया है, जो infrastructure बनाया है, उसी के ऊपर आज हिन्दुस्तान मजबूती के साथ कायम है। मैं समझती हूं कि इस बजट में सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, आजादी के बाद हम क्वांटिटी पर जोर देते थे कि कितने स्कूल खुल जाएं, कितने हॉस्पिटल बन जाएं, कितनी सड़के बन जाएं, कितने ट्यूबवैल लगें, ये सारी चीजें हम करते थे। लेकिन खुशी की बात है कि आज हम क्वांटिटी के साथ-साथ क्वालिटी पर जोर दे रहे हैं। अगर इस बजट में आप देखेंगे तो क्वालिटी के ऊपर, चाहे वह एजुकेशन की क्वालिटी हो, चाहे हेल्थ की क्वालिटी हो, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एक विजनरी बजट है, एक आम आदमी के लायक और हिन्दुस्तान के जो हालात हैं, उनको देखते हुए है। दूसरी बात, मैं कहना चाहती हूं कि बहुत दिनों के बाद पार्लियामेंट में हमें इस बार ज्यादा सीटें मिली हैं और मैं समझती हूं कि उसका मेन कारण यह है कि हमारे रहनुमाओं के ऊपर अवाम का एतबार, हमारे रहनुमाओं के वायदों के ऊपार आवाम का एतबार और हमारे रहनुमाओं की नीयत पर पूरा भरोसा, क्योंकि जितने काम पहले यू.पी.ए. गवर्नमेंट में हुए, उसमें सब ने यह दिखाया कि जो हम करते हैं उसको करने में ईमानदारी से कोशिश करते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूं किः

"वही कौमें ही पाती हैं बुलन्दी आसमानों की,

कि जिनके रहनुमा खुद साहबे किरदार होते हैं।"

तो मैं समझती हूं कि आज जो हमारे रहनुमा हैं, हमारे डा. मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी इनके ऊपर यह शेर सादिक आता है कि उनकी जो सदाकत है, उनकी जो नीयत है काम करने की, उसमे अवाम को फिर से यह भरोसा दिलवाया और अवाम ने उन्हें सबसे ज्यादा सीटें देकर पार्लियामेंट में भेजा।

महोदय, एग्रीकल्चर की बात मैं पहले कहना चाहूंगी कि हमारा एग्रीकल्चर एक रीढ़ की हड्डी है और एग्रीकल्चर में जितना ध्यान सरकार दे रही है, बड़ी खुशी की बात है कि सरकार का किसानों की तरफ जबर्दस्त ध्यान है। लेकिन मैं समझती हूं कि आज एग्रीकल्चर, बावजूद इसके कि इंडिया की 57 परसेंट पॉपुलेशन कामकाज में लगी हुई है, तकरीबन बाइ एंड लार्ज 57 परसेंट जो गांवों में काश्तकारी के जरिए काम करती है। लेकिन जी.डी.पी. में जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का हिस्सा है, वह कुल 27 परसेंट है और यह मैं समझती हूं कि यह बढ़ना चाहिए। वैसे आप और देखिए, पूरी दुनिया में जितनी सब्जियां पैदा होती हैं उसका 15 फीसदी हमारा मुल्क पैदा करता है, जितने फल पैदा होते हैं उसका 8 परसेंट हमारा मुल्क पैदा करता है, दूध के मामले में हमारा 17 लाख मैट्रिक टन हुआ करता था, जो आज लगभग 104 से ज्यादा है। तो ये चीजें दिखाती हैं कि हम इतना करते हैं। लेकिन बावजूद इसके कि इतना सब पैदा करने के बाद लगभग 40 परसेंट वेस्टेज है जिसकी वजह से पूरा फायदा इन लोगों को तथा किसानों को मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता। मैं समझती हूं कि यहां पर आकर स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इम्प्लीमेंट अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। आज हमें एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि यह जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात आ रही है उसमें सबसे बड़ा असर हमारे एग्रीकल्चर का पड़ने वाला है, क्योंकि जो खबरें आ रही है, जो बयानात आ रहे हैं, तो मैं समझती हूं कि इसकी तरफ सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले बजट में भी क्लाइमेंट चेंज के लिए कोई फंड नहीं थे और इस बजट में भी कहा गया है कि प्रोविजन किया जाएगा, लेकिन कोई खास फंड का एलोकेशन नहीं हुआ है। मैं समझती हूं कि यह बहुत बड़ा चेलेंज हिन्दुस्तान के सामने है। जब तक हम एग्रीकल्चर को मजबूत नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर के मामले में हम खुदकफ़ील बहुत दिन पहले हो चुके हैं, यह खुशी की बात है और यह भी उन पौलिसीज़ के जरिए जो हमारे उन रहनुमाओं ने बनाई थी, तो मैं समझती हूं कि आज क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा चेलेंज हमारे पास है, जिसकी तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा किसानों से ही जुड़े हुए कोआपरेटिव बैंक की बात है। उपसभाध्यक्ष जी, आप इतना वक्त मुझे देंगे नहीं, इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि कोआपरेटिव बैंक आज नोडल बैंक बनने वाले हैं, जो किसानों को कर्जा देंगे, उनकी हालत बहुत खराब है और हर स्टेट में वह एक तरह से पोलिटिकल अड्डे बन गए हैं जो भी पोलिटिकल पार्टी है वह कोआपरेटिव के जरिए अपनी सियासत चलाना चाहती है। तो सियासत के शिकंजे से कोआपरेटिव बैंकों को निकालना चाहिए तथा जैसे और अन्य बैंक काम करते हैं, उस तरह से उसके पूरे ढांचे को बदलने की बात करनी चाहिए। जितना भी आप उसमें कर सकते हैं करना चाहिए। दूसरी बात, मैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए कहना चाहती

हूं। सरकार ने बहुत दिनों के बाद प्राइमरी एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया है, पिछले बजट के मुकाबले। बजट का 6 परसेंट प्राइमरी एजुकेशन पर खर्च हुआ। आज एक अच्छा इंसान बनाने के लिए primary education बेहद जरूरी है। जैसा अभी स्वामीनाथन जी कह रहे थे कि 3 साल का बच्चा malnutrition का शिकार है, तो बच्चे का जो character building है, वह किसी कालेज में नहीं बनता, यूनिवर्सिटी में नहीं बनता। बच्चे का जो character बनता है, वह primary education से ही बनना शुरू होता है। अगर हम primary education को मजबूती के साथ अच्छा चलाएं, तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपको क्या बताऊं, मेरी तो इसमें ज़िन्दगी गुजर गई। पहले आप जाएंगे, तो पाएंगे कि दर्ज़ा चार टीचर वहां बैठी हुई हैं। बच्चों को उसने समेट लिया, क्लास में आई, चली गई। आज मैं समझती हूं कि primary education के लिए सबसे जरूरी है कि trained teachers रखे जाएं। ऐसे teachers prefer कीजिए, जो child psychology जानते हों। एक ऐसा environment हो, माहौल हो कि बच्चे का पढ़ने में दिल लगे, क्योंकि गरीबों के बच्चे primary schools में आते हैं। बड़े लोगों के बच्चे primary schools में नहीं आते। इसलिए मैं समझती हूं कि इन चीज़ों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

तीसरी बात मैं weavers के बारे में कहना चाहती हूं। Agriculture के बाद अगर कोई सबसे बड़ा पेशा है, तो वह handloom का है। आज weavers की हालत बहुत खराब है। उनको वैसा ही पैकेज देना चाहिए, जैसा आपने किसानों के लिए दिया है।

वाइस-चेयरमैन साहब, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूं कि मेरे साथ यह ज्यादती है कि आप मुझे 10 मिनट भी नहीं दे रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) : कांग्रेस का जो टाइम बचा हुआ है, उसी में से टाइम दिया गया है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : फिर भी मैं आपसे चाहूंगी कि आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगी, क्योंकि मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं कह सकती हूं।

श्री एस. एस. अहलुवालिया (झारखंड) : मोहसिना जी, एक मिनट। सर, हमारे बिल्डिंग की 5 नंबर लिफ्ट, जो राज्य सभा की लिफ्ट है, आधे घंटे से फंसी हुई है। उसमें हमारे कुछ कर्मचारी और एमपी भी बन्द होंगे। वह अभी तक नहीं चल रही है। राज्य सभा की 5 नंबर की जो लिफ्ट आती है, जिससे हमारे रिपोर्टर्स आते हैं, वे फंसे हुए हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वे अभी भी फंसे हुए हैं। आधा घंटा से ज्यादा हो गया। अभी तक कुछ व्यवस्था नहीं की गई है। अगर कोई वहां suffocation से मर गया, किसी का heart attack हो गया, उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। आप उसको दिखवाने की कृपा करें। आप सेक्रेटरी जनरल को आदेश दें कि इसके लिए तुरंत व्यवस्था करें।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) : जी, जरूर। अहलुवालिया जी ने जो बताया है, उसे देखा जाए।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मेरा ख्याल है कि अहलुवालिया जी ने जो कहा है, हमें उसकी नोटिस लेनी चाहिए और किसी को भेज कर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) : अहलुवालिया जी ने जो बताया है, किसी को भेज कर उसे देखा जाए और देख कर बताया जाए।

श्रीमती मोहसिना किदवई : सर, मैं आपसे कह रही थी कि infrastructure पर बहुत जोर दिया गया। मजबूत infrastructure न होने की वजह से हमारा wastage भी बहुत है और बहुत सख्त नुकसान होता है। इसको इतनी importance दी गई है, उसका सबूत यह है कि प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, जो यह देखेगी कि हर तरह के infrastructure को कैसे मजबूत किया जाए।

एक अन्य बात मैं कहना चाहती हूं कि minorities के लिए फाइनांस मिनिस्टर साहब ने 74% बढ़ाया है। उसमें उनकी तालीम, उनके वजीफे और उनकी म्यारे ज़िन्दगी को उठाने के लिए उन्होंने जो काम किया है, मैं समझती हूं कि वह सराहनीय है।

इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहती हूं कि आज जरूरत है तालीम को रोजी-रोटी के साथ जोड़ा जाए। आज इस बात की जरूरत है। यह तो स्कूल में पता चल जाता है कि किस बच्चे का क्या caliber है, उसका रूझान क्या है, वह किस तरफ जाना चाहता है। मैं समझती हूं कि इसके लिए एक सिस्टम evolve करना चाहिए कि बच्चों को vocational training की तरफ, उस तालीम की तरफ ज्यादा रूजू करें, ताकि वे vocational training लेकर, उसकी तालीम लेकर अपनी रोजी-रोटी का इंतजाम कर सकें।

मैं छत्तीसगढ़ के बारे में एक बात कहना चाहती हूं। यह बड़ा पिछड़ा इलाका है। वहां रोज नक्सली हमले होते हैं। अभी आपने देखा कि वहां कितने लोग मर गए और कितने पुलिसवालों की जान गई। मैं होम मिनिस्टर साहब को एक सुझाव देना चाहती हूं कि जितने naxal infested areas हैं, जैसे महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार हैं, इन सारी स्टेट्स की एक मीटिंग बुला कर एक combined operation होना चाहिए, ताकि ये जो रोज़ मजलूम लोग मरते हैं, उनको इससे छुट्टी मिले। छत्तीसगढ़ में न सड़के हैं, न बिजली है, न स्कूल्स हैं, न हॉस्टिपटल हैं। मैं समझती हूं कि छत्तीसगढ़ को इसके लिए कोई पैकेज देना चाहिए।

सर, मैं अपने एमपी साहिबान को एक आखिरी सुझाव देना चाहती हूं कि हमारा जो MPLAD फंड है, आज हमारी कितनी बहनें कैंसर की मरीज़ हैं...। अगर हमारे एमपी फंड से हम हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक-एक मैमोग्राफी की मशीन दे दें तो मैं समझती हूं कि यह बहुत बड़ा काम होगा। उसकी कीमत बीस लाख रुपये होती है। हमारी भी यह जिम्मेदारी है कि हम अपने फंड्स में से हैल्थ और एजुकेशन के लिए हिस्सा दें। वह भी सरकार का फंड है। हैल्थ और एजुकेशन, यही दो चीजें हैं जो इन्सान को चुस्त रख सकती हैं। मैं अब एक आखिरी बात कहती हूं, अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि यह सरकार पॉपुलेशन की तरफ ध्यान नहीं देती है। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने इससे नुक़सान उठाया है, क्योंकि हमारे दूसरी तरफ बैठने वाले भाइयों ने 1977 में इसे एक पॉलिटिकल टूल बना लिया था। मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करना चाहूंगी कि अपने मुल्क के लिए कुछ मसले ऐसे होते हैं, जिन पर above the party line सोचना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है कि हमारे सामने पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे उम्मीद है कि उसके लिए सरकार को कोई न कोई उपाय करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

محترمہ محسنہ قدوائی (چھتیس گڑھ) : آپ سبھا ادھیکش مہودے، آپ کا بہت بہت دھنیواد۔ فائنینس منسٹر صاحب نے جو بجٹ پیش کیا ہے، میں اس کی تائید کرنے کے لئے کھڑی ہوئی ہوں۔ جہاں ہندوستان کا تعلق ہے، مجھے یاد ہے کہ آج ہندوستان کا پہلا بجٹ غالبا 2000 کروڑ کا تھا۔ پھر تین ہزار کروڑ کا اگلا بجٹ ہوا اور بیسویں صدی تک اسی طرح سے بجٹ بڑھتے رہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ 21 ویں صدی میں جو پچھلا بجٹ تھا، وہ ایک لاکھہ کروڑ سے زیادہ کا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ہندوستان نے کتنی ترقی کی اور کس طرح سے وہ آگے بڑھا۔ ہمارے فائنینس منسٹر صاحب نے جو یہ بجٹ پیش کیا ہے، جس وقت یہ بجٹ پیش کیا جا رہا تھا، اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کے بہت سے ممالک ایک اکانومک کرائسز سے گزر رہے تھے اور لگتا تھا کہ دنیا کی جو اکانومی ہے، وہ چرمرا گئی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے فائنینس منسٹر صاحب کا اور ہماری یو۔پی۔اے۔ گوورنمنٹ کا بہت بڑا قدم ہے کہ ان حالات میں انہوں نے اس بجٹ میں حوصلے اور ہمت کے ساتھہ جی۔ڈی۔پی۔ کو 9 فیصد سے اوپر لے جانے کی بات کہی۔ ہم نے اس عرصے میں دیکھا کہ 7 فیصد، 6 فیصد ہوئی، وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے ملک نے اس کو سہا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سب سے بڑا ہاتھہ ایگریکلچر کا ہے۔ بائے اینڈ لارج ہماری اکانومی ایگریکلچر بیسڈ ہے اور ہماری 80 فیصد آبادی آبادی ہماری اس پیشے میں مصروف ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج جو ہم نے یہ بجٹ پیش کیا ہے، اس میں بہت بڑا بل ایگریکلچر پر دیا ہے اور ایگریکلچر کے نیچے جتنی چیزیں آتی ہیں، چاہے وہ horticulture ہو، چاہے poultry ہو یا cooperative banks ہوں، جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، ان کی طرف پوری توجہ دی گئی ہے۔ جو سب سے بڑی بات اس میں مجھے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بجٹ ایک عام آدمی کے حالات کو، معیار زندگی کو اوپر اٹھانے کا بجٹ ہے۔ میں بار

†[Transliteration in Urdu Script]

بار یہ کہتی ہوں کہ یہ ایک ایسا دور اندیش بجٹ ہے جو ہمارے رہنماؤں کی جو vision ہے، جس نے آزادی کے بعد کے ہندوستان کو اب کس طرح سے آگے بڑھایا ہے، جو infrastructure بنایا، اسی کے اوپر آج ہندوستان مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس بجٹ میں سب سے زیادہ دھیان دیا ہے، آزادی کے بعد ہم کوالٹی پر زور دیتے تھے کہ کتنے اسکول کھل جائیں، کتنے ہاسپٹل بن جائیں، کتنی سڑکیں بن جائیں، کتنے ٹیوب ویل لگیں، یہ ساری چیزیں ہم کرتے تھے۔ لیکن خوشی کی بات ہے کہ آج ہم کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی پر زور دے رہے ہیں۔ اگر اس بجٹ میں آپ دیکھیں گے تو کوالٹی کے اوپر چاہے وہ ایجوکیشن کی کوالٹی ہو، چاہے ہیلتھ کی کوالٹی ہو، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک وژنری بجٹ ہے، ایک عام آدمی کے لائق اور ہندوستان کے جو حالات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، میں کہنا چاہتی ہوں کہ بہت دنوں کے بعد پارلیمنٹ میں ہمیں اس بار زیادہ سیٹیں ملی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کا اہم کارن یہ ہے کہ ہمارے رہنماؤں کے اوپر عوام کا اعتبار، ہمارے رہنماؤں کے وعدوں کے اوپر عوام کا اعتبار اور ہمارے رہنماؤں کی نیت پر پورا بھروسہ، کیوں کہ جتنے کام پہلے یو پی۔اے۔ گوورنمنٹ میں ہوئے، اس میں سب نے یہ دکھایا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کرنے کی ایمانداری سے کوشش کرتے ہیں۔ اپ سبھا ادھیکش مہودے، میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ

وہی قومیں ہی پاتی ہیں بلندی آسمانوں کی
کہ جن کے رہنما خود صاحب کردار ہوتے ہیں

تو میں سمجھتی ہوں کہ آج جو ہمارے رہنما ہیں، سارے ڈاکٹر منموہن سنگھ جی اور سونیا جی ان کے اوپر یہ شعر صادق آتا ہے کہ ان کی جو صداقت ہے، ان کو جو نیت ہے کام کرنے کی، اس نے عوام کو پھر سے یہ بھروسہ دلوایا اور عوام نے انہیں سب سے زیادہ سیٹیں دے کر پارلیمنٹ میں بھیجا۔

مہودے، ایگریکلچر کی بات میں پہلے کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ایگریکلچر ایک ریڑھ کی ہڈی ہے اور ایگریکلچر میں جتنا دھیان سرکار دے رہی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ سرکار کا کسانوں کی طرف زبردست دھیان ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج ایگریکلچر باوجود اس کے کہ انڈیا کی 57 فیصد پاپولیشن کام کاج میں لگی ہوئی ہے، تقریبا بائی اینڈ لارج 57 فیصد جو گاؤں میں کاشت کاری کے ذریعے کام کرتی ہے۔ لیکن جی۔ڈی۔پی۔ نے جو ایگریکلچر منسٹری کا حصہ ہے، وہ کل 27 فیصد ہے اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑھنا چاہئے۔ ویسے آپ اور دیکھئے، پوری دنیا میں جتنی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں اس کا 15 فیصدی ہمارا ملک پیدا کرتا ہے، جتنا پھل پیدا ہوتے ہیں اس کا 8 فیصد ہمارا ملک پیدا کرتا ہے، دودھ کے معاملے میں ہمارا 17 لاکھ میٹرک ٹن ہوا کرتا تھا، جو آج لگ بھگ 104 سے زیادہ ہے، تو یہ چیزیں دکھاتی ہیں، کہ ہم اتنا کرتے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے کہ اتنا سب پیدا کرنے کے بعد لگ بھگ 40 فیصد ویسٹیج ہے جس کی وجہ سے پورا فائدہ ان لوگوں کو اور کسانوں کو ملنا چاہئے، وہ نہیں ملتا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر آکر اسٹیٹ گوورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے، کیوں کہ امپلی مینٹ اتھارٹی اسٹیٹ گوورنمنٹ کے پاس ہے۔ آج ہمیں ایگریکلچر کو پرائرٹی دینا چاہئے، کیوں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کی بات آ رہی ہے اس میں سب سے بڑا اثر ہمارے ایگریکلچر پر پڑنے والا ہے، کیوں کہ جو خبریں آ رہی ہیں، جو بیانات آ رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی طرف سرکار کو بہت زیادہ دھیان دینا چاہئے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے بجٹ میں بھی کلائمیٹ چینج کے لئے کوئی فنڈ نہیں تھے اور اس بجٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ پرووژن کیا جائے گا، لیکن کوئی خاص فنڈ کا ایلوکیشن نہیں ہوا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہندوستان کے سامنے ہے۔ جب تک ہم ایگریکلچر کو مضبوط نہیں کریں گے، ایگریکلچر کے معاملے میں ہم خود کفیل بہت پہلے ہو چکے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے اور یہ بھی ان پالیسیز کے ذریعے جو

ہمارے ان رہنماؤں نے بنائی تھی، تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کلائمیٹ چینج کا اتنا بڑا چیلنج ہمارے پاس ہے، جس کی طرف ہمیں زیادہ دھیان دینا چاہئے۔

اس کے علاوہ کسانوں سے ہی جڑے ہوئے کوآپریٹو بینک کی بات ہے۔ اپ سبھا ادھیکش جی، آپ اتنا وقت مجھے دیں گے نہیں، اس لئے میں کہنا چاہتی ہوں کہ کوآپریٹو بینک آج نان بینک بننے والے ہیں، جو کسانوں کو قرضہ دیں گے، ان کی حالت بہت خراب ہے اور اسٹیٹ میں وہ ایک طرح سے پولیٹکل اڈے بن گئے ہیں اور جو بھی پولیٹکل پارٹی ہے وہ کوآپریٹو کے ذریعے اپنی سیاست چلانا چاہتی ہے۔ تو سیاست کے شکنجے سے کوآپریٹو بینکوں کو نکالنا چاہئے اور جیسے دوسرے بینک کام کرتے ہیں، اس طرح سے اس کے پورے ڈھانچے کو بدلنے کی بات کرنی چاہئے۔ جتنا بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں، کرنا چاہئے۔

دوسری بات، میں پرائمری ایجوکیشن کے لئے کہنا چاہتی ہوں۔ سرکار نے بہت دنوں کے بعد پرائمری ایجوکیشن کی طرف دھیان دیا ہے، پچھلے بجٹ کے مقابلے بجٹ کا 6 فیصد پرائمری ایجوکیشن پر خرچ ہوا۔ آج ایک اچھا انسان بنانے کے لئے پرائمری ایجوکیشن بیحد ضروری ہے۔ جیسا ابھی سوامی ناتھن جی کہہ رہے تھے کہ 3 سال کا بچہ malnutrition کا شکار ہے، تو بچے کا جو character building ہے، وہ کسی کالج میں نہیں بنتا، یونیورسٹی میں نہیں بنتا۔ بچے کا جو کریکٹر بنتا ہے، وہ پرائمری ایجوکیشن سے ہی بننا شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم پرائمری ایجوکیشن کو مضبوطی کے ساتھ اچھا چلائیں، تو بہت اچھا ہوگا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میری تو اس میں زندگی گزر گئی۔ پہلے آپ جائیں گے، تو پائیں گے کہ درجہ چارٹیچر وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ بچوں کو اس نے سمیٹ لیا، کلاس میں آئی، چلی گئی۔ آج میں سمجھتی ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن کے لئے سب سے ضروری ہے کہ ٹرینڈ ٹیچرس رکھے جائیں۔ ایسے ٹیچر prefer کیجئے، جو چائلڈ سائیکلوجی جانتے ہوں۔ وہ ایسا environment ہو، ماحول ہو کہ بچے کا پڑھنے میں دل لگے، کیوں کہ

غریبوں کو بچے پرائمری اسکولس میں آتے ہیں۔ بڑے لوگوں کے بچے پرائمری اسکول میں نہیں آتے۔ اس لئے میں سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کی طرف سرکار کو دھیان دینا چاہئے۔

تیسری بات میں weaver کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں۔ ایگریکلچر کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا پیشہ ہے، تو وہ ہینڈ لوم کا ہے۔ آج weaver کی حالت بہت خراب ہے۔ ان کو ویسا ہی پیکج دینا چاہئے، جیسا آپ نے کسانوں کے لئے دیا ہے۔

وانس چیئرمین صاحب، میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ آپ مجھے 10 منٹ بھی نہیں دے رہے ہیں۔

اپ سبھا ادھیکش (شری طارق انور): کانگریس کا جو ٹائم بچا ہوا ہے، اسی میں جو ٹائم دیا گیا ہے۔

محترمہ محسنہ قدوائی: پھر بھی میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ مجھے 5 منٹ دے دیجئے، میں اپنی بات ختم کر دوں گی، کیوں کہ میں اس پر بہت زیادہ نہیں کہہ سکتی ہوں۔

شری ایس۔ایس۔ اہلووالیہ: محسنہ جی، ایک منٹ۔ سر، ہمارے بلڈنگ کی نمبر-5 لفٹ، جو راجیہ سبھا کی لفٹ ہے، آدھے گھنٹے سے پھنسی ہوئی ہے۔ اس میں ہمارے کچھ کرمچاری اور ایم۔پی۔ بھی بند ہوں گے۔ وہ ابھی تک نہیں چل رہی ہے۔ راجیہ سبھا کی نمبر -5 کی جو لفٹ آتی ہے، جس سے ہمارے رپورٹرس آتے ہیں، وہ پھنسے ہوئے ہیں اور ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے۔ وہ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ ابھی تک کچھ ویوستھا نہیں کی گئی ہے۔ اگر کوئی وہاں suffocation سے مر گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کے لئے بھی کوئی ویوستھا نہیں ہے۔ آپ اس کو دکھوانے کی کرپیہ کریں۔ آپ سکریٹری جنرل کو آدیش دیں کہ اس کے لئے فورا ویوستھا کریں۔

اپ سبھا ادھیکش: جی ضرور، اہلووالیہ جی نے جو بتایا ہے، اسے دیکھا جائے۔

محترمہ محسنہ قدوائی: میرا خیال ہے کہ اہلووالیہ جی نے جو کہا ہے، ہمیں اس کا نوٹس لینا چاہئے اور کسی کو بھیج کر دیکھنا چاہئے کہ کہا ہو رہا ہے۔

اپ سبھا ادھیکش: اہلووالیہ جی نے بتایا ہے، کسی کو بھیج کر اسے دیکھا جائے اور دیکھہ کر بتایا جائے۔

محترمہ محسنہ قدوائی: سر، میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ infrastructure پر بہت زور دیا گیا۔ مضبوط infrastructure نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ویسٹیج بھی بہت ہے اور بہت سخت نقصان ہوتا ہے۔ اس کو اتنی امپورٹینس دی گئی ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی ادھیکشتہ میں ایک کمیٹی بنی ہے، جو یہ دیکھے گی کہ ہر طرح کے infrastructure کو کیسے مضبوط کیا جائے۔

ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ مائنارٹیز کے لئے فائنینس منسٹر صاحب نے 74٪ بڑھایا ہے۔ اس میں ان کی تعلیم، ان کے وظیفے اور ان کی معیار زندگی کو اٹھانے کو لئے انہوں نے جو کام کیا ہے، سمجھتی ہوں کہ وہ سراہنئے ہے۔

اس کے علاوہ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آج ضرورت ہے کہ تعلیم کو روزی روٹی کے ساتھہ جوڑا جائے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے۔ یہ تو اسکول میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس بچے کا کیا کیلبر ہے، اس کا رجھان کیا ہے، وہ کس طرف جانا چاہتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لئے ایک سسٹم evolve کرنا چاہئے کہ بچوں کو vocational training کی طرف، اس تعلیم کی طرف زیادہ رجوع کریں، تاکہ وہ vocational training لیکر، اس کی تعلیم لیکر روزی روٹی کا انتظام کر سکیں۔

میں چھتیس گڑھ کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ یہ بڑا پچھڑا علاقہ ہے۔ وہاں روز نکسلی حملے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ وہاں کتنے لوگ مر

گئے اور کتنے پولیس والوں کی جان گئی۔ میں ہوم منسٹر صاحب کو ایک سجھاؤ دینا چاہتی ہوں کہ جتنے naxal infested areas ہیں، جیسے مہاراشٹر، آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار ہیں، ان ساری اسٹیٹس کی ایک میٹنگ بلا کر ایک combined operation ہونا چاہئے، تاکہ یہ جوروز مظلوم لوگ مرتے ہیں، ان کو اس سے چھٹی ملے۔ چھتیس گڑھ میں نہ سڑکیں ہیں، نہ بجلی ہے، نہ اسکولس ہیں، نہ ہاسپٹلس ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ چھتیس گڑھ کو اس کے لئے کوئی پیکج دینا چاہئے۔

سر، میں اپنے ایم پی۔ صاحبان کو ایک آخری سجھاؤ دینا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو MPLAD فنڈ ہے، آج ہماری کتنی بہنیں کینسر کی مریض ہیں۔ اگر ہمارے ایم پی۔ فنڈ سے ہم ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ایک ایک میسو گرافی کی مشین دے دیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ اس کی قیمت بیس لاکھ روپے ہوتی ہے۔ ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے فنڈس میں سے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لئے حصہ دیں۔ وہ بھی سرکار کا فنڈ ہے۔ ہیلتھ اور ایجوکیشن، یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو چست رکھ سکتی ہیں۔ میں اب ایک آخری بات کہتی ہوں، ابھی ہمارے بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سرکار پاپولیشن کی طرف دھیان نہیں دیتی ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ سب سے زیادہ کانگریس پارٹی کی سرکاروں نے اس سے نقصان اٹھایا ہے، کیوں کہ ہماری دوسری طرف بیٹھنے والے بھائیوں نے 1977 میں اسے ایک پالیٹکل ٹول بنا لیا تھا۔ میں آپ سب سے یہی درخواست کرنا چاہوں گی کہ اپنے ملک کے لئے کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن پر above the party line سوچنا چاہئے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے سامنے پاپولیشن گروتھ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کے لئے سرکار کو کوئی نہ کوئی اپائے کرنا چاہئے۔ بہت بہت دھنیواد۔

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I congratulate our Finance Minister for having presented a historic and unprecedented Budget. In the very constrained circumstances, he has given more than Rs.10,00,000 crores. We must bear in mind that we are passing through the global recession. Still, fortunately, India is not so much affected by it. The hon. Finance Minister has taken all pains to make more allocations for both the economic growth and the social sector. The social sector is very important. Some hon. Members, while speaking on the Budget, criticised the Government for allocating so much money for the social sector. They criticised the Government for taking up so many development activities. They criticised the Government for having Budget deficits, etc. On the other hand, some hon. Members said that industrial growth is very important for our country. They emphasised on the economic growth also. So, this contradiction is going on. One thing is very important for us. Whatever happens, the most important thing for the hon. Finance Minister, the hon. Prime Minister and the hon. Chairperson of the UPA is to eradicate poverty and see that employment potentiality is increased and overall development of the country takes place. Since the time at my disposal is very short, I would not repeat what has already been said by the earlier speakers. The Finance Minister has given Rs.39,000 crores for the NREG Scheme, which is an increase of 144 per cent. For the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, there is an increase of 59 per cent; for the Rajiv Gandhi Gram Vidyutikaran Yojana, there is an increase of 27 per cent. Then, for farmers credit, the Finance Minister has increased the allocations to Rs.3,25,000 crores from Rs.2,87,000 crores of the last year. Food security is very important. For the first time in the history of Independent India, our Government has come forward to give a poor man foodgrains at Rs.3 per kilogram. It is a big challenge for this Government. It is a very courageous decision of the Government. Giving 30 kilogram of wheat and rice at Rs.3 per kilogram every month is a great achievement of this Government. This Food Security Scheme was also criticised by the Opposition leaders yesterday. They asked the Government as to why the Food Security Scheme is there. I don't understand it. Similarly, on the one side, they say that industrial growth is required. On the other side, they say that the Government should not levy more taxes. At the same time, they say that the Government should give more tax exemptions. Shri Venkaiah Naidu said that the Government should raise the Income-tax exemption limit to Rs.3 lakh. I would like to clarify to him that it is totally wrong. Three lakh Income-tax exemption means, an income of Rs.25,000 per month. In India, a man who earns Rs.25,000 per month is not a poor man. He is an above middle-class man. So, for an above middle-class man, how can the Finance Minister give tax exemption of Rs.3 lakh? The Government is more bothered about the poor people. Therefore, proposing an Income-tax exemption of Rs.3 lakh, that too by the Opposition Members is not at all acceptable. I must say it is not correct. So, what the hon. Finance Minister proposed, *i.e.*, Rs.1.60 lakh is absolutely right.

Similarly, Sir, in this Budget, a GDP growth rate of 9 per cent is expected. This is what the hon. Finance Minister expects to achieve through this Budget, We must bear in mind that in its earlier term the UPA Government achieved a growth rate of 9 per cent. Afterwards, because of global recession, it has come down to 6.5 per cent. On this point also, the Opposition Members are criticising the Government and saying that it should be kept at 6.5 per cent. I must say that we have achieved four per cent increase in agricultural production whereas the NDA Government had achieved only 2.5 per cent increase. Therefore, here also it is the achievement of the UPA Government, In the present Budget, our Government is planning to maintain at least 4 per cent increase. I need not repeat, already there are credit facilities for farmers and there are so many other facilities for agricultural production. So many facilities have been given.

I would like to say about reforms. Regarding reforms, it has become a fashion for a lot of people – intellectuals, distinguished persons. They say that reform is not pursued. Let me clarify to the House that reform is of two types. One type of reform is, licence-raj has been removed; when our present Prime Minister was the Finance Minister, it was started, Free cash flow, investment has been allowed from the world towards India. Also, import of various things are required. This is one type of reform. The other kind of reform is, subsidy is given on fertilizers. People say, 'Remove the subsidy, we want reform.' That is not the reform. If you remove the subsidy, immediately you only would attack, 'Oh! Subsidy has been removed. What about the poor agriculturists and farmers?' Though the Government is planning to remove subsidy, in fact, several times, even the Finance Minister has been planning to do it; why could they not do? There would be uproar, again. Therefore, such type of reforms could not be done. I cannot understand why others say that reforms are not pursued. They say, 'Reforms are not pursued, therefore the Budget is not good!' Somebody says, 'Industrial production is not good, industrial growth is not good, therefore, the Budget is not good.' Another Member from the Opposition would say, 'Now, the Sensex has gone down.' Yesterday, the Sensex has gone up! It is going up again now. Industry has been encouraged, surcharge has been abolished, the fringe benefit tax too has been removed, on export too so many facilities are given. Therefore, with these measures we are bound to have the industrial growth. The Finance Minister is planning Budget deficit of 5.5 per cent only in the next year, 2010. In 2011, he is aiming at 4 per cent. It is possible. Yesterday also he clarified it in the Lok Sabha that he can do the financial discipline. With the financial discipline, he said that he can plan for more industrial growth and more economic growth.

I must say that this Budget has taken into account the social sector, has taken into account the overall development, has taken into account every sector. Now, the Opposition makes a big uproar, 'Debt is being taken, there is deficit finance!' What is deficit finance? Last year, they had taken Rs. 2,85,000 crores. The Government is borrowing.

You see, any business house, or anybody, can borrow money and indulge in development. Here, also, the Government is helping various sectors and, if necessary, it is borrowing the money. Year by year, they are going to reduce this borrowing. A day will come, perhaps, after four-five years, the deficit finance will disappear by witnessing more economic growth and industrial growth.

I would like to say on one more thing. Mr. Palanimanickam, the Minister of State, must note down, tourism is also very important for revenue generation. In the world, India is one of the biggest tourism attraction. Therefore, you need hotel industry too to be very much encouraged. But, unfortunately, for the last 6-7 years, the hotel industry is tagged down with the real estate. The real estate is totally full of fluctuation, risky gambling. It is highly unpredictable. Tourism industry cannot be linked with that. It must be seen that this too becomes one of the robust industry not linked with the real estate.

I would like to speak on one more thing. Nobody raised this point till now. Rs.1,45,000 crores of cash has been flown into the market in the last 5-6 months by the Reserve Bank of India by pursuing various methods and encouraging the banks. What for? Because, 2008, the inflation went up to 13 per cent. When they wanted to cut credit, they said that 13 per cent rate of inflation is very dangerous, so you increase the interest rate abnormally. This 'abnormal' rate went up to 15, 16 per cent. With the result, the industry also has been very much constrained and the growth has been hampered. At that stage, now - the inflation as on March, 2009 has come down to zero. Inflation has come down to zero. Still, the banks are enjoying the interest rates! This is in spite of the Finance Minister's conference with all banks. He said, 'Come on, reduce!' They do not reduce and are enjoying the fruits! There must be categorical instructions to see to it that to the extent they have increased, to 13 per cent, they must come down, back to the lower rates.

It is unfair to have the interest rate more and discourage the industrial growth. Today the industrial growth is being affected because of constraints in the credit system, because of the high interest rate. I do not understand that in spite of Rs.1,45,000 crores cash flow into the market and inflation coming down to below zero, why we should have the same interest rate. Then I come to Arogyasri. Mr. Venkaiah Naidu though he was adversely criticising the Budget but in his heart of hearts he knows that the Budget is very good. He must criticise it because he is in the opposition side. Arogyasri is a scheme, which is very popular in Andhra Pradesh. Those poor who cannot get themselves operated upon in hospital, the cost towards this is being borne by the Andhra Government. That system should be spread all over India, not immediately but at the time of the next Budget. The Finance Ministry must bear in mind this point. So, when the leader of the principal opposition party says this, then the entire House must agree that it is a very good scheme. Arogyasri scheme of Andhra Pradesh has become now a national subject, which is very good, Sir. Lastly,

yesterday Mr. Naidu was telling ...*(Interruptions)*... Mr. Naidu was telling that inflation was 4.5 per cent when the NDA was in power but the inflation is very high during the time of our Government. Let me clarify, Mr. Naidu, we are at below zero level inflation. Of course, he was comparing the prices of some of the commodities; Wholesale Price Index is the reflection of inflation. Consumer Index temporarily moves and it is temporarily going like this. ...(**Time-bell**).. So, in conclusion, I once again congratulate the hon. Minister and I request the Minister of State for Finance that without forgetting my two points, he must inform the Finance Minister about tourism and bank interest rate. Thank you all.

SHRIMATI VASANTHI STANLEY (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you very much for this opportunity. I recall of already having spoken on the Interim Budget. I would like to thank our leader and also our DMK Party leader for giving me at this juncture this golden opportunity to be here and express my views on the Budget. I feel like a kitten, Sir, trying to lick away the whole sea of milk. I pray that you do not compare me with my size, it is only a comparison because it is an ocean of welfare scheme by the Minister, I do not know where to start, what to include and what not. I would like to thank the people of Tamil Nadu at this juncture for their clear verdict. Much against the predictions of the media and Press, I attribute this to the verdict of our people of Tamil Nadu, especially to the UPA, alliance under the leadership of our Chief Minister Dr. Kailgnar Karunanidhi. This mandate is a clear mandate showing that the people have acknowledged all the efforts of the State Government and the UPA Government and people's faith in the schemes of the Government. So, I would like to thank the people of Tamil Nadu and also the people of India who have elected this UPA Government once again to rule. I would like to congratulate the Prime Minister, Dr. Manmohan Singhji, and also the Chairperson of UPA, Madam Sonia Gandhiji for their leadership for brining back the UPA to power.

The whole world was trailing back due to financial crisis in 2007 but India was able to show a healthy 7.1% GDP growth last year. But this year India is also under the clutches of economic slowdown and financial crisis. This is the time when our Budget is being prepared by our Finance Minister to meet the challenges both, economically and socially and also has kept in view the global demand. First, I would like to congratulate the Minister for admitting or stating that the economic recovery and growth is a cooperative effort of the Central and State Governments. For the first time in the history he has called upon all the Finance Ministers of the States to offer their remarks before preparing the Budget. I hope that this healthy trend will continue. I would like to recall at this juncture, Sir, that this is also the practice of our Chief Minister calling the representatives of farmers, Government employees, etc. before preparing the Budget. I hope and wish that this healthy trend would continue so that more contribution to the State is afforded in the future to come.

Our great poet, Thiru Valluvar says, which means that the farmers are the key persons of any nation. Agriculture credit has been increased, the credit flow has been increased to Rs.3,25,000

crores and also debt relief scheme has been extended up to 31.12.2009. One per cent tax reduction is also announced which is a welcome relief to the farmers. This holistic approach has resulted in food security for the country. But here also I cannot help myself comparing with our State of Tamil Nadu where the Government has announced in this year's Budget that no interest will be charged on the cooperative loans of the farmers if they pay their loans properly. So, I would like the Union Government to extend this scheme to all the farmers of giving free power, that is, free electricity to all the farmers that is being distributed by our Government. I hope this scheme will be extended to all the farmers of our country. For the AIBP, that is, accelerated irrigation benefit programme, there is an additional allotment of Rs.1000 crores for this purpose. Our neighbour States like Andhra Pradesh and others are enjoying fruits of this programme but we have been waiting for a very long time. Three projects are already lying before the Government. I call upon the Government to make provision for us also under the accelerated irrigation benefit programme, Sir. I would also like to reiterate my earlier request made in the interim Budget to keep minimum support price for paddy and it should be kept on par with wheat. Now coming to taxes, it is a welcome measure. That the Minister has raised the personal tax exemption limit marginally by Rs.10,000 and Rs. 15,000 for senior citizens and also abolishing ten per cent surcharge on higher income, also scrapping the fringe benefit tax and also keeping the corporate tax untouched. I think the minimum alternate profit of companies from 10 per cent to 15 per cent is also appreciable to make up the revenue shortfall. I appreciate the Finance Minister for announcing short term and medium term measures to save the economy and at the same time bring the fiscal deficit in tune with the FIRBM Act at the earliest. Again I would like to quote from our famous Tamil Nadu poet Thiru Valuvar that the friendship is not only for enjoyment and laughing. When something wrong happens, you have to mention about it, you have to reproach it and you have to see that it is being corrected. So, as an alliance party, we would also like to point out certain shortcomings in this Budget. For example, the Government seems to be counting on assumptions to just keep the fiscal deficit at 6.8 per cent of the GDP. The deficit is expected to be bridged by collection of increased direct taxes and so on. Without mentioning any specific target for public sector disinvestment, the Finance Minister has estimated to mop up Rs. 1120 crores during the fiscal year. I am afraid, Sir, if any of the assumption does not work out, the fiscal situation wilt get more precarious. I wish the Minister had more plans in the years to come to bridge this gap more effectively and substantially. In the development process, *aam aadmi* continues to be the basic slogan of ail the welfare schemes of the Government. It is commendable that about 4.47 crores households are benefited under the NREG Scheme. ...(**Time-bell**)... Sir, give me two more minutes. A budget provision of Rs.39,100 crore has been made for raising the wages from Rs.80 to Rs.100. This reminds me of our party founder leader Anna's slogan that is, let us see the God in the laughter of the

poor people. I would like to comment upon the National Security Act and on more provisions which have been made under Bharat Nirman and Indira Awas Yojana, etc. But for the Scheduled Castes, just Rs.100 crores have been allotted.

I hope more allocation would be made in future. Now, I would request the hon. Minister for Budgetary provision for Intra-State River Linking Projects. Already, the Thambra Bharani Project, worth Rs. 400 crores, is lying before the Government. Sir, more Budgetary allocation needs to be made to Sethusamudram and Desalination Projects in Chennai.

Sir, last but not the least, I wish to say about the rehabilitation of Ceylon Tamils. I would like to recall an incident from Mahabharata. Lord Krishna went as an ambassador to Duryodhana and asked for giving Pandavas their rights and land. Duryodhana says that even a pinpoint of land will not be given. But, ultimately, only Pandavas will win. In the same way, Mr. Rajapaksa is denying Tamils of their rights. He says that their rights will not be given back. Now, in the name of rehabilitation, nothing is being done. With all the efforts of the hon. Chief Minister and the hon. Member Smt. Kanimozhi, the relief vessel, Vananha Man, is able to reach only now. Though Rs. 500 crores of relief has been allocated to them, it has to reach them. For this, I request that concrete and continuous measures should be taken by the Government.

Last point is this. I would like, as former Member of the Minority Commission and also as former Member of the National Commission for Minority Educational Institutions, to commend the hon. Minister for allotting Rs. 1704 crores for minority welfare. Sir, allocation for Maulana Azad Education Foundation has also been doubled. I wish, on behalf of all the minorities, the poor of Tamil Nadu and the country, the hon. Finance Minister with an Urdu couplet -

तुम सलामत रहो कयामत तक

और कयामत न हो कयामत तक।

Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Shri Abony Roy. Not present. Mr. Naresh Gujral.

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Mr. Vice-Chairman, Sir, Shri Pranab Mukherjee, who is known for his prudence and sagacity, unfortunately, is steering the economy down on an extremely risky path through his populist measures which will increase the fiscal deficit to alarming levels.

The total income of the Central Government, according to the Budget Estimates, will be Rs. 6,19,842 crores, but the interest payable alone would be Rs. 2,25,500 crores which is 37 per cent of its revenue. This figure would certainly cross the 40 per cent mark once the Revised Estimates are released in a few months.

Sir, such huge market borrowings of over Rs. 4.20 lakh crores by the Central Government and increased borrowings by State Governments and the public sector companies will squeeze out the

borrowing programme of the private sector. This, obviously, would mean that interest rates would be under pressure and if interest rates remain at this level, then, I am sorry to say, my friend Mr. Rahul Bajaj will not be able to sell his motorcycles, farmers will not be able to buy tractors and demand for consumer goods would remain sluggish. As it is, housing loans are coming at 12-13 per cent interest, thereby, making it difficult for the poor and middle-class to buy cheap homes.

Sir, I understand the Finance Minister's predicament. He wishes to kick start the economy. He wants to give an impetus to industry by creating demand. However, throwing good money in populist schemes, which does not even reach the ultimate beneficiaries, will not solve the problem till we fix the delivery mechanism. Instead, in the short run, we need to, somehow, reduce interest rates so that there is demand for goods and industry finds it viable to make fresh investment in plant and machinery.

Sir, the Government is predicting 7 per cent growth rate in the current financial year. However, our industrial growth is stagnant, the monsoon is disappointing which would mean a decline in our agricultural production and our exports are showing a 30 per cent decline month-after-month. So, what is the basis of this optimism? According to the latest issue of the *Economist*, India's deficit could reach 12 per cent of the GDP in this year which is double of what the Finance Minister is predicted.

The hon. Finance Minister in his speech has repeatedly emphasized the word 'growth.' Sir, you enable and encourage growth by providing investment boosters. You attract capital by rationalizing and simplifying taxation. Nothing has been done in this respect except that MAT has been increased from 10 per cent to 15 per cent, which in itself is a stop that is anti-growth and anti-industry. Sir, you feed economic momentum by cutting out the Public Sector waste and by improving industrial productivity, which is directly linked to labour reforms. Sir, the Budget makes no mention of disinvestment and also of the Government selling its stake in sick PSUs. Out of 214 PSUs under the Central Government control, only 160 are in the black, 54 are in the red, but only 99 have a positive net worth.

Sir, we need to privatise rapidly so that public sector companies become more accountable and the Ministerial interference in day-to-day running of the companies is eliminated. More importantly, it would help the Government reduce its huge fiscal deficit, which is the need of the hour, as such a heavy fiscal deficit would, certainly, lead to downgrading of India's credit ratings. It would also lead to very high inflation rates in the medium to long-term, once the economies of the developed World stabilize and the global demand picks up.

Sir, this Budget has done nothing for our labour-intensive export-oriented industries, specially, segments like garments, leather, gems and jewellery, handlooms and carpets. They employ millions of unskilled labour, many of whom, thanks to the recession, have lost their jobs. Garment export

industry alone earns the country $ 10 billion per annum and employs 3.9 million people directly and 3 million people indirectly. It is the second largest employer after agriculture. It is distressing to note that a small country like Bangladesh is exporting more than India. The Finance Minister needs to urgently provide some tax incentives for a limited period to these labour-intensive industries.

Sir, I welcome the inclusive programme of the Government, especially, to provide subsidized foodgrains to the BPL families. However, three questions come to my mind. (a) What is the definition of a BPL family? (b) Where will the food to feed the poor come from? (c) How do we ensure long-term food security for our nation?

Sir, the entire House would agree with me that Punjab has, traditionally, been the food bowl of the country. I want to caution the Finance Minister that if the present attitude of the Central Government persists and Punjab's demands for strengthening and improving its canal system are ignored, the State would not be in a position to feed the nation in the future. Our groundwater resources are fast depleting and our yields are also declining. We have requested the l3th Finance Commission to provide Rs.12,750/- crores as 90 per cent cost of repair and expansion of our water resource infrastructure till 2014-15. This will ensure much higher foodgrains production and food security for the country. Sir, from the last six weeks, Punjab has been spending Rs.250 crores every week to buy expensive electricity to save the paddy crops. However, our request for compensation from the Centre continues to fall on the deaf ears.

Sir, in his Budget speech, the Finance Minister mentioned that the norms for distribution of fertilizer subsidy would be changed and the subsidy would be given directly to the consumer. This is creating some disquiet in Punjab as our farmers are large consumers of fertilizers. The Government's delivery mechanism, being what it is, can lead to serious difficulties for the farmers in our State and I hope the hon. Minister would urgently spell out the contours of the new policy.

Sir, the Finance Minister needs to take a holistic view and rationalise the distribution of revenue between the Centre and the States, especially, in view of the Sixth Pay Commission Report which has broken the back of all the small States. Punjab, for example, gets only 1.30 per cent of the Centre's tax collection, but faces an additional burden of Rs. 3000 crores per annum in addition to Rs. 4800 crores of arrears for its employees. Sir, 85 per cent of the State's revenues goes into paying salaries and interest. This plight is similar for other States also. ...(**Time-bell**)...

Sir, in the end, I would like to mention that the footprint of the Naxalites is increasing rapidly. It is not just a law and order problem but an economic problem which we need to address urgently. Our extremely poor countrymen have lost all hope in the system and are taking to the gun. We must take immediate steps to uplift these districts economically. I would urge the Finance Minister to offer 100 per cent tax incentives to industrialists who set up industry in the extremely backward districts of this country so that employment can be generated there and the people living in these areas join the mainstream. Thank you.

MS. MABEL REBELLO (Jharkhand): Sir, I stand here to support this Budget. I congratulate the Finance Minister and our UPA Government for taking a pro-poor approach for this entire Budget. This is a social sector Budget. This Budget has increased allocation for NREGA. This Budget has increased allocation for Mid-Day Meal, for Anganwadi, for Bharat Nirman, farm credit and water resources. This is what we need. People are talking about deficit. Just because Rs. 39,000 crore has been earmarked for NREGA, people feel that it is like a populist measure and this money will be wasted. If this sort of allocation is given to the industrialists, they use it very well. From the public sector banks, the industrialists have taken multi-multi thousand crores of loan, and they have not paid it back. Then, that is okay for them. But if a poor farmer is not able to pay back and if a poor farmer is given Rs. 71,000 crores waiver, that hurts the industrialists. I do not understand this logic. I really congratulate the Finance Minister and compliment him for his bold stand for taking a view on social sector and trying to bridge the gap between the rich and the poor. He is trying to bridge the urban and rural divide. He is trying to bridge it. I also congratulate the Finance Minister for increasing the gender Budget by 105 per cent. Sir, if you see the trends of the Budget, for the last 10 years, you will see that UPA has given more subsidies. Sir, compare the five-year term of NDA and ours. This is our sixth Budget. Even here, we have given huge subsidies on power, on food, on mid-day meal, on ICDS, on health. Just compare these subsidies with what they gave. They gave Rs. 44,000 crore during their last year for all these types of schemes, whereas we have given this year Rs. 1,11,000 crores of subsidy, double the subsidies because we care for children. We want the children to come to the school; we want malnourishment to be - abolished. That is why we are spending a large amount of money on children and on women, so that our human resource really becomes rich. Without human resource, even if you have wealth, it is of no use. That is why we are doing this. Similarly, just see our planned expenditure. When the NDA was in power, they had spent only Rs. 1,32,000 crore. This year, we are spending something like Rs. 3,25,000 crore. This shows that the UPA Government is spending more money, giving more money to the States, more money to the people, more money for the poor so that the quality of the life of poor man improves. So, this Budget shows that money is not a problem. Plenty of money is there. But the only thing is that it should be utilized properly by the States, by the Executives so that the poor really become rich. I don't say, 'very rich', but, at least, poor will be able to come above poverty line. Similarly, talking of subsidies, UPA Government in their last regime, during 2004-05, gave only Rs. 43,000 crores subsidy, whereas we have given Rs. 1,06,000. For food, they gave Rs. 25,000 crore, whereas we gave Rs. 52,000 crore for BPL families. For fertilizer subsidy, they had given a pittance, Rs. 12,000 crores whereas we have made a provision of Rs. 50,000 crores. We really care for the poor farmers also.

Since I am associated with the social sector, I would like to speak on social issues, Sir. The very emphasis of this Budget is rural development and rural employment generation. You are aware that

Rs. 39,000 crores have been allocated for NREGA. And almost Rs. 10-12,000 crores are lying with the States. So, effectively, it comes to Rs. 50,000 crores. So, if this Rs. 50,000 crores given for NREGA is used well and effectively and, at least, 60 per cent of the wages go into the hands of the poor in the 500 districts of India, that means effectively 100 crore will go per district. And if, of the Rs. 100 crore per district, even Rs. 60 crores are spent on the poor, we shall get rid of poverty within a short span of time and a large number of our people shall move above the Poverty Line. This is the intention of the UPA Government. Sir, about 4.5 crore households got employment last year. That is almost 25 per cent of our rural poor. And, this year, with this increase, almost 6 crore households will get employment. If they really get employment and if we all ensure that this money really reaches the poor man and, that too, the full amount – hon. Finance Minister has made it Rs.100 now – I don't think there will be poverty, or there will be malnourishment. Everybody will live happily and everybody's quality of life will improve. And, since the minimum wage has been increased to Rs.100, States like Jharkhand, Orissa, Bihar, Chhattisgarh, from where people usually migrate, all this migration will stop. And, they will be able to look after their families well. They will be able to cultivate their land well, and they will be able to lead a better life. Sir, there were 115 districts which had been selected by our Government as pilot project to have convergence with NREGA and, that is, convergence with agriculture, forestry, land and water resources. I tell you, Sir, in Jharkhand, six districts have been selected for this convergence. I request hon. Finance Minister to prevail upon the Rural Development Minister to see that 24 districts of Jharkhand are included for this convergence because Jharkhand is a poor State. Similarly, coming to the Indira Awas Yojana, this year, Rs.8800 crores have been given. I am happy to tell you that for Jharkhand, they have given two lakh *Awas* units in the Indira Awas Yojana. People are really happy that per district almost 10,000 Indira awas units have been given; people can build nice houses and live in them happily. This is what our UPA Government is doing. Now, the poor can live in nice houses and also do not fall a prey to the Naxalites. Similarly, Sir, for the AIDP scheme, allocation has been increased to Rs.9700 crores. ...(**Time-bell**)... What is this, Sir? Before I start, you ring the bell.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Please conclude. You have been given eight minutes.

MS. MABEL REBELLO: All right, Sir. Anyway, I am very, very happy about this allocation to the AIDP scheme. But I have a problem with the Pradhan Mantri Sadak Yojana. The length of the bridges that come within that project are limited to fifty meters. I request the hon. Minister to waive this clause, particularly in the case of the Naxal-affected districts and LWE-affected districts so that whatever the bridge length may be, whether it is fifty meters, hundred meters or 120 meters, the entire bridge should be included; the entire cost should be given by the R.D. Ministry, without depending upon the State. Similarly, the Finance Minister has given hundred crores to start branches

of banks in non-banked Blocks. What will happen with this? NREGA people, all those people who have got job cards, can open their bank accounts and the money can be deposited there so that all these contractors and others who are trying to cheat people, are not able to do that and the money goes to the people. Similarly, I want to especially thank the Finance Minister for introducing a new educational scheme for the development of children living in tribal areas, which comes under Schedule V, and Naxal-affected areas. He has made a provision of Rs.500 crore towards this scheme. This is a very good measure, especially for the States of Jharkhand, Chhattisgarh, Orissa, and parts of Bihar which are Naxal-affected. People living in these areas will be greatly benefited by this scheme. The tribal people, who are feeling alienated, may be brought back to the mainstream. They should be given good education, so that they also feel that they are wanted by the country and they do not join Naxals. By doing this, we can prevent them from going towards Naxals.

The Finance Minister has also made a provision of Rs.100 crore for developing critical infrastructure in the areas which are affected by the Left Wing Extremists. This is a big help to the people of Jharkhand, Chhattisgarh, Orissa and other places.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Please conclude.

MS. MABEL REBELLO: Coming to educational institutions, out of the three States, namely, Jharkhand, Uttarakhand, and Chhattisgarh, Chhattisgarh and Uttarakhand have been given AIIMS-like institutions, but Jharkhand has been deprived of it. I do not know why. Similarly, so many IITs and IIMs have been started all over the country. But nothing has been given to Jharkhand.

For the last 8-9 years, people of Jharkhand did not have a stable Government. People of Jharkhand have been deprived of the benefits. Our executives have not been able to prepare projects and come to the Government of India to take money and use it for the people to help them improve their lives. Now they have been deprived of all these institutions. Sir, what will happen to the people of Jharkhand? Sir, you have been from a part of Bihar. You should do some justice with Jharkhand. I seek your indulgence in the matter. Please don't treat Jharkhand as a colony of Bihar.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): I am sorry, the time allotted to you is over.

MS. MABEL REBELLO: Sir, Jharkhand has become an independent State. But it is still treated as a colony of Bihar.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): You have already consumed your time.

MS. MABEL REBELLO: Sir, two minutes only. Sir, Jharkhand is a State which receives 1400 mm of rainfall. In spite of that, people are able to have just one rainfed crop. There is no irrigation at all. The average national irrigation is 40 per cent and Jharkhand has just six per cent. This is what Bihar has done to Jharkhand, and we have not been able to improve upon it.

I, therefore, request you, as suggested by Prof. M.S. Swaminathan, Chairman, National Commission on Farmers, that rate of interest on loan to farmers should be brought down from six per cent to four per cent. China gives loan to its farmers at zero per cent rate of interest. That is why they are able to produce so much foodgrains. We must give incentives to our farmers. Otherwise, our youth will go away from farm sector. ...*(Interruptions)* Tamil Nadu is able to give it. But Jharkhand does not have money to give it. Sir, I seek your indulgence and request you to prevail upon the Finance Minister to see that, at least, the farmers, the youth of Jharkhand may be given special attention.

Sir, lastly, in terms of electricity, Jharkhand has a very bad situation due to historical reasons. I ask the Finance Minister to give a special package for Jharkhand. If it will improve in this area, especially distribution, we can have a sub-station in every district. If this is done, the supply of electricity will improve and people will get electricity. In the *Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana,* we are giving single phase connection to poor people. I request you to provide Jharkhand a special package, so that its farmers may be given three-phase connection. This will help them lift water and they will be able to produce more crops. Then they need not come to you for any assistance and Jharkhand may stand on its own feet and become prosperous.

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL (Gujarat): Thank you very much, Mr. Chairman, Sir. I am here to speak about Annual Budget for 2009-10. Originally, I thought that I should give a total reply to my colleague, Mr. Arun Shourie, from BJP. But I will not do that because there is a shortage of time, and I am sure, the hon. Finance Minister will do an appropriate job. Wherein Mr. Shourie has raised various issues which were not connected with the Union Budget, I mean, talking of event of 1940, particularly the partition of India, that I want to reply because it should go on record. He quoted some British author with his book. That author, Mr. Smith or someone like that, declared in the year 1940 that there would be a partition of this country. Mr. Shourie does not know that the division of the country was demanded by Mr. Savarkar as back as 1937 in his speech in Ahmedabad when he was President of the Hindu Maha Sabha. First time, the demand was made by Mr. Savarkar about a two-nation theory that Hindus and Muslims cannot stay together. That is for the information of Mr. Shourie. I may also inform him that Dr. Ambedkar wrote a book first on Pakistan as back as 1944. I may further inform him that the first demand from a Muslim leader, named Jinnah. To whose *Samadhi*, Mr. Advani visited and paid respect; made a demand of Pakistan in the year 1944, and for information of my colleagues here, let me tell you that the word "Pakistan" is not an Urdu word. The word "Pakistan" was coined by a student of Oxford taking first word of the district or the area of that particular part of India, where the majority Muslim population was residing, and that was 'P' for 'Punjab', 'a' for 'Afghanistan', 'k' for 'Kashmir', 'i' for 'Sind' and 'stan' for 'Baluchistan'. This is how the word "Pakistan" was coined. This is just for the information of Mr. Shourie.

But when I come to the Union Budget, and, in total support of the Budget, presented by the hon. Finance Minister, I will restrict myself to only two areas of 'expenditure'. On the one side, I also want to request my senior colleagues, particularly Dr. Jalan and Dr. Rangarajan, who are here. And, then, we had a retired Revenue Secretary; Mr. N.K. Singh is also here. They are all well-informed and very senior in this particular subject, and they have all raised the issue of deficit, that the fiscal deficit is on a higher side. Now, I am a layman. No doubt, I am also a student of Economics. I did my graduation, from Bombay, in the year 1964, but I do not know much like them. But I just want to request them to, at least, explain to me, whenever they find it convenient. I see this map in the Union Budget where 31 paise are given back for Planned Budget to Union, to States and Union Territories; 19 paise are given for interest payment; 12 paise are given for defence; 10 paise are given for subsidies; 14 paise are given for non-Plan expenditure! And you know what is non-Plan expenditure. And the State share of taxes and duties which is written back by the Central Government comes to 14 paise. Now, this is how we make '100 paise'. As a layman, I may please be informed where the Finance Minister can reduce. Can he reduce the expenditure of defence? Can he reduce the expenditure of the Plan? Can he reduce the expenditure of State share of taxes? Where and in which area? This is for my information. I want their help.

Sir, now, when I come to the 'expenditure' side, I am restricting myself only to two paragraphs from the Union Budget and where I am very much in support of the Union Finance Minister. One is 'inclusive development' – and my sister, Miss Mabel Rebello, has talked about that 'inclusive development', which includes NREG, national food security, Bharat Nirman, Pradhanmantri Rozgar Yojana and another beautiful Yojana meant for Scheduled Castes, in particular, of 44,000 villages, according to the Union Finance Minister. This is a very good information available for all those who are worried for the weaker sections of the society. I may request my colleagues that we should also help these particular villages. There are 44,000 villages in our country where the estimated population of S.C. is above 50,000. As the hon. Prime Minister is very much worried about inclusive growth, the Budget has taken care to see that we should do something for these 44,000 villages which are occupied by the lowest of the low in this country. They are low not only economically but also socially and religiously. Here again, I want to give a reply to my colleague Mr. Arun Shourie who gave a very wrong economic policy yesterday. He said, "If the Government wants to help the poor, they should do it on an individual basis". I am afraid, it can never be done. If the Government wants to help the minority, it has to help the minority as a class. Another misconception among the learned people in this country is that by "minority" they mean only Muslim. It is wrong. The minority in this country does not mean only Muslim. The minority for the Central Government includes Sikh, Buddhist, Christian and Muslim. When you go to Gujarat and certain other States, Jain is also included in the minority. So, all minorities made together ...(**Time-bell rings**)... I may be given more time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): You have been given seven minutes.

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Otherwise, I will not be able to reply to my learned friends. The total expenditure for this inclusive growth is Rs.69,000 crores. Here are these villages of Scheduled Castes. When the learned Finance Minister has admitted that there are 44,000 villages, if we select only 1000 villages a year, we will not be able to do any welfare. So, I request that the number of villages, where help should be given, should be increased to 1,00,000 per year.

Now, I come to the second most important point, the empowerment of weaker sections where all these schemes are there. My specific suggestion – let me come to my specific suggestions – is about income-tax slab. It is very important. The learned Finance Minister...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Please conclude.

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: ... has not increased the tax exemption limit. But I will request that the maximum limit of taxable income for all should be raised from Rs.1,60,000 to Rs.2 lakhs; for women, it should be raised from Rs.1,90,000 to Rs.2.25 lakhs; and for the senior citizens it should be raised from Rs.2.4 lakhs to Rs.2.5 lakhs.

My another request is – I have also written a separate letter that in our country there is separate age limits for senior citizens. In the Railways, it is 62; in the Air India, it is 65; and in the Central Government, it is 60. I have written a letter. I will give you a copy of that letter. I have got a copy here. It is dated June 18, 2009 and addressed to the learned Finance Minister requesting that the age limit may be made uniform for alt purposes. That is my request.

The last but not the least, I am very much worried about the welfare of the Scheduled Castes and here I quote the reply given to me in this very House on 2nd July, 2009:

> "Prime Minister in the 51st meeting of the National Development Council, held on 27th June, 2005 had stated 'in the mid-1970s, the SCSP and TSP were initiated. TSPs and SCSPs should be an integral part of Annual Plans as well as Five Year Plans, making provisions there non-divertible and non-lapsabie, with the clear objective of bridging the gap in socio-economic development of SCs and STs within a period of 10 years."

The hon. Prime Minister wanted to bridge the gap within a period of ten year. It can be done only if the budget allocation is made for the welfare of SCs and STs on the basis of their population. If the population of SC is 20 per cent and of ST is 8 per cent in this country, today, the budget must be equal to their proportion, in the Plan, not in the non-Plan. Suppose there is a Plan expenditure of Rs. 4,00,000 crores. Then 28 per cent should be made available for the economic welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Then only we will be able to meet the gap. With these words, I conclude my speech. Thank you.

SHRI M.V. MYSURA REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I heard with rapt attention the speeches of leading economists, industrialists and also of politicians on the Budget. I come from a rural family, a farmer family. I can say one thing that I cannot use 'high-profile' economic or technical words. But, one thing I can certainly say that I know my income and my expenditure. If I have some savings, I can adjust that in some property by borrowing some loan also. Perhaps, that is the basic principle of any budget.

The common notion is, redemption of taxation from rich people and some part of it can be spent for poor people and for infrastructure and basic amenities. Indirect taxation can definitely be passed on to the consumers by way of prices. Direct taxation also reflects on the prices of commodities. That is why all kinds of taxes excise, customs, service tax, including corporate and income tax, etc., are paid by the people, promptly, by purchasing commodities, directly or indirectly. But the corporate sector and non-corporate sector, and individuals are not passing the taxes to the Government, in one or the other way, by creating some disputes or by delaying tactics. Let me refer to Annexure 10 of the Budget Receipts of 2009-10 - 7 revenues raised but not realised. Sir, Rs. 64,000 cores are under dispute and the undisputed amount is Rs. 39,000 cores. The total put together is Rs. 1,09,000 crores. Annexure 12 of the Budget Receipts talks about revenue foregone because of special tax rates, exemptions, deductions, rebates, differences, credits, etc. These measures are sometimes called as tax preferences. This will have an impact on the Government revenue also. It is approximately Rs. 4,18,000 crores.

Sir, I would like to refer to paragraph 102 of the Budget Speech regarding one exemption. It says, "It is necessary for us to create our own facilities for energy security. Accordingly If propose to extend the tax holiday under Section 80 1B (9) of the Income Tax Act." He further says, "I also propose to retrospectively amend this provision." It looks as if there is only one favoured beneficiary in this, and that is, RGTI, a 100 per cent company owned by Shri Mukesh Ambani. He will get tax exemption of Rs.20,000 crores because of this Pexemption. And, who has given them the authority to give it retrospectively? Now, because of these tax exemptions in corporate tax, personal tax, excise duty, customs duty, less export credit, the revenue loss would come to around Rs.4,18,000 crores.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

It is not Rs.100 crores or Rs.200 crores, but it comes to around Rs.4,18,000 crores. As compared to allocations, it may look to be a meagre amount. Now, apart from tax exemptions amounting to Rs.4,18,000 crores, there are also arrears amounting to Rs.1,09,000 crores, and we also have the various subsidies. Food subsidy stands at Rs.52,000 crores; fertiliser subsidy is Rs.49,000 crores and farmer debt waiver scheme amounts to Rs.15,000 crores for 2009-10. Sir, the hon. Railway Minister stated, while replying the other day, that if she had Rs.4,00,000 crores, she would complete all the pending railway projects in one go. But the money has to come from the Budget allocations to the Railways.

Sir, the present receipts come to Rs,6,00,000 crores, apart from States' receipts, and the revenue foregone is Rs.4,00,000 crores. Does it reflect economic recession, or, is it due to inclusive growth? I am puzzled as to whether the contribution is made by Aam Aadmi or the rich man. The reward for poor man's mighty contribution is in the name of infrastructure creation on PPP model and taxing a booster dose in the form of toll tax and user development charges for their corruption and inflated cost of the project.

Sir, the other thing, which I would like to mention, is about debts. The interest payments and debt servicing in 2009-10 stood at Rs.2,25,000 crores. As per the Economic Survey, the interest rate is 8 per cent. This will only help in the growth of fiscal deficit. It is next to impossible to bring it down. The market borrowings of this year is Rs.4,40,000 crores, and the earliest date of maturity would be year 2039. People have given the mandate...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mysura Reddy, you have to conclude because there are already 17 Members.

SHRI M.V. MYSURA REDDY: The people of this country have given mandate to this Government only up to 2014. How can the people be burdened up to 2039? Who has given authority to this Government to penalise the future generation? Then, Sir, the outstanding internal and external debt of the country, at the end of 2009-10, apart from guarantees, stood at Rs.34,95,000 crores. In 2007-08, it was Rs.28,37,000 crores. The total assets at the end of 2007-08 was Rs.6,35,000 crores...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to call the next speaker ...*(Interruptions)* ...I am calling the next speaker.

SHRI M.V. MYSURA REDDY: If one is in such kind of a situation in a family or organisation, people call them as insolvent family or insolvent organisation, I do not know what economists and industrialists would say on this.

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान) : धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। मुझे दस मिनट दिए गए हैं?

श्री उपसभापति : नहीं, आपको सात मिनट दिए गए हैं।

श्री प्रभा ठाकुर : सर, मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगी। उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह संतुलित और व्यावहारिक है। उसमें उन्होंने आम आदमी की सुविधाओं का ध्यान रखा है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों, गांवों एवं शहरों, सभी का पूरा ध्यान रखा गया है। जब मंदी के इस दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है, उस समय में अब तक का सबसे बड़ा बजट, 10 लाख करोड़ से भी अधिक राशि का बजट वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। उसके लिए मैं उनको और सरकार को बधाई देती हूं।

महोदय, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ग्रामीणें के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, एससी/एसटी समाज के लिए, युवाओं को रोजगार और शिक्षा देने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए, इंदिरा आवास योजना के लिए, बीपीएल के लिए और स्वास्थ्य, परिवहन, सड़क, रेल, पेयजल, सभी क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए बजट अलॉकेशन किया गया है और एक अच्छा-खास बजट इन सभी क्षेत्रों को दिया गया है।

महोदय, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहूंगी जो बातें पहले कही जा चुकी हैं। मैं कुछ खास चीजों के ऊपर कहना चाहूंगी। मैं ज्यादा आंकड़े भी नहीं देना चाहूंगी क्योंकि ये वित्त मंत्री जी के भाषण में हैं। इनके बारे में सभी जानते हैं कि मेरे कई साथी भी इसके बारे में बोल चुके हैं। सर, सबसे बड़ी चिन्ता का विषय तो यह है कि पिछली बार भी हर राज्य को व्यापक बजट दिया गया है। एनडीए सरकार से जितनी राशि मिलती रही थी, उससे चौगुनी राशि पिछली बार भी यूपीए सरकार ने हर राज्य को बिना किसी भेद-भाव के विभिन्न योजनाओं के तहत दी थी और इस बार भी दे रही है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग भी पूरी हो। उसका कोई मापदंड भी सुनिश्चित हो कि जब भी किसी मामले में निर्माण संबंधी कोई योजना हो, कोई बात हो तो उसका कोई पैमाना केन्द्र सरकार द्वारा सुनिश्चित होना चाहिए। अगर उस पैमाने के हिसाब से राज्य सरकारें काम करें, तभी उस बजट की पूर्ति उन्हें आगे की जाए। अगर ऐसा कुछ सुनिश्चित नहीं करेंगे तो यह जो भ्रष्टाचार का मामला है, जिस पर राजीव गांधी जी ने चिन्ता जताई थी कि जितना धन दिया जाता है, उसमें से 15 पैसे पहुंचते हैं। जो जनहित का पैसा है, वह ऊपर से लेकर नीचे तक सब की जेबों में पहुंच जाता है। इसी प्रकार, आज भी राहुल जी ने भी उसी बात को दोहराया है कि 10 पैसे जनता तक पहुंचते हैं। सर, इसका स्पष्ट रूप से यह अर्थ है कि धन देने में कमी नहीं है। केन्द्र सरकार धन देती है, लेकिन जिनके लिए यह दिया जाता है, वे लोग फिर भी उससे वंचित रह जाते हैं। सर, यह जो भ्रष्टाचार की नदी है - एक तरफ तो भ्रष्टाचार है और दूसरी तरफ बढ़ती हुई जनसंख्या है, यह हमारे सारे विकास को खा जाती है। इन पर किस तरह नियंत्रण लगे, सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मेरे ख्याल में इतना दिया हुआ बजट पर्याप्त है, इसमें कोई कमी नहीं है। इससे हर क्षेत्र में खूब विकास और तरक्की हो सकती है। पूरा भारत चमक सकता है। भारत के गांव चमक सकते हैं।

महोदय, किसानों की सुविधा के लिए और गांवों के विकास के लिए प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत एस.सी. बाहुल्य और बी.पी.एल. बाहुल्य गांवों के लिए 10 लाख रुपये का अलॉकेशन किया गया है। किसानों के लिए जो उर्वरक पर सब्सिडी दी जाती है, वह फैक्टरीज़ या इंडस्ट्रीज़ को न देकर डायरेक्ट किसानों को दी जाए, जिससे किसान लाभान्वित हों, सरकार ने यह विचार किया है। मैं यह भी मांग करती हूं कि जो कुटीर उद्योग है - किसानों को यह प्रशिक्षण दिया जाए कि वे खुद दालें बना सकें। वे खुद अपना Self Help Group बना सकें। सरकार कोई ऐसी स्कीम दे कि अपना Self Help Group बनाकर खुद दालें या आटा बना सकें और छोटे-छोटे कुटीर उद्योग लगा सकें जैसे कि महाराष्ट्र एवं कई और जगहों पर लोग शुगर इंडस्ट्री द्वारा चीनी बना रहे हैं। वे खुद मसाले, आटा, टमाटर का sauce और चटनी बना सकें एवं आयुर्वेदिक दवाओं संबंधी फसल उगाकर अपनी फसल का पूरा लाभ ले सकें। महोदय, मेरा यह निवेदन है।

महोदय, पिछली बार 72 हजार करोड़ रुपए की राशि किसानों की माफ हुई थी। आज कई जगहों पर यह स्थिति जरूर आ रही है कि बैंक लोन नहीं दे रहे हैं। किसान परेशान हैं। बैंकों को लगता है कि शायद वे नहीं चुकाएंगे और कहीं न कहीं किसानों की भी ऐसी भावना है। तो बैंक किस प्रकार उन्हें लोन दें और योजना कुछ इस प्रकार की हो, मैं सरकार से दरख्वास्त करुंगी, कि जहां अकाल पड़ जाए या फसल बर्बाद हो जाए, उस क्षेत्र के उस जिले का आकलन किया जाए और उसके आधार पर कम से कम उस जगह के किसानों का अगली फसल होने तक ब्याज माफ किया जाए, ऐसी व्यवस्था भी सरकार करे, यह किसानों के हित में होगी।

महोदय, गांवों में मिड डे मील देना, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी योजना है। 'नरेगा' योजना एक ऐतिहासिक योजना है, जिसने पिछली बार रोजगार देने का बहुत बड़ा काम किया है। इस बार सरकार ने उसमें बढ़ोत्तरी करके

100 रुपए रोज की जो मजदूरी निर्धारित की है, उससे पूरे देश के गांव के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। महोदय, वह पूरा पैसा उन्हें मिले, काम ठेके पर न हो, उन तक मजदूरी का सही-सही पैसा, 100 रुपए मजदूरी का, उन तक पहुंचे, इसके बारे में भी किसी समिति का केन्द्रीय स्तर पर गठन होना चाहिए और मॉनिटरिंग होनी चाहिए।

महोदय, आज बिजली की कमी है। ऊर्जा के लिए ही परमाणु करार किया गया है, ताकि बिजली की कमी दूर हो। बिजली के लिए दिल्ली में और कई जगह त्राहि-त्राहि मची है, जिसके कारण पंखे तक नसीब नहीं होते, एक बल्ब तक नहीं जलता। बिजली की यह कमी कैसे पूरी हो, यह देखा जाना चाहिए। सर, पिछली से पिछली बार जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, तो वहां बिजली बनी। पिछली सरकार ने एक यूनिट भी बिजली नहीं बनाई। राज्यों को यह निर्देशित किया जाए कि हर राज्य के लिए इतने यूनिट बिजली बनाना जरूरी है और उसी आधार पर हर राज्य को आगे उस क्षेत्र में बजट दिया जाए।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस सरकार ने बहुत कुछ किया है। बहुत योजनाएं हैं और केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात भी पूरे देश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है।

महोदय, मैं कुछ बातें विशेष रूप से कहना चाहूंगी पेयजल के बारे में। पीने का पानी एक ऐसी चीज है जो कि स्वास्थ्य से जुडी है, लेकिन आज भी हमारे देश में कई जगह लोग अशुद्ध या फ्लोराइड युक्त जल पीने को बाध्य हैं। पानी मनुष्य की एक मूलभूत जरूरत है। वायु के बाद जल ही पहली चीज है जो जीवन के लिए, प्राणियों के लिए, कृषि के लिए, सबके लिए जरूरी है। स्वच्छ और मीठा पेयजल सबको उपलब्ध हो, यह आवश्यक रूप से देखा जाए।

श्री उपसभापति : समाप्त कीजिए।

डा. प्रभा ठाकुर : यह बहुत जरूरी समस्या है, सर, जब समुद्र का जल पीने योग्य बनाया जा सकता है तो सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती कि समुद्री तटों पर ऐसे कारखाने लगें। जब गैस पाइपलाइन विदेश से भारत द्वारा पहुंचाई जा सकती है तो पाइपलाइन से मीठा समुद्री जल राज्यों तक क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता? कई खाड़ी देशों में भी इस तरह से समुद्री जल को मीठा किया जा रहा है। मैंने जब पता किया तो मुझे जानकारी हुई कि इसमें सिर्फ 80 पैसे प्रति लीटर पर खर्च आता है। तो ऐसे, पाइपलाइन के जरिए किसी भी तरह से समुद्री जल को मीठा पानी बनाकर लोगों तक पहुंचाने का बजट बनाया जाए। यह 20 रुपए, दूध से महंगा पानी की बोतल कौन खरीद सकेगा? सर, इस बारे में भी कुछ हो।

सर, चिकित्सा और शिक्षा ये नोबल चीजें हैं, लेकिन यह पूरा व्यापार बन गया है। कहते हैं शिक्षा बढ़ाओ, लेकिन ऐडमिशन मिलता नहीं, 70-70 परसैंट वाले बच्चों को ऐडमिशन नहीं मिलता है। कहते हैं चिकित्सा कराओ, लेकिन 'एम्स' में 24-24 घंटे तक लोगों का नम्बर नहीं आता है। इसलिए शिक्षा और चिकित्सा पर विशेष बजट आबंटित करने की जरूरत है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please conclude. आप यह जब हेल्थ मिनिस्ट्री पर डिस्कशन आएगी, उस समय बोलिएगा। श्री तारिक अनवर।

डा. प्रभा ठाकुर : ग्रामीण क्षेत्रों में लोग तरस रहे हैं, न उनको शिक्षा मिलती है और न ही चिकित्सा। इसके लिए विशेष बजट का आबंटन हो। सर, 'नरेगा' के तहत यह काम हो कि चिकित्सा केन्द्रों का निर्माण हो। लोग जांच नहीं करा सकते हैं, हजारों रुपए तो स्वास्थ्य की जांच कराने में लग जाते हैं। तो सरकार द्वारा स्वास्थ्य जांच केन्द्र स्थापित हों और इसका भी कुछ बजट हो।

श्री उपसभापति : बस, हो गया।

डा. प्रभा ठाकुर : सर, मैं अंत में कहूंगी कि राजस्थान का दो तिहाई भाग रेगिस्तानी है, तो पहाड़ी क्षेत्रों की भांति राजस्थान को भी विशेष स्टेट का दर्जा देते हुए, उसको विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता है।

श्री उपसभापति : देखिए, ऐसे मत कीजिए। If you do not follow the time-limit – there will be guillotine at 5 o'clock – then, all the Members will not be able to speak. Shri Tariq Anwar.

डा. प्रभा ठाकुर : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी के इस दौर में एक संतुलित बजट पेश करना बहुत ही कठिन काम था, लेकिन हमारे वित्त मंत्री ने बहुत ही सूझ-बूझ का सबूत दिया है और उन्होंने कोशिश की है कि समाज के सभी वर्गों को विश्वास में लिया जाए, उनको संतुष्ट किया जाए। उपसभापति जी, वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं और यह स्वाभाविक है, यह आश्चर्यजनक नहीं है, परन्तु आम तौर पर देश की जनता की ओर से, देश के आम लोगों की ओर से इस बजट का स्वागत किया गया है। सबसे पहले हमें यह बात देखनी है कि वित्त मंत्री ने जो यह बजट पेश किया है, उसके पीछे उनका लक्ष्य क्या है। अर्थव्यवस्था की जो सुस्ती है, हमारे सामने जो चुनौती है, उसको कैसे तत्काल समाप्त किया जाए, कैसे उस चुनौती का सामना किया जाए, इस बजट में इस बात पर ध्यान दिया गया है। भाषण के आरंभ में ही उन्होंने जो लक्ष्य स्पष्ट किया है, वह इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में हमारी विकास दर को 9 प्रतिशत तक ले जाने की उनकी कोशिश है और उस पर सरकार का ध्यान है। मूलभूत संरचना के बारे में हमेशा चर्चा होती है, देश को इस बात की आवश्यकता है, जरूरत है, लेकिन मूलभूत संरचना का मतलब सिर्फ हवाई अड्डे से या नेशनल हाइवे से नहीं है, बल्कि जब हम कहते हैं कि यह देश गांवों का देश है, तो जब तक गांवों में इस मूलभूत संरचना पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक हम इस देश के जिस बुनियादी ढांचे को सुधारने की बात करते हैं, वह संभव नहीं हो सकता है। इसलिए पूरे बजट में इस बात पर ध्यान दिया गया और आम आदमी की जो बुनियादी समस्याएं हैं, उन पर ध्यान दिया गया। अगर यह कहा जाए कि यह "भारत" और "India" की दूरी को कम करने वाला बजट है, तो यह गलत नहीं होगा। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में 144 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, वृद्धि हुई है और इसके लिए लगभग 39,100 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं, भारत निर्माण कार्यक्रम में 45 प्रतिशत की वृद्धि, इंदिरा आवास योजना में 63 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी और ग्रामीण आवास कोष के लिए अलग से 2,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन कदमों से विकास की गति पर सकारात्मक असर पड़ना स्वाभाविक है।

उपसभापति जी, कृषि क्षेत्र के लिए भी कर्ज की राशि को 2 लाख, 87 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 लाख, 25 हजार करोड़ रुपए किया गया है। कृषि लोन का जहां तक सवाल है, हम लोगों ने इस बात को पिछले दिनों देखा कि इस देश के जो किसान कर्ज़ के बोझ से दबे हुए थे, उनको निज़ात दिलाने के लिए सरकार ने जो कर्ज माफी का काम किया, उससे एक बार फिर इस देश का किसान अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। इस बजट में उनके लिए जो कर्ज पर इंट्रस्ट रेट है, उसे घटाकर 6 प्रतिशत किया गया है। यहां काफी लोगों ने इस बात का सुझाव दिया है कि उसको घटाकर कम से कम 4 प्रतिशत किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसानों की स्थिति को नहीं बदलेंगे, जब तक किसानों को इस देश के विकास से नहीं जोड़ेंगे, तब तक सही मायनों में हमारे विकास की जो कोशिश है या विकास दर है, वह नहीं सुधर सकती है।

उपसभापति जी, इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि इस बजट में इस बात का ध्यान भी रखा गया है और जैसा हम लोगों ने महसूस किया है कि हमारे यहां जो अनाज पैदा होता है या फल पैदा होते हैं, उनको रखने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से इनमें करीब 40 प्रतिशत नुकसान होता है। इस बजट में इस बात के लिए प्रावधान किया गया है कि इसमें जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा investment होगा, उसको tax incentive से लिंक किया गया है और इस तरह यह कोशिश की जा रही है कि हमारे जैसा मुल्क, जो विकसित मुल्क है और जहां अनाज की कमी है, जहां लोग भूखे मरते हैं, जहां लोगों को जरूरत है, वहां अगर हमारे 40 प्रतिशत फल और अनाज बर्बाद होते हैं, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसलिए इसकी व्यवस्था करनी जरूरी है। और यह जो प्रावधान warehouse sector का और cold chain का इसमें रखा गया है, मैं समझता हूं कि यह एक दूरदर्शिता का परिचय है और आने वाले समय में इससे देश को लाभ मिलेगा।

महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में बहुत कुछ है, लेकिन उन सब बातों पर चर्चा करना संभव नहीं है, समय का अभाव है, लेकिन मैं एक चीज़ कहूंगा कि जहां दूसरे राज्यों की समस्याओं पर ध्यान दिया गया है, वहां बिहार राज्य के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। महोदय, बिहार की जो स्थिति है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। बिहार आज हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। जब से बिहार का बंटवारा हुआ, तक से बिहार और झारखंड बनने के बाद, उसके लिए लगातार यह मांग होती रही है। यह बात सही है कि झारखंड नया राज्य बना, लेकिन हकीकत में बिहार अलग राज्य बना, क्योंकि जब संयुक्त बिहार था, बिहार और झारखंड एक था, तो उस समय जो सारे उद्योग थे, माइन्स थीं, जो भी बिहार की आमदनी का ज़रिया था, वह झारखंड में चला गया और अब जो शेष बिहार बचा है, उसके पास कुछ भी नहीं है। आमदनी के तौर पर उसके पास कोई ज़रिया नहीं है। तो इसलिए आवश्यक है कि बिहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जब बिहार राज्य बना था, तो उस समय यह मांग आई थी कि बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाए, इसलिए मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री उस पर विचार करें और आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखें कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए।

महोदय, इस बजट में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित भी कुछ अच्छे फैसले लिए गए हैं, खास तौर पर वज़ारत अक़लियत के लिए जो 1740 करोड़ रुपया मुहैया किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैम्पस खोलने की बात फातमी कमेटी ने की थी, जिसमें उन्होंने पांच जगहों के लिए सुझाव दिया था, लेकिन इस बजट में सिर्फ दो ही जगहों में खोलने की बात की गई है - मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद, जबकि फातमी कमेटी ने बिहार में कटिहार, मध्य प्रदेश में भोपाल और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में भी खोलने की सिफारिश की थी। तो मैं चाहूंगा कि उस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि हम जब अल्पसंख्यक समुदाय को ऊपर उठाने की और उनको मेनस्ट्रीम में लाने की बात करते हैं, तो शिक्षा उनके लिए आवश्यक है और अलीगढ़ विश्वविद्यालय का कैम्पस जो पांच जगहों पर खोलने की बात है, इसके लिए फातमी कमेटी ने कहा था कि 2000 करोड़ रुपया लगाया जाए, मैं समझता हूं कि इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि मात्र 25 करोड़ रुपया इस काम के लिए रखा गया है, जो कि बहुत ही नाकाफी है। महोदय, ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि बहुत लोग बोलने वाले हैं, मैं अंत में अपनी बात उर्दू के एक शेर से समापत करना चाहूंगा -

"मंज़िल मिले न मिले, इसका ग़म नहीं,

मंज़िल की जुस्तजू में मेरा कारवां गुज़र गया।"

बहुत-बहुत शुक्रिया।

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Thank you, Sir. Today is the 107th Birthday of Karmavir Kamrajar, who was one of the tallest leaders of socialist mind and who was the All India Congress Committee President. We are celebrating the 41st year of the nationalisation of banks also. Sir, this Budget is dealing with a situation of crossing a road where there is history of 60 years. In the first 20 years, Jawaharlal Nehru created the basic structure of India by mixed economy and the Nehruvian thought and the Gandhian thought were mixed with that and the public sector and the private sector were allowed to go hand in hand so that economy of India can be pioneered in the world. At that time people were afraid why there is a Planning Commission and why there is this system of mixed economy. Subsequently, when Madam Indira Gandhi nationalised the banks and the General insurance companies, the people were saying that these were unnecessary things and they should be given to the private sector. But subsequent to the elections in 1980, Indira Gandhi made first attempt to focus upon privatisation. Sir, Rajiv Gandhi, as youth leader, created an impetus for private sector to play an important role. Subsequently, Sir, the mixed economy system was adopted throughout the world. At one stage, the Communists pioneered the mixed economy in some parts of the world and the capitalist countries have also taken this up in other parts of the world. Now, the Trios – the three leaders or Trimurthis – Madam Sonia Gandhi, Dr. Manmohan Singh and Pranabji, have created a great system and made India as the topmost leader in every sector in the world. Sir, Pranabji has presented a full-fledged Budget after more than 24 years. The youthful days of his Budget were more socialistic. Sir, with your permission, I just want to quote his words from the Budget Speech. They are at page 7 of the Budget Speech. Sir, he says and I quote, "I must state clearly that the public sector enterprises such as banks and insurance companies will remain in public sector and will be given all support, including capital infusion, to grow and remain competitive." This is the core of this Budget. The American economy looks at India to take this example. During last days in office, Mr. Bush took the example of India and infused money from the Treasury of the US into banks and insurance companies which were in the private sector to make them alive. Now, they took a leaf out of the Nehruvian socialist thought that when private sector is suffering or when the private sector is not sailing properly then the Government has to give a helping hand. So, as a result of the help, the private companies in the US are coming out of the meltdown. Therefore, this is a good system. Now, the entire world is realising that mixed economy is only the panacea for economic ills. At this junction, this Budget is very, very important. It has focused on the middle-class, labour and, at the same time, it protects the interests of the private sector as well. Sir, one of our economists, while speaking here, indicated that the production in the manufacturing sector in 2006-07 was very low. It is true. At that time, all the money was given through the nationalised banks. And, all the profits earned by private sector and manufacturing sector were diverted to China. They started to become the traders, rather than manufacturers. They purchased

manufactured things from China and traded them with their own brand name in India. Therefore, we suffered. We could not manufacture much. Now, there is a spree to use all our money and purchase assets and companies in other countries. No doubt, the East India Company 'purchased' India once up on a time. But, now, we can say proudly that Indians are purchasing companies in France, UK, USA and other countries. At the same time, we have to focus on an important thing. The lands are very much needed for our country. Now, lands are sold to foreign companies. That has to be stopped and regulated. Lands should not be sold to any foreign companies. Therefore, I request the hon. Finance Minister to save the country from being sold to foreigners. We should not repeat the history of the British Colonialism. Thank you.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, on the 6th of July when the Finance Minister got up to make his major speech, he was standing on the threshold of history. His hands were strengthened by the considerable mandate his Party had received in the recent Lok Sabha elections. On the other hand, he was facing the calamity of a global crisis. The third thing that did not find a mention in the discussion in this House was the global warming and the climate change. He got up on the 6th of July and the rains arrived in Mumbai on the 4th of July. If he had spoken two days earlier, I think, 20 per cent of the allocations made for the agriculture could have gone for the provision of irrigation or water facility because in the absence of sufficient water, the whole country would be in ruins. On that day, there was much discussion about the implications of the global crisis. What I would like to say is, Sir, that Mr. Finance Minister has said that his Budget is, actually, a roadmap for the five years to come. It is only history and the next elections which will decide whether he chose the right path. But on that day, given the importance of irrigation, as Dr. Swaminathan mentioned, that he has made provisions for irrigation, but there is so much water that can be available from the seas and from the clouds. What is important is to regulate the utilisation of water and for that purpose drip irrigation, sprinkler irrigation and the mist irrigation are the things these require considerable investment. A lot of water, with global warming, will get evaporated and, therefore, the under-the-sky agriculture will be in trouble and, therefore, massive investment will be required for covered agriculture. The Finance Minister has not made any provision for that. Sir, on the 6th of July, because of the delayed arrival of monsoon by one month, an unusual calamity arose. The NREGA employment was not available in the month of June because that is the month when the farmers normally need the labour. In the month of July when the rains came and the farmers wanted to do either the first sowing or the second sowing, they found that there were no labour at all. The NREGA is taking away labour from the normal agricultural operations because that is easy labour, which is getting money for signature while you have to do back-breaking work in agriculture. Sir, the President mentioned it and there is some reference in the Budget speech also about the need to carry out a thorough review, a transparent review of all the flagship schemes. I would suggest that

the Finance Minister should have proposed a comprehensive review of the working of the Debt-Relief and Loan-Waiver schemes also because in spite of the Government's claims, a number of farmers continue to commit suicides. Under these circumstances, it is necessary to know the reality. The Finance Minister has accepted a task force on the operation of money lending in Maharashtra. He has also offered one per cent interest reduction for those who make timely payment but it is necessary to find out how exactly the debt relief and loan waiver scheme was implemented on a computer basis. What was the advantage that farmers, actually, received. That kind of a study is extremely important. Sir, I would like to compliment the Finance Minister for a very major decision he took. I was working for that since a number of months. He has abolished the Commodity Transaction Tax for which I compliment him and congratulate him. I would only request that for too long a time, the Government has been perturbing the Futures Market. Abhijit Sen Committee gave a clean chit to Futures Market. And there was no reason for the Government to interfere in the Futures Market because that would create suspicion in the minds of farmers about the stability of the market. I would suggest the FM make sure that there are no further interventions without justification in the operations of Futures Market, so that this market will become a permanent feature in the Indian agriculture scenario.

Then, Sir, the next thing I would like to say is about the fertilizer subsidy. They have said that it would be made nutrient based. Yesterday, Shri Arun Shourie pointed out that this word had been used far too many times. What I didn't understand this time was that from the last year's figure of about Rs.1,00,000 crores, the figure of subsidy has been brought down by 50 per cent. If the Finance Minister does not know what are going to be the outline of the nutrient-based scheme, where the subsidy will be delivered directly to the farmers, what is this new calculation based on, I would like to know that. I would like to know that. Sir, then, on the concessional rate of interest given to the farmers, I would like to say that the Finance Minister, who was the Commerce Minister in 1986-89, under his own signatures admitted that the Indian farmers are suffering under negative subsidy. ...(**Time-Bell**)... He knows that the CACP does not provide for any kind of a profit margin in the calculation of Minimum Support Prices nor is there any calculation of the risk factor involved. Under these circumstances, forget 6 per cent, forget 7 per cent, .the farmers will not be able to pay even 4 per cent rate of interest. I would suggest that the Finance Minister should order a study into the profitability of agriculture whether it is possible for the farmers to pay even four per cent or six per cent. Let them recommend.

Sir, the last point that I would like to make – and that is going to be the crucial thing – is, it is said that from 6.7 per cent, we can go back to 9 per cent on the basis of a certain multiplier effect. I would like to submit that the aam admi or the inclusive approach is not going to help us in getting into the higher rates of growth. For one thing, as pointed out by a Hong Kong-based NGO, Indian

bureaucracy is a highly inefficient bureaucracy and is a highly corrupt bureaucracy. As pointed out by the Planning Commission, out of Rs.65 spent in from Delhi, not even one rupee reaches the other end. Further, Sir, the common man or the *aam admi* has a propensity for leisure. When his incomes increase, he goes more for leisure. And there is also a demographic effect of that kind of money going into the hands of *aam admi*. With this, Sir, I think, the money that goes into the hands of the so-called *aam admi* will not serve the purpose of inclusive growth. They will actually result in the lowering of the multiplier and therefore some of the calculations that he has made and the efficiency of the roadmap that the Finance Minister claims to have charted might come in doubt. Thank you, Sir.

श्री उपसभापति : श्री मंगल किसन। आपके पास पांच मिनट हैं।

श्री मंगल किसन (उड़ीसा) : डिप्टी चेयरमैन सर, फाइनांस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में 2009-10 का जो बजट रखा है, इसमें विशेषकर गरीब व आम जनता के लिए सिर्फ तीन या चार प्वाइंट ही रखे गए हैं। उनका पहला प्वाइंट है कि इस बजट के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख युवक-युवतियों को इम्प्लाइमेंट देने की व्यवस्था की गई है। दूसरा प्वाइंट है कि अभी भी एक-तिहाई पॉपुलेशन, जो बिलो पावर्टी लाइन, उसे वह 50% तक कम करेंगे और फिर इसे वह 2014 तक कंटीन्यू रखेंगे, यह उन्होंने अपने बजट भाषण में इंगित किया है। तीसरे प्वाइंट में उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में 4% ग्रोथ रेट को कंटीन्यू करने की बात रखी है। चौथे प्वाइंट में उन्होंने कहा कि देश में जितने भी बीपीएल कैटेगरी के परिवार हैं, उन्हें तीन रुपए प्रति किलो की दर से चावल प्राप्त होंगे।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो 1 करोड़ 20 लाख इम्प्लाइमेंट क्रिएट करने की बात कही गई है, वह कैसे क्रिएट होंगी और फिर वह उनके लिए धन कहां से देंगे? इस बात को वह ठीक से अपने बजट अभिभाषण में नहीं रख पाए हैं। फिर दूसरी बात यह है कि वह 50% बीपीएल कैटेगरी को रेड्यूस कैसे करके रखेंगे? उसके लिए क्या उपाय किया जाएगा, यह भी उन्होंने नहीं बताया है। बजट अभिभाषण में जो कुछ लिखा गया है, वह सही में गरीब आदमी के काम आएगा या नहीं, यह मेरी कुछ समझ में नहीं आता।

आज आजादी के 62 साल बाद भी न गांव में बिजली है, न पीने के लिए पानी है, न गांवों तक पहुंचने के लिए सड़क है। आजादी के पहले गांव की जो हालत थी, अभी भी कमोवेश वही हालत है और सरकार सोच रही है कि 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट बना देने से वह आम जनता का भला कर देगी, यह संभव नहीं है। कैसे यह पैसा आम जनता के पास पहुंचेगा जब उसके इम्प्लिमेंटेशन के लिए, मोनिटरिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है?

सर, हिन्दुस्तान का शैड्यूल्ड एरिया, जो फिफ्थ शेड्यूल में आता है, वहां न सिर्फ ट्राइबल्स और शेड्यूल्ड कास्ट रहते हैं बल्कि वहां अदर बैकवर्ड क्लास और अन्य कैटेगरी के लोग भी रहते हैं। आजादी के पहले शैड्यूल्ड एरियाज़ की एकोनॉमिकली, एजुकेशनली जो कंडीशन थी, जिस तरह पहले वह बैकवर्ड था, आज भी वहां पर ठीक वही कंडीशन है। लेकिन आज आजादी के 62 साल बाद भी हम लोग बोल रहे हैं कि देश की समस्याओं का समाधान हो गया है। This neglected population of the scheduled areas are now against the Government's policies. These people are afriad of the system. These people, who are dwelling in forests in the past, are now agitating against the injustice done to them by the Government. Sir, it is time that we included them into the system lest they feel cut off from the mainstream.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please, conclude.

SHRI MANGALA KISAN : Therefore, we must take utmost care of the scheduled areas, falling under the Fifth Schedule.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Shrimati Alka Balram Kshatriya. You have six minutes.

प्रो. अलका क्षत्रिय (गुजरात) : धन्यवाद, उपसभापति महोदय। सर्वप्रथम तो मैं विश्वस्तरीय विषम परिस्थितियों में भी संतुलित और कल्याणकारी बजट देने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं और साथ ही प्रस्तुत बजट को अपना समर्थन देती हूं।

महोदय, भारत गांवों में बसता है। देश की 60% से 70% आबादी कृषि पर आधारित है और इस वजह से अगर गांव आबाद होता है, तो देश भी आबाद होता है। गांव खुशहाल होगा तो किसान खुशहाल होगा और किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए तथा इसी बुनियादी सोच को ध्यान में रखते हुए पिछले पांच सालों में यू.पी.ए. की चेयर परसन श्रीमती सोनिया जी ने और हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह जी ने कार्य किया है, जिससे कि शहरों में केन्द्रित इंडिया की तरफ झुकी हुई उदारीकरण की नीति की वजह से गांवों में केन्द्रित भारत को नुकसान न हो तथा वह कहीं पिछड़ न जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले 5 सालों में बजट प्रस्तुत किये हैं, जिसे इस देश की जनता ने भी सराहा है और पिछले चुनाव में हमारी सरकार को समर्थन भी दिया है। इसी से यह साबित हो जाता है कि इस सरकार की नीति गांवों के लोगों के प्रति और गरीब आदमी के प्रति समर्थित रही है।

महोदय, मैं यह बताना चाहती हूं कि यह बजट समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याण्कारी है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, मध्यम वर्ग हो या वह अति पिछड़ा हो। हमारे वित्त मंत्री ने इसे सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ-न-कुछ दिया है। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं उन सभी पहलुओं पर बात न करते हुए कुछ एक बातों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

महोदय, गांवों में बुनियादी सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए तथा उन्हें सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्री जी ने जिन महत्वाकांक्षी योजनाओं पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है, उनमें से एक सबसे पहली योजना है - "भारत निर्माण कार्यक्रम"। इन्होंने इसका विस्तार किया है। दूसरी यह है कि 50 फीसदी से ज्यादा अनुसूचित आबादी वाले गांवों में इन्होंने "आदर्श ग्राम योजना" लागू की है। यह एक बिल्कुल नई योजना है। "नरेगा" योजना का भी विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया गया है। इसके साथ ही कृषि और कृषकों पर भी विशेष बल दिया है। मैं इनकी चर्चा करना चाहती हूं।

सबसे पहले मैं "भारत निर्माण कार्यक्रम" की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। यह योजना यू.पी.ए. सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में जो दूरियां हैं, उनको खत्म कर के दोनों क्षेत्रों के बीच समानता को बढ़ावा देना है और इसके साथ-ही-साथ गरीब तथा अमीर के बीच की दूरी को पाटना भी है। इसी वजह से इस बजट में पिछले वित्तवर्ष की तुलना में भारत निर्माण के लिए 45 प्रतिशत से अधिक का आबंटन किया गया है। इसी योजना के अंतर्गत 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' में 59 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है, तो वहीं 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' में 27 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। इतना ही नहीं, बल्कि 'इंदिरा आवास योजना' के लिए चालू वित्त वर्ष में 8 हजार 800 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है।

सर, सभी जानते हैं तथा सभी की एक महत्वाकांक्षा होती है कि अपने सिर पर एक छत हो, अपना खुद का एक घर हो। इसी सपने को साकार करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने 'ग्रामीण आवास निधि' के अंतर्गत 2 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जहां पर 50 फीसदी से अधिक आबादी अनुसूचित जाति की है, ऐसे 44 हजार गांवों के विकास के लिए एक नई योजना "प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना" है, जिसे शुरू करने की भी वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है। इसका मैं स्वागत करती हूं। प्रायोगिक तौर पर यह योजना एक हजार गांवों में लागू होगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसका सीधा-सीधा लाभ ऐसे गांवों तथा वहां रहने वाले लोगों को मिलने वाला है।

महोदय, "राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी कार्यक्रम" यू.पी.ए. सरकार की एक क्रांतिकारी योजना है। इसके लिए मैं विशेष रूप से एक बात कहना चाहती हूं कि पूरे देश के सभी अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हैं तथा उनका यह कहना है कि विश्व में अभी जो मंदी व्याप्त है, उस मंदी से अगर भारत की अर्थ व्यवस्था बची हुई है, तो इसका श्रेय राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी कार्यक्रम को जाता है, जिसकी वजह से गांव में रहने वाला एक गरीब आदमी आज अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा है। इसी के लिए उन्होंने इस बजट में 144 प्रतिशत की वृद्धि की है। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत जो व्यक्ति काम करता है, उसे प्रति दिन सौ रुपए की रोज़गारी देने का वादा भी इस योजना में किया गया है ...(**समय की घंटी**)...

सर, मैं यह कहना चाहती हूं कि कृषि और कृषकों पर इसमें विशेष बल दिया गया है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने 411 करोड़ रुपए का इजाफा किया है। इसके अलावा अगर कोई किसान 3 लाख रुपए तक का कर्ज लेना चाहता है, तो उसे यह 7 प्रतिशत ब्याज-दर पर दिया जाएगा तथा अगर वह उस ऋण की अदायगी निर्धारित समय पर कर देता है, तो उसे इसमें 1 परसेंट की छूट मिलती है और इस तरह उसे 6 प्रतिशत ब्याज-दर पर यह ऋण मिलेगा। यह बात किसानों के लिए बड़ी राहत की है। पिछले साल इन्होंने जो 40 लाख किसानों के लिए 71 हजार करोड़ रुपये की "ऋण-माफी योजना" जाहिर की थी, उससे 6 मास की वृद्धि की है तथा दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जोतने वाले किसानों के लिए भी इन्होंने 6 मास की वृद्धि की है। साथ ही मैं एक बात और कहूंगी कि इन्होंने निजी साहूकारों के कर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए भी एक विशेष कार्य-दल गठित करने की बात कही है। महोदय, मैं आखिरी दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी।

मैं सदन का ध्यान छोटे-छोटे सहकारी बैंकों की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। महोदय, सभी जानते हैं कि छोटे सहकारी बैंक गांव में रहने वाले गरीब आदमी के लिए काफी मददगार साबित होते हैं। उनको पगभर होने में काफी मदद करते हैं। पिछले वित्त मंत्री जी ने इन सहकारी बैंकों को आयकर अधिनियम की धारा 80(पी) के तहत जो छूट दी जाती थी, वह छूट वापस ले ली और सहकारी बैंकों पर कर का बोझ डाल दिया है। मैं मानती हूं कि यह अनुचित है क्योंकि इस वजह से सहकारी आंदोलन कमजोर हो जाता है। इन बैंकों का उद्देश्य नशा करना नहीं है, लाभ कमाने का नहीं है और न ही ये commercial बैंकों से होड़ करती हैं। एक तरफ तो आप भारत निर्माण की बात करते हैं, गांव के विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ गांवों को आबाद करने के लिए किसानों व गरीबों की मदद करने वाले इन बैंकों पर हम कर का बोझ डाल रहे हैं, यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि जिस तरह से आपने fringe benefit tax हटाया है, और जिंस जैसी ऐतिहासिक कर प्रणाली को लागू करने से पहले ही आप ने हटा लिया, ऐसा ही कोई ऐतिहासिक निर्णय लेकर फिर से 80(पी) के अंतर्गत सहकारी बैंकों को छूट दी जानी चाहिए। इससे सहकारी बैंकों को लाभ होगा।

महोदय, आखिरी बात कहना चाहती हूं। हम जानते हैं कि भारत गांवों में बसता है, इसलिए कृषि क्षेत्र का विकास होना चाहिए तो क्या हम एक ऐतिहासिक निर्णय नहीं ले सकते कि जिस तरह से हम रेलवे के लिए अलग बजट प्रस्तुत करते हैं, उसी तरह से कृषि और कृषकों के विकास के लिए अलग बजट प्रस्तुत करने की बात हम कहीं से शुरू करें और किसानों के विकास की बात करें? इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं, धन्यवाद।

SHRI KHEKIHO ZHIMOMI (Nagaland): Thank you very much, Sir. Before I go to the main speech, I would like to bring to the notice of this House that while the Budget itself is debatable, though I am a first comer in this august House, I have been silently observing, but with due apologies, this House, the Upper House, Rajya Sabha, should have been more disciplined. But I have observed that, and regret to say that State Assemblies are more disciplined than this august House. This is number one.

Secondly, as I said, Sir, the Budget itself is a debatable one. Even the family budget is debatable. The family budget is budgeted by the father and the mother; their daughters will bring some demand; their sons will bring other demand, the younger ones will bring yet another demand, and the elders will bring their own demand. So, it is very difficult to adjust their budget. But I do, really, with all the sincerity, appreciate the hon. Finance Minister and the Prime Minister for budgeting in favour of the common people, which I really commended and I wish them a successful journey in their mission towards national service.

Sir, I rise to participate in the discussion on the General Budget of 2009-10, presented by Shri Pranab Mukherjee, hon. Finance Minister, on July 6, 2009. Sir, at a glance the hon. Minister has displayed his exceptional skill in financial management by presenting a pro-people, pro-poor and balanced Budget, which could be considered as the magic key to unlock the economic crisis as it exists in the present context.

Sir, it is a matter of satisfaction to note that the current economic growth has been projected at 6.7 per cent, despite the global economic slow down that is sweeping the so-called developed countries the world over. This is, indeed, a commendable achievement. The hon. Finance Minister has laid considerable emphasis on the need to give maximum benefit to the rural areas, in general, and the farmers, in particular. However, I am afraid, no special programme worth the name finds a mention in the current Budget proposals aimed at improving the regional economic imbalances in the North-Eastern Region, particularly, the State of Nagaland to which I belong.

Again, Sir, we are on the stepping-stone of UPA-II's five-year tenure. It is imperative that a five year road map is drawn up to meet the fiscal deficit of Nagaland. The hon. Minister is aware that the tax base in the region is negligible and totally insufficient to boost the economic growth. Whatever funds provided from the Central pool are utilised to meet the monthly outflow on account of salaries

and pension and also for meeting the expenditure on debt liability. These are all of unproductive nature. As a result, hardly any developmental activity is possible and sustenance of growth remains a distant dream. Hence, a blueprint for sustained economic growth of the North-Eastern Region, in general, and the State of Nagaland, in particular, needs to be drawn up. Thereafter, ways and means to translate this plan into a reality must be found. For this purpose, I believe that sincere efforts on the part of the Central Government would make a lot of difference.

Sir, one way of putting Nagaland State into a better growth trajectory is to restore the pattern of financial assistance prevalent prior to 1987 when the funding was 100 per cent and not 90% : 10% as of today. Ours is almost a zero revenue State and, therefore, bringing a matching grant of 10 per cent from the revenue of the State is very difficult.

Sir, I would like to highlight in this regard that the annual Plan size of Rs. 1,500 crores to the State is too meagre and insufficient to meet the economic challenges of the State. This amount is too little when considered against the enormity of the agricultural, economic and other developmental needs of the State. Yet all the developmental activities depend on it. Another way of development is, by way of Centrally-sponsored projects, whose guidelines seem to be an instrument to deny the benefit of such projects.

Therefore, the Nagaland State has no option but to depend on whatever meagre funds available under the State Plan. Hence, I would like to appeal to the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister, to have a little more sympathetic and favourable consideration for the State of Nagaland. Efforts should also be made to restore the financing assistance pattern, which was prevalent prior to 1987.

Mr. Deputy Chairman, Sir, the 13th Finance Commission has recently visited the State of Nagaland. By the end of the current financial year, the Commission would be deciding the quantum of grants to be given to the State of Nagaland for the forthcoming five-year period from 2010-11 to 2014-15. The Chief Minister of Nagaland has taken certain positive initiatives and proactive measures by involving all the political parties in the discussions that took place with members of the Finance Commission. The Commission on its part has also expressed its appreciation over the initiatives taken by the State for communitisation of various public institutions and services in the State.

Sir, I would once again urge the hon. Prime Minister, the hon. Finance Minister, the Planning Commission, the 13th Finance Commission and hon. Members of this august House, including the hon. Deputy Chairman, to support my request for a greater financial assistance to Nagaland for meeting its developmental needs. Additional Central assistance is also absolutely necessary for meeting the expenditure required to implement the recommendations of the Sixth Central Pay Commission for the employees of the Nagaland Government.

Sir, with these words, I once again congratulate the hon. Finance Minister for the excellent job he has done in presenting the Budget which has been acclaimed by all. I support the Budget proposals and the House may pass the same. Thank you.

SHRI BHARATKUMAR RAUT (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am afraid I cannot subscribe to the feelings of support that my predecessor speaker has expressed because the budgetary provisions that have been made by the hon. Finance Minister are far from my level of satisfaction. The people of India have, once again, brought back this Party, a group of parties, to power. Therefore, I was expecting much better and much fruitful budget than what has been presented.

I am deeply pained by the way the Government has indulged in cheap populism in the matter of tax concessions. We are a country, which believes in the rule of law and any commitment, made by the Government, is honoured. My pain is that the Government is prone to making pronouncements in every budget only to discover. A few years later, it does not have the resources or inclination to honour what they have spoken on the floor of the House. This is a very, very pathetic situation. A lot has been said before, therefore, I will not go into everything. I would only like to highlight two issues. One is the issue of' urban poor and the second issue is, many States, particularly Maharashtra and Gujarat, have been deprived of natural resources like oil.

Firstly, I will talk about the second issue. In Maharashtra and Gujarat, there are many natural resources. There are deposits of coal. There are deposits of oil. What we need to do is, we need to put in money to explore the natural resources. In Vidarbha, we have a lot of coalmines. On the coastlines, especially, in Maharashtra and Gujarat, we have oil resources. When we keep saying that we need to import oil from outside, and, therefore, our prices keep going up, it is but natural that the Government should give top priority to exploration of these natural resources within our country. And, if we do that, in the next five years, I am sure that we can be very close to self-reliance as far as these things are concerned. The next point is the issue of urban poor. We have been talking about rural poor. In my State, every day, there are at least four cases of suicides of farmers. These people end their lives because of heavy debt that they face. The Government is, at least, saying that it is doing something. My question to you is: What do we do for the urban poor? I come from Mumbai, the biggest metropolis in our country. In my city, you will not believe, every day, there are five cases of suicides. In most cases, they end their lives because of poverty. Nobody is bothered about this. Who are these people? These people are poor workers, jobless youth, frustrated youth and women. The plight of the women is that they do not get money from their husbands to cook for the next morning, and she has nothing. Sir, my city has elected all six MPs from Congress (I) and the NCP. What are we doing to ensure that the urban poor, poor youth, who has come to Mumbai from somewhere else, from rural areas of the country, get their bread and butter every evening and every morning? We keep on saying that there is a global meltdown and, therefore, there is no job, But, in that situation, it is the responsibility of the Government to ensure that all those who want to work,

and those who need work, are given some work. If they are not given work, then, it means that you are putting him into debts. And, we have no authority to do this. People are looking at the Government with a great expectation that if not shelter, if not water, if not sanitation, if not education, it would, at least, ensure a meal for their families. On the other hand, on the outskirts of their slums, when these slum dwellers see huge towers coming up, and their children are wasting money and going to five-star hotels, but these poor men do not have even a piece of bread for the evening, what do you think? I think, if we are talking of socialism, if we are talking of equality, then, it is our duty to bring them on par, and that is the least thing that the Government can do.

One point more I would raise, and, then, I will conclude. This pertains to green houses. Many people may not be knowing that Maharashtra develops maximum number of green houses. Green house is a new technology that allows farmers to grow vegetables, to do horticulture, in any given environment, whether you have a good soil or a bad soil, good rains or bad rains; even then, you can cultivate horticulture and floriculture. And, we have a good market for this business even outside India. These green house makers have been put to unnecessary taxes, like, service tax, excise duty, and so on. My suggestion to you is, please look at this business as a potential tool to get extra foreign exchange and work to rural poor, half-skilled people and also, the use of barren land. We have huge barren land across the country. If these types of Green Houses are developed, the whole scenario can change. I can tell you that we have the demand; we have the demand from the Gulf; we have the demand from America. The flowers which are cultivated in these Green Houses, are exported all over the world, from Australia to America. So, my suggestion to you is that you should look at it from a longer-term perspective and you should stop levying taxes on them and treat them as agriculture. For agriculture, we have this tax umbrella; the same should be applicable to the Green House cultivation also. I think that will help improve rural employment.

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I request you to kindly allow me ten minutes time to speak. As it is, we on these large Benches have very rare opportunity to speak.

First, let me support and congratulate our hon. Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee, for having presented this Budget. Sir, when I think about his capabilities, ग़ालिब का एक शेर मुझे याद आया है-

"मुश्किलें मुझ पर पड़ीं इतनी कि आसान हो गईं।"

मैं समझता हूं कि ग़ालिब ने यह बिल्कुल appropriately प्रणब दा के लिए ही लिखा है। इनके सामने जो भी चैलेंज आता है, उसे वे इतनी सरलता से, इतनी सहज-बूझ से और इतने अच्छे तरीके से कर लेते हैं कि सब लोग देख-देखकर परेशान होते हैं कि इतने बड़े-बड़े चैलेंज वे किस तरह से ले पाते हैं? हमारे अपोज़िशन के कई ...(**व्यवधान**)...

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला : सर, शेर तो उन्होंने सुनाया नहीं!

श्री उपसभापति : सुनाया है उन्होंने। ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : पूरा शेर पढ़िए।

श्री गिरीश कुमार सांगी : पूरा ही है, आप उसे समझ लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

सर, हमारे अपोज़िशन के कई दिग्गज नेताओं ने अपने-अपने भाषण में कई बातें कहीं और टिप्पणियां भी कीं। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने जितनी भी टिप्पणियां की हैं, यह आंकड़ा उसको पूरा नकारता है। सर, 2000-01 में जो बजट इन्होंने पेश किया था, वह 3,38,000 करोड़ का था और इनका 2003-04 का बजट 4,38,000 करोड़ का था। तो इनके कार्यकाल में बजट की जो वृद्धि हुई, वह करीब 1 लाख करोड़ की। 2004-05 में जो यू.पी.ए. सरकार आई, उन्होंने जो बजट पेश किया, वह 4,77,000 करोड़ का था और अब जो बजट पेश किया गया है, वह 10,20,000 करोड़ का है। तो इसमें जो वृद्धि हुई है, वह डबल से ज्यादा हुई है। उनके कार्यकाल के दौरान करीब 1 लाख करोड़ की वृद्धि हुई और यू.पी.ए. सरकार की रिजीम में करीब 5 लाख करोड़ से ज्यादा की वृद्धि हुई है। यही वह आंकड़ा उनके हर क्लेम को नकारता है।

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश) : जितना हमारा बजट था, उतना इनका घाटा है। यह क्यों नहीं बताते?

श्री गिरीश कुमार सांगी : ठीक है। आप ऐसे ही बोलते रहिए, हम ऐसे ही सरकार चलाते रहेंगे। सर, सबसे पहले मेरी जो स्टेट है, आंध्र प्रदेश, वहां के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की दृष्टि में कुछ बातें लाना चाहूंगा। हमारे जो नेता हैं, चीफ मिनिस्टर, श्री राजशेखर रेड्डी जी, उन्होंने बड़े gigantic projects इरीगेशन में दिए हैं। मैं चाहूंगा कि बजट में इरीगेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रावधान रखा जाए। खास कर आंध्र प्रदेश में जो मेजर प्रोजेक्ट्स इरीगेशन के लिए गए हैं, जिनके तहत करीब पचास लाख एकड़ और नई जमीन सिंचाई में लाने का पूरा हमारा प्लान है। काफी ऐडवांस स्टेज में ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट्स को नैशनल प्रोजेक्ट्स के तहत लेकर उसका पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट ही उठाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और बहुत अच्छा प्रोग्राम अभी recently हमारे मुख्य मंत्री जी ने लिया है, वह drinking water का है। यह बड़ा unique प्रोग्राम है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूंगा। आज आप और हम सब लोग देखते हैं कि सब लोग पीने के लिए pure drinking water चाहते हैं, स्वच्द मिनरल वाटर चाहते हैं जो मार्किट में बहुत महंगा मिलता है। हमारी सरकार ने यह योजना बनाई है कि हर घर में, हर गांव में एक मिनिरल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा और दो रुपए में बीस लीटर pure drinking water, mineral water, purified water उपलब्ध कराया जाएगा। यह बहुत बड़ी योजना है। इसके लिए भी मैं चाहूंगा कि हमारी केन्द्र सरकार मदद करे, उसकी सराहना करे, उसको encourage करे। सर, हम सब यहां पर आते हैं, बातचीत करते हैं और हम सबका एक कॉमन कंसर्न है कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े। हमारा देश कैसे उन्नति करे, हमारा देश कैसे तरक्की करे, हमारे देश से गरीबी कैसे हटे। आज हम देखते हैं कि दस लाख से अधिक का बजट पेश किया गया। लेकिन जब हम गांव में जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि गरीबी जहां की तहां रहती है, भुखमरी जहां की तहां रहती है, बेरोज़गारी जहां की तहां रहती है। यह जो बजट और लेजीस्लेशन पास होता है और जो डिलीवरी सिस्टम है, जो वास्तविकता ग्राउंड पर होती है, उसमें जो मिसमैच है, उसकी वजह क्या है। जब तक हम सब मिलकर इसकी खोज नहीं करेंगे,

इसके बारे में नहीं जानेंगे कि कहां पर loophole है, कहां पर ग्रे एरिया है, कहां पर लीकेज है, डिलीवरी सिस्टम कहां पर खराब है, जब तक हम उस डिलीवरी सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, तब तक चाहे कितने ही बजट हम पेश कर लें, चाहे कितनी बात कर लें, चाहे कितना टैक्स हमारे लोगों पर ...(समय **की घंटी**)... सर, मैं दस मिनट चाहूंगा। जो मेरा अनुभव है, उसके तहत मैंने जो देखा और समझा है, वह यह है कि the office should seek the man, not the man the office. अकसर यह देखा जाता है कि जो अफसर होता है, वह ऑफिस सीक करता है, वह अपनी इच्छानुसार, अपने सलेक्शन के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार अपना ऑफिस सलेक्ट करता है, उसकी पैरवी करता है और पैरवी करके उस ऑफिस में पहुंच जाता है। सर, जो ऑफिस होता है, उसके लिए जो एक सक्षम आदमी चाहिए, उसकी खोज होनी चाहिए, इस हिसाब से उस ऑफिस में उस तरह का आदमी हम बिठाएंगे, उस तरह का अगर कर्मचारी बिठांएगे जो सच्ची निष्ठा से काम करेगा तो मैं समझता हूं कि हमारा डिलवरी सिस्टम काफी इम्प्रूव हो सकता है। और एक बात पंचायत राज के संबंध में कहना चाहता हूं क्योंकि हमारा देश गांवों में बसा हुआ है। पंचायत राज में जो devolution of power है जो राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा सपना था, वह devolution of power का सपना अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि डिवोल्यूशन ऑफ पॉवर्स ज्यादा से ज्यादा हो और गांवों में वे अपना जो निर्णय लेना चाहेंगे, अपना निर्णय खुद लें। एक बात और है सर ...(**समय की घंटी**)... दो मिनट और, सर।

श्री उपसभापति : दो मिनट करते-करते आपके आठ-नौ मिनट हो गए। आपकी पार्टी का अभी 20 मिनट बाकी है तथा चार लोग बोलने वाले हैं।

श्री गिरीश कुमार सांगी : जब तक हम वेल्यू एडीशन नहीं करेंगे, हमारे देश के जो यूथ हैं, यंग हैं उनको अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनको प्रोत्साहन नहीं देंगे, तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी वेल्यू एडीशन के लिए नए-नए इंसेंटिव बढ़ाएं, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए नए-नए इंसेंटिव बढ़ाएं तथा सपोर्ट में जो हमारा शॉर्ट फॉल हो रहा है, एक्सपोर्ट के लिए क्या प्रोत्साहन देंगे, उसके लिए क्या नई स्कीमें निकालेंगे, उसके बारे में बताएं? इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं एक लास्ट पोइंट बोलूंगा। सर, वह है सोशल सिक्योरिटी टू ट्रेड एंड बिजनेस। आज हमारे यहां लाखों-करोड़ों दुकानदार हैं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, उनके लिए न कोई फंड है, न ग्रेच्युएटी है, न प्रोविडेंट फंड है। जो मेहनत करता है, अपनी कमाई करता है तथा सरकार को टैक्स पे करता है और वह जो टैक्स जमा करता है उसका कोई भुगतान उसको नहीं मिलता है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसी नीति लाए, जिसमें जो भी टैक्स पेयर है उसके लिए कोई फंड क्रिएट किया जाए तथा उसके सोशल सिक्योरिटी के लिए कोई प्रावधान किया जाए। धन्यवाद।

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) : उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। यहां मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं, क्योंकि यह बजट एक डवलपमेंट ऑरिएंटेड है, चाहें मि. नायडु की नज़रों में नहीं था, लेकिन यह बहुत ही अच्छा बजट पेश किया गया है जिसमें गरीबी उन्मूलन के लिए तथा जो और सबसे बड़ी बात है, जो इतने सालों से एक समस्या, एक मांग चली आ रही थी, हमारे जो फौजी भाई हैं, उनकी एक मांग थी कि हमें एक रेंक और एक पेंशन मिलनी चाहिए, इस बजट में इसका प्रावधान करके, मैं कहूंगी कि वित्त मंत्री जी ने उन लोगों का, उन फौजियों का ध्यान रखा है जो हमारी सीमाओं पर लड़ते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं, इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। इसमें उन्होंने

यह बात भी क्लिअर की है कि इसमें सिर्फ रैंक ही नहीं इसमें ऑफिसर्स भी हैं जिससे हमारे फौजियों को एक बहुत बड़ा उत्साह मिला है, क्योंकि लोग फौज में जाने से घबरा रहे थे, नहीं जाते थे तथा इससे पीछे हट रहे थे, इससे उनको एक प्रेरणा मिलेगी। हमारे यहां के लोग खास करके हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान आदि के लोग फौज में जाते हैं, यह उनके लिए बहुत बड़ी देन है, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूंगी। यह बजट सभी वर्गों के लिए है चाहे महिलाएं हों, चाहे हमारे सीनियर सिटीजंस हैं, चाहे आप शिक्षा में ले लीजिए, अल्पसंख्यकों की बात ले लीजिए और सबसे बढ़िया किसानों के लिए है। हम कहते तो जरूर हैं हमारी 60 परसेंट से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है, इसकी हम बहुत चर्चा भी करते हैं, लेकिन पहली बार यू.पी.ए. सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, डा. मनमोहन सिंह जी ने उस किसान के लिए सोचा है कि जो दिन-रात मेहनत करता है, जो धूप में तपता है, उसके बारे में आज तक कोई नहीं सोचता था, उन्होंने यह सोचकर चाहे उसका कर्जा माफ किया या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो और जिस तरह से स्वामीनाथन जी ने कहा कि इरिगेशन की बात रखी गई है, जो कि बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूं।

जहां तक नरेगा की बात है, मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि नरेगा का बजट बहुत बढ़ा दिया है। उपसभापति महोदय, जब तक इसकी समीक्षा नहीं होगी, जब तक इसके बारे में सही तरह से इसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी तथा यह नहीं देखा जाएगा कि यह पैसा गांवों में लोगों को मिल भी रहा है, उनके पास पहुंच भी रहा है या कुछ लोगों के हाथों में ही रह रहा है, क्योंकि मैं माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूं कि पहले नरेगा का पैसा जिलों में डायरेक्ट जाता था, लेकिन पिछली बार कुछ ऐसा किया गया कि यह राज्यों को दिया जा रहा है। यह राज्यों को नहीं दिया जाना चाहिए, सीधे जिलों में जाना चाहिए, जिससे वहां की प्लानिंग बन सके। अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश को उनके एकाउंट खोल करके स्टेट फंड में दिया गया है, जो ठीक नहीं है। इसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। केवल पैसा देने, sanction करने से बात नहीं बनती है, उस पैसे को किस तरह से खर्च किया गया है, उस पैसे का किस तरह से सदुपयोग किया गया है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगी कि यूएनडीपी के लोगों को समीक्षा के लिए लगाया गया है, जो ठीक नहीं है। हमारे पास लायक लोग हैं, हमारे पास योग्य लोग हैं, हमारे पास ऐसी एजेंसीज़ हैं, जो इसकी समीक्षा कर सकती हैं। Implementation बहुत जरूरी है। हमने सब कुछ दे दिया है, हर वर्ग को दे दिया है, लेकिन जब तक implementation नहीं ठीक होगा, फिर वही बात आएगी। राजीव जी ने कहा था कि 15 पैसे पहुंचते हैं और आज हम कह रहे हैं कि 8 पैसे पहुंचते हैं। जब तक इसका implementation ठीक नहीं होगा, जितने हमारे प्रोग्राम्स हैं, वे वहीं के वहीं रह जाएंगे।

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि हमने सब कुछ कर दिया। हमने food security दी, हम right to education दे रहे हैं, लेकिन जब तक हम population को control में नहीं लाएंगे, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। बड़ा अच्छा हुआ, कल-परसों ही stabilize नाम दिया गया है कि population stabilize होनी चाहिए। इसी नाम से जब तक हम population को control नहीं करेंगे, हमारी जितनी स्कीमें हैं, वे वहीं की वहीं रह जाएंगी और यही होगा कि तरक्की नहीं हुई।

मैं एक और बात कहना चाहती हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी । आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं, मैं इसका मौका नहीं दूंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि हम लोग कहते थे कि 2008 में inflation 12 परसेंट से ऊपर चला

गया था, कीमतें बढ़ गई थीं, आज हम inflation .0 कुछ कह रहे हैं, लेकिन कीमतों में फर्क नहीं पड़ा, विशेष कर जो खाने-पीने की चीजें हैं, चाहे सब्जियां हैं या दालें हैं। मैं वित्त मंत्री जी से यह कहूंगी कि यह जो रिटेल है, चाहे वह इनकी मिनिस्ट्री के अन्दर नहीं है, लेकिन फिर भी वे इस पर गौर करें। गरीब को तब तक नहीं लगेगा कि सरकार कुछ कर रही है, जब तक कीमतें कम नहीं होगी। इसलिए इस पर भी कुछ ध्यान दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

————————

RE: MALFUNCTIONING IN LIFT OF PARLIAMENT

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Sir, I have a point to make. Sir, I was in my room and while coming back by lift I was very much worried. I request the Chair to call the Minister of Parliamentary Affairs to ask him to make a statement to the entire House on what has happened. ...*(Interruptions)*... All the TV channels are showing it. ...*(Interruptions)*... It is a very serious matter. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I was about to make an announcement and you got up. Eight persons were trapped in the lift. They are all rescued and they are safe. It took one or one-and-a-half hour. ...*(Interruptions)*...

SOME HON. MEMBERS: Two hours, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: According to our information, it is about one to one-and-a-half hour. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): I raised that issue, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I also visited there. So, I just wanted to inform you about it, ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am not criticising, Sir, what has happened has happened. If you just go from here to 1st Floor or 3rd Floor by a lift, these lifts are before BC. ...*(Interruptions)*... it is not to criticise anybody. ...*(Interruptions)*... It is not a political issue. ...*(Interruptions)*... Sir, for example, if any person who has got phobia and he is there, he would have gone. One of the persons, I don't know whether the hon. Chair got the information, was to be put on oxygen. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Oxygen was regularly supplied. ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: My only request is, because we have now an important thing, there has to be total replacement of these lifts and then there should be open lifts with oxygen coming inside. ...*(Interruptions)*... It is a serious matter. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not only lifts, there are certain things, which are being looked into, and discussions are going on. ...*(Interruptions)*..

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: My suggestion to the Chair is that rather than Chair taking the responsibility, it is the duty of the Parliamentary Affairs Minister or the CPWD or the Urban Affairs Ministry or whoever is looking after it, they should seriously look into this matter. ...*(Interruptions)*...